प्रेरणा

एक अच्छा जीवन वही है जो प्रेम से प्रेरित है और ज्ञान से दिशा लेता है। -बर्ट्रेंड रसेल

संपादकीय

हवाई हादसों में कितने लोगों को खोएंगे हम?

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन से देश स्तब्ध है। वे एक पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए निजी विमान से जा रहे थे। वे शरद पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे। इस घटना के बाद हाल के वर्षों में कई प्रमुख शख्सियतों के वायु-दुर्घटना में निधन से भारत में तेजी से उभरते एविएशन सेक्टर पर सवाल उठने लगे हैं। किसी भी उभरती इकॉनोमी में उड्डयन क्षेत्र में निजी उपक्रम भी बढ़ते हैं। उद्यमी अपने निजी जेट और चॉपर रखने लगे हैं। गैर-सरकारी एयरलाइंस के अलावा दर्जनों कंपनियां चार्टर्ड प्लेन्स और हेलीकाप्टर्स उपलब्ध कराती हैं, जिनका राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इन यानों के रखरखाव, पायलट्स के कौशल और लैंडिंग-टेक ऑफ प्रोटोकॉल के लिए सरकार को सख्त मानिटरिंग सिस्टम बनाना होगा। बीते साल ही एक विमान दुर्घटना में एक को छोड़कर सभी यात्री मारे गए थे। उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। कुछ वर्ष पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर क्रैश में निधन भी कई सवाल उठाता है। राजशेखर रेड्डी, माधव राव सिंधिया, संजय गांधी, जीएम बालयोगी, दोरजी कांडू, मोहन कुमारमंगलम आदि एयर क्रैश के शिकार रहे हैं। अब पवार के निधन से नसीहत लेकर एविएशन सेक्टर को दुर्घटना-शून्य बनाने की दिशा में काम करना होगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए ध्यान से जोड़ें

आज माता-पिता अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर बड़े परेशान हैं। पूरी दुनिया में भारत के युवा सबसे ज्यादा करियर ओरिएंटेड माने जाते हैं। तो भविष्य के प्रति यह गंभीरता तो युवा पीढ़ी में है, लेकिन जब यह बचपन युवा होगा, तब क्या होगा? ऐसा कहते हैं कि इच्छा की यात्रा पर निकले हुए व्यक्ति अपनी नींद खो देते हैं। इच्छा रखना मनुष्य का स्वभाव है। फिर इच्छा लालसा में बदलती है। लालसा वासना में तब्दील होती है और वासना फिर परेशान करती है। पहले युवा लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन अब बच्चे भी ऐसा करने लग गए हैं। एक्शन में उतनी ऊर्जा नहीं लगती, जितनी रिएक्शन में खर्च हो जाती है। मनुष्य के मन में एक चुम्बक होता है। हम जो सोचते हैं, उस परिस्थिति को वो खींचता है। आज बचपन जो सोच रहा है, उसकी जरूरत उस उम्र में नहीं है। और उम्र से पहले ही कुछ बातें यदि मन में उतर जाएं तो उसकी प्रतिक्रिया खतरनाक ही होती है। बच्चों की मेंटल हेल्थ को यदि ठीक रखना है तो समय रहते उनको मेडिटेशन से जरूर जोड़ा जाए।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

नए यूजीसी नियम सरकार की मुसीबत

नए यूजीसी नियमों पर सरकार ने स्वयं को भारी असमंजस में डाल लिया है। अब इन्हें ऐसे ही रखते हैं तो इनका कोर वोट बैंक टूटेगा और संशोधन करने पर ये मनुवादी और सवर्ण समर्थक कहे जाएंगे। कुल मिलाकर ये उस कीचड़ में लड़ने चले हैं, जहां विपक्ष बहुत वर्षों से सरकार को लड़ने का न्योता दे रहा था। नतीजा कुछ भी हो, इसी बहाने देश सत्तावाद के चंगुल से निकलता दिख सकता है।
-पी.पी., भोपाल, मध्य प्रदेश

पहाड़ों पर विकास सावधानी से हो

हम पहाड़ों पर विकास और निर्माण ऐसे कर रहे हैं कि पहाड़ों की सांस ही फूलने लगी है। कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो कभी पहाड़ गिर रहे हैं। पहाड़ों पर विकास ऐसे किया जाए कि प्रकृति की लक्ष्मण रेखा पार न हो। निर्माण करने के लिए पहाड़ों में ब्लास्टिंग इस तरह न हो कि आसपास की बुनियाद ही कमजोर पड़ जाए। पहाड़ों पर अवैध निर्माण रोकना भी जरूरी हैं।
-राजेश कुमार चौहान, जालंधर, पंजाब

कार्रवाई के नाम पर हत्या गलत

हाल ही अमेरिका के मिनियापोलिस में एक इमिग्रेशन अधिकारी ने कार में बैठी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या ट्रम्प प्रशासन इमिग्रैंट्स को हटाने के नाम पर ऐसे लोगों की हत्या करेगा? कोई कानून तोड़े तो कानूनी प्रावधानों के तहत सजा मिलनी चाहिए, न कि गोली मार देनी चाहिए। ऐसे ही शासन चलाना है तो किस मुंह से आप ईरान, सऊदी अरब और उत्तर कोरिया की आलोचना करते हो? -जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

देश में विकास का विकेंद्रीकरण हो

हम निरंतर महानगरों को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए महानगरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और वहां की व्यवस्था चरमरा गई है। विकास का विकेंद्रीकरण हो तो निश्चित ही महानगरों में बढ़ती हुई भीड़ पर विराम लगेगा और पूरे देश के सभी क्षेत्रों को विकास के रास्ते पर समान रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। -केएन शर्मा, बड़वाह, मध्य प्रदेश

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

काजुंगुला क्वाड्रीपॉइंट पर एक साथ मिलते हैं चार देश

अफ्रीका में जाम्बेजी नदी के पास काजुंगुला क्वाड्रीपॉइंट क्षेत्र दुनिया का अपनी तरह का इकलौता और अनोखा भौगोलिक क्षेत्र है। इस स्थान पर चार देशों की सीमाएं एक ही क्षेत्र में आकर मिलती हैं। इन देशों में जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया शामिल हैं। दरअसल, इस इलाके में अफ्रीका की जाम्बेजी और चोबे नदियां मिलती हैं। इसी संगम पर चारों देशों की सीमाएं भी लगती हैं। पर्यटन के नजरिए से दुनिया का प्रसिद्ध जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स इस जगह से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर ही है।

923 मीटर का एक इस्पात का पुल जाम्बेजी नदी पर इस क्वाड्रीपॉइंट के ठीक ऊपर से बनाया गया है, जो बोत्सवाना और जाम्बिया देशों को आपस में मिलाता है।

सुर्खियों से आगे • दरअसल, आसन और सिंहासन का कर्तव्य ही लोगों को भयग्रस्त करना हो चला है...

यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला क्यों?

देश-समाज

नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

यूजीसी के नए नियमों पर इतना हल्ला क्यों है? दरअसल, नए नियमों में जाति-आधारित टिप्पणियों में शामिल वर्ग का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इस दायरे में केवल अनुसूचित जातियां और जनजातियां ही शामिल थीं। कार्रवाई में सख्ती भी कुछ कम थी।

सही भी है- मान सकते हैं कि दलित वर्ग के साथ वर्षों अन्याय हुआ था और इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए ऐसा करना उचित रहा होगा। लेकिन अब इस दायरे में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग भी जुड़ गया है। केवल सामान्य या अनारक्षित वर्ग ही इस दायरे से बाहर रह गया है।

विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के कारण सामान्य वर्ग अपने आप ही आरोपों से घिर जाएगा। कहना यह चाहिए कि वह एक तरह से डिफॉल्ट अपराधी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य यह है कि सामान्य वर्ग को तो कोई राहत नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि आरक्षित वर्ग अगर झूठी शिकायत कर दे तो भी उसके लिए किसी दण्ड का प्रावधान तक नहीं किया गया है। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है।

कहा यह भी जा रहा है कि सरकारें पिछड़ा वर्ग की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करती रहती हैं। हो सकता है कि भारी विरोध के बाद ये नए नियम वापस ले लिए जाएं या उनमें सुझाए जाने वाले उचित संशोधन कर दिए जाएं। लेकिन नियम वापसी के बाद भी सरकार के प्रति उन वर्गों की सहानुभूति तो बनी ही रहेगी! विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार अपना यही उद्देश्य पूरा करना चाहती है।

वैसे, समग्र के नकार और केवल टुकड़ों को वास्तविक बताने की राजनीति आजादी के पहले भी थी और आज भी है। अन्याय के अनवरत शिकार छोटे-छोटे समूहों को नेता पहले उकसाते रहे, फिर कोरे आश्वासनों की अफीम खिलाते रहे और अंतत: इन्हें अतिवाद की हद तक जाने देते रहे। बाद में चूंकि उन कुछ टुकड़ों की सभी मांगें मानी नहीं गईं, इसलिए वे राजकाज के पूरे तंत्र और आखिरकार पूरे देश को ही अन्यायपूर्ण बताने लगे थे।

यही वजह थी कि टुकड़ों की राजनीति के उल्टे पड़ जाने पर वही सत्ताधीश इन टुकड़ों को इन बिखरी हुई जातियों को ठोक-पीट कर इकट्ठा करते हुए पाए गए और कहते रहे कि हम समग्रता को पहचान देने या छोटे-छोटे वर्गों को एकजाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि समग्र सामाजिक विकास की खातिर ऐसा करना अवश्यम्भावी हो गया है। अनिवार्य हो गया है।

आजादी के पहले हमारे देश में अंग्रेजों ने भी यही किया था। उन्होंने पहले समाज के छोटे वर्गों को अलग पहचान देकर उन्हें तोड़ा। उनकी सहानुभूति अर्जित की और फिर उन्हीं का समर्थन पाने की मजबूरी के चलते उन्हें जोड़ने का उपक्रम भी किया। वर्षों वे अपनी इन्हीं तिकड़मों के भरोसे राज करने में सफल भी हुए।

नए नियमों के कारण सामान्य वर्ग आरोपों से घिर जाएगा?

विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के कारण सामान्य वर्ग आरोपों से घिर जाएगा। वह डिफॉल्ट अपराधी घोषित हो जाएगा। कहा जा रहा है कि आरक्षित वर्ग झूठी शिकायत कर दे तो भी उसके लिए दण्ड का प्रावधान नहीं है।

दरअसल, सियासत की कोई आत्मा नहीं होती। जिस दिन कोई भी सियासतदान लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाएगा, उस दिन सियासत की आत्मा जाग उठेगी। यह भीतर के आत्मबल और बाहर की सत्ता का अंतर है। यह भयमुक्त होने और भयग्रस्त होने का अंतर है। चूंकि राजनीति की आत्मा नहीं होती, इसलिए उसमें भीतरी शक्ति भी नहीं होती। ...और इसीलिए वक्त पाकर हर सत्ता के हाथों अपनी चेतना का विज्ञान खो जाता है। आश्वासनों के भरोसे सिंहासन पाने के खयाल उसी के पैरों की जंजीर बन जाते हैं।

हमारे प्राचीन इतिहास में एक नाम आता है- मीरदाद। कुछ लोग उनके पास यह सवाल लेकर पहुंचे कि हम इतने उदास क्यों हैं? मीरदाद ने कहा- इसका जवाब तो वह हवा ही दे सकती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। वह हवा जो हमारे ही खयालों के जहर से भरी हुई है।

यही जहर हमारे घर-आंगन में, हमारी गलियों में और हमारे दरो-दीवार पर अंकित हो गया है। यही वजह है कि हम अब चेतना या महाचेतना के वारिस नहीं हैं। ...आज हम चीखों के वारिस हैं, जख्मों के वारिस हैं और सड़कों पर बहते हुए लहू के वारिस हैं।

दरअसल, आसन और सिंहासन, सत्ता और सरकार का कर्तव्य ही लोगों को भयग्रस्त करना हो चला है। वे लोगों को सिर्फ शारीरिक गुलामी ही नहीं देते, जेहनी और मानसिक गुलामी भी देते हैं। इसीलिए... सिर्फ इसीलिए हम रोज अपनी कोख से खुशियों का सूरज जन्मते हैं और रोज हमारा सूरज यतीम हो जाता है।

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

नजरिया • सच्चे जर्नलिज्म के पुरोधा थे मार्क टली

सनसनी पर विश्वसनीयता को महत्व देने वाले पत्रकार

स्मरण

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन के हमारे जीवन पर हावी होने से बहुत पहले रेडियो की दुनिया थी। 1970 के दशक के भारत में पले-बढ़े हम जैसे लोगों के लिए रेडियो ही व्यापक संसार की खिड़की हुआ करता था। और उसी में बीबीसी रेडियो सेवा भी थी। हर सुबह मेरे दिवंगत दादाजी- जो एक पुलिस अधिकारी थे- एक घंटे के योग और ध्यान के बाद उसका दैनिक बुलेटिन सुनते थे। वे मुझसे कहा करते थे, अगर खबर चाहिए तो बीबीसी सुनो। समाचारों की दुनिया में डूबा एक जिज्ञासु बच्चा होने के नाते बीबीसी तब मेरा शुरुआती साथी बन गया था। और इसी के साथ मिस्टर बीबीसी कहलाने वाले- द वन एंड ओनली मार्क टली (बाद में सर मार्क टली) भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए।

मुझे याद है, 1984 में मैं एक हजामत की दुकान में था, जब बीबीसी पर खबर आई कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। ऑल इंडिया रेडियो शोकपूर्ण संगीत बजा रहा था, लेकिन इस भयावह खबर की पुष्टि मार्क टली की स्पष्ट और प्रभावी आवाज ने की। वर्षों बाद, 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब मैं मुंबई में एक रिपोर्टर था। उस समय भी सबसे सटीक और मौके से की गई रिपोर्टिंग के लिए हम बीबीसी और टली की ओर ही मुड़े। तब कारसेवकों की भीड़ ने टली का पीछा किया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन इस भयावह अनुभव के बावजूद उन्होंने घटनाओं को यथासंभव स्पष्टता के साथ सामने रखा।

वे भरोसे और विश्वसनीयता की आवाज थे। उनके भीतर ये गुण समय के साथ और एक विशाल देश के कोने-कोने की वर्षों की कठिन यात्राओं के जरिए गढ़े गए थे। बीबीसी के भारत ब्यूरो प्रमुख के रूप में वे कई दशकों तक घटित हुए ऐतिहासिक और विनाशकारी घटनाक्रमों के साक्षी रहे थे। मुझे याद है, 1990 के दशक के मध्य में मैं अपने कैमरापर्सन के साथ यूपी की यात्रा कर रहा था। हम लखनऊ के पास एक गांव पहुंचे, जहां एक आम के बाग के मालिक ने हमें चाय के लिए अपने घर बुलाया। उन्होंने हमें एक एल्बम दिखाया, जिसमें कुछ साल पहले टली के साथ खींची उनकी एक तस्वीर थी। वे उत्साह से बोले, यह मेरा फैन मोमेंट था। टली साहब उस दौर के सेलिब्रिटी थे, जब पहचान बनाने के लिए आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं होता था। शांत, संयत और अधिकारपूर्ण लहजे में बोलना ही पर्याप्त हुआ करता था।

मेरा भी उस महान पत्रकार के साथ अपना 'फैन मोमेंट' रहा है। 1994 में मैं दिल्ली आया था और राजधानी के सत्ता-गलियारों को समझने की कोशिश कर रहा था। राजनेताओं से ज्यादा मुझे मार्क टली से मिलने की उत्सुकता थी। जब मैंने उनसे समय लेने के लिए फोन किया, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा कि उन्हें मुझसे मिलकर खुशी होगी। उन्हें साथी पत्रकारों की संगत पसंद थी और वे अपनी कहानियां तथा व्यापक अनुभव उन सभी के साथ साझा करते थे, जो उन्हें सुनना चाहते थे। वे उन 'फिरंगी' पत्रकारों में से नहीं थे, जो भारतीय पत्रकारों से सिर्फ सूचनाओं के लिए सम्पर्क करते हों; बल्कि वे खुद को व्यापक भारतीय पत्रकारिता समुदाय का अभिन्न हिस्सा मानते थे और आजीवन मित्रताएं निभाते थे।

शायद यही कारण था कि उन्हें इंग्लैंड की तुलना में भारत में कहीं अधिक अपनापन महसूस होता था। भारत के प्रति उनका स्नेह और लगाव वास्तविक था, वह कोई ओरिएंटलिस्ट-फैंटसी नहीं थी। टली के लिए भारत दृश्य-श्रव्य अनुभवों की वह जीवंत दुनिया था, जिसने उन्हें पूरी तरह से मोहित कर लिया था। उन्होंने कुछेक टीवी डॉक्यूमेंट्री जरूर कीं- जिनमें भारतीय रेल यात्राओं पर बनी एक यादगार फिल्म भी शामिल थी- लेकिन रेडियो ही उनका पहला प्यार रहा था। शायद इस माध्यम की सादगी उन्हें आकर्षित करती थी।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई हमारी आखिरी बातचीत में उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि आज के भारत में पत्रकार होना आसान नहीं है! मैंने भी सिर हिला दिया। कई बार चेहरे का भाव हजार शब्दों से ज्यादा कह देता है।

एक बार मैंने उन्हें एक टीवी बहस के लिए आमंत्रित किया। काफी मनाने के बाद वे आए, लेकिन वो अनुभव उन्हें खास पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, यह सब कुछ ज्यादा ही शोरगुल भरा नहीं है? इन अर्थों में वे एक ऐसे शालीन-युग के पत्रकार थे, जिसमें सनसनी और कोलाहल पर विश्वसनीयता और सच्चाई को तरजीह दी जाती थी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई हमारी आखिरी बातचीत मुझे आज भी याद है, जहां वे अकसर अपने करीबी दोस्तों के साथ नजर आया करते थे। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा था, मुझे लगता है कि आज के भारत में पत्रकार होना आसान नहीं है! मैंने भी उनकी ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। कई बार चेहरे का भाव हजार शब्दों से ज्यादा कह देता है। और जैसा कि उनकी पुस्तक का एक शीर्षक ही कहता है- भारत में कभी पूर्ण विराम नहीं होते।

अलविदा सर मार्क, शुभ यात्रा!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

स्पीक-अप • कट्टरपंथ की ओर बढ़ता पड़ोसी देश

बांग्लादेश में होने जा रहे चुनाव हमारे लिए भी अहम

आस-पड़ोस

मिन्हाज मर्चेंट
लेखक, प्रकाशक और सम्पादक
mmleditorial@gmail.com

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में तीन ताकतें मैदान में हैं। पहली, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जिसे पाकिस्तान से जुड़े इस्लामिक समूहों का समर्थन है। दूसरी, बीएनपी, जिसकी कमान पिछले ही माह दिवंगत हुई खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। तीसरी, वो विदेशी ताकतें, जो बांग्लादेश की अस्थिरता में अपने हित साध रही हैं। इनमें चीन और पाकिस्तान भारत-विरोधी तत्वों का समर्थन करते हैं। फिर अमेरिका है, जो हसीना सरकार की जगह अपने अनुकूल शासन चाहता है। शेख हसीना सरकार ने वर्षों तक अमेरिका को बंगाल की खाड़ी स्थित सेंट मार्टिन द्वीप तक पहुंच बनाने से रोके रखा था। म्यांमार से केवल पांच किलोमीटर दूर इस द्वीप का गहरा भू-रणनीतिक महत्व है।

गए साल शेख हसीना के पलायन के बाद से भारत ने यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के साथ सीधे टकराव के बजाय शांत कूटनीति को प्राथमिकता दी। लेकिन हसीना को शरण देने से इस्लामवादी नियंत्रण वाली यूनुस सरकार भारत से नाराज हो गई। हसीना का 15 वर्ष का शासन भारत-बांग्लादेश संबंधों में सबसे उत्पादक और सौहार्दपूर्ण रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें जबरन हटाया जाना भारत के लिए बड़ा झटका था। हालांकि, ब्रह्मपुत्र और गंगा के जल प्रवाह पर नियंत्रण और बांग्लादेश को पावर ग्रिड से बिजली सप्लाई के चलते भारत आज भी बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखने की हैसियत में है।

चुनाव नजदीक आते ही हसीना मुखर हो गई हैं। ढाका छोड़ने के बाद पिछले सप्ताह अपने पहले सार्वजनिक भाषण में उन्होंने बांग्लादेशियों से यूनुस सरकार और उनके कट्टरपंथी समर्थकों को उखाड़ फेंकने की अपील की। भारत बीएनपी की जीत की उम्मीद कर रहा है। ओपिनियन पोल्स में बीएनपी को 70% से अधिक समर्थन मिल रहा है। बीएनपी अतीत में भारत-विरोधी रही है, लेकिन रहमान के नेतृत्व में पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी, आर्थिक विकास पर केंद्रित और भारत से सहयोग रखने वाली सरकार चलाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंदी जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) है। बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो चुकी हैं। हसीना की अवामी लीग के खिलाफ पहले दोनों ही दल सहयोगी थे, लेकिन अब लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहां बीएनपी कट्टर इस्लामवाद से मध्यमार्गी विचारधारा की ओर आई है, वहीं जमात विषैले कट्टरपंथ की ओर बढ़ी है। जमात के संयोजक नाहिद इस्लाम ने टी-20 विश्व कप में भारत में मैच नहीं खेलने संबंधी सरकारी फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। नतीजतन, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया।

बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावना तब चरम पर आ गई, जब आईपीएल से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया। भारत-विरोधी गुस्सा इतना गहरा था कि इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी वित्तीय नुकसान तक उठाना पड़ा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार 'जो टीमें टूर्नामेंट में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़तीं, उन्हें भी 3,82,500 डॉलर की इनामी राशि मिलती है। 9वें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2,47,500 डॉलर मिलते हैं। 13वें से 20वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2,25,000 डॉलर मिलते हैं। मैच जीतने पर हर टीम को 31,154 डॉलर अतिरिक्त मिलते हैं। हिस्सा लेने वाली टीमों को आईसीसी तीन से पांच लाख डॉलर तक की फीस भी देता है, जो स्थानीय क्रिकेट बोर्ड को जाती है।'

भारत बीएनपी की जीत की उम्मीद कर रहा है। यह अतीत में भारत-विरोधी पार्टी रही है, लेकिन हाल में इसने धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी, विकास पर केंद्रित और भारत से सहयोग रखने वाली सरकार चलाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

आम चुनाव से पहले भारत ने बांग्लादेश के साथ तनाव घटाने की कोशिश की है। लेकिन चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति भारत को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत होगी। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। हमारे यहां पश्चिम बंगाल और असम में लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं। इस बीच, पाकिस्तान बांग्लादेश में नया भारत-विरोधी 'पूर्वी पाकिस्तान' बनाने की कोशिश में है। चीन बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की तैयार कर रहा है। अमेरिका ने भी बांग्लादेश में सक्रियता बढ़ा दी है।

क्या रहमान की बीएनपी वास्तव में एक समावेशी और सुधारवादी सरकार बना पाएगी? शेख हसीना इस पर आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन भारत उम्मीद करेगा कि निर्वासन में बिताए एक दशक ने बीएनपी के रहमान का रुख नरम किया होगा। जमात जैसे कठोर इस्लामवादी विपक्ष के सामने रहमान को चरमपंथ के बजाय मध्यमार्गी विचारधारा से शासन चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एआई • कम्प्यूटरों ने गणित सीखने की जरूरत को खत्म नहीं किया था, सोच-विचार का महत्व भी बना रहेगा

एआई का फायदा उठाना है तो शिक्षा पर ज्यादा फोकस करें

एजुकेशन

पेनी गोल्डबर्ग
वर्ल्ड बैंक की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट और येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

पिछले दो सालों में जिस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएम) ने तरक्की की है, उससे यह अंदेशा जताया जाने लगा है कि एआई जल्द ही कॉलेज शिक्षा, विशेषकर लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई को अप्रासंगिक बना देगा। ऐसे में युवाओं के लिए कॉलेज छोड़कर सीधे काम पर लगना बेहतर होगा। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं। व्यावहारिक अनुभव के जरिये सीखना तो मूल्यवान है ही, लेकिन यह तभी कारगर होता है, जब लोगों को इस बात की अच्छी समझ हो कि कौन-सी नौकरियां और स्किल्स भविष्य में भी मांग में रहेंगे। यह सच है कि रोजगारों का भविष्य अनिश्चित है। लेकिन युवाओं को कॉलेज छोड़कर जल्द से जल्द श्रम बाजार में प्रवेश करने की सलाह देना तो भ्रामक ही कहलाएगा।

आधुनिक एआई के अग्रदूत कहलाने वाले जेफ्री हिंटन ने कभी अपनी फील्ड में हो रही घटनाओं की तुलना 'कोहरे' में रास्ता खोजने से की थी : यह कि आप सामने का रास्ता तो देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या है, यह नहीं। ऐसे में शिक्षकों के सामने चुनौती यह है कि वे छात्रों को ऐसे हालात में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करें। इसका समाधान उन्हें उन कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना नहीं है, जो जल्द ही अप्रचलित हो सकते हैं। बल्कि उन्हें ज्यादा एडाप्टेबल बनाना है।

इस नजरिये से तो शिक्षा- और विशेष रूप से उच्च शिक्षा की भूमिका पहले से कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि हमें यह नहीं पता कि भविष्य में कौन-सी स्किल्स मांग में होंगी, इसलिए बुनियादी चीजों की ओर लौटना अनिवार्य है। लिबरल शिक्षा इस पर जोर देती है कि कैसे सोचा जाए, न कि इस पर कि क्या किया जाए। यह छात्रों को तर्क करना, ध्यान से पढ़ना, स्पष्ट रूप से लिखना और साक्ष्यों का मूल्यांकन करना सिखाती है। ये कौशल दूसरी तकनीकी दक्षताओं की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि तकनीकी की अनदेखी की जाए। इसके उलट, छात्रों को एआई के साथ काम करना सीखना ही होगा। लेकिन इसका मकसद उन्हें एआई उपकरणों का निष्क्रिय उपभोक्ता बनाने के बजाय उनका सजग यूजर बनाना होना चाहिए। गणित, तर्कशास्त्र और विवेचन सिखाना; बुनियादी किताबों से जुड़ना; और यह समझना कि तर्क कैसे गढ़े और कैसे परखे जाते हैं- ये सब आज भी अनिवार्य हैं। यही वे कौशल हैं, जो हमें तकनीक से आगे बने रहने में सक्षम बनाते हैं।

हमें क्या पढ़ाना चाहिए, और कैसे पढ़ाना चाहिए? पहला प्रश्न कठिन है और स्वाभाविक रूप से बहस को जन्म देगा। मूल अवधारणाओं के महत्व पर व्यापक सहमति हो सकती है, लेकिन विवरण समय के साथ बदलते रहेंगे। पहले की तकनीकों के साथ हमारा अनुभव देखें। कैलकुलेटर और कंप्यूटर ने अंकगणित पढ़ाने की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर दिया था। छात्र आज भी यह सीखते हैं कि गणनाएं कैसे काम करती हैं। इसी तरह, वर्तनी और व्याकरण भी आज भी महत्वपूर्ण हैं।

एआई के कारण अनेक क्षेत्रों में इसी तरह के एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। एलएलएम अब किसी लेख का सार निकालने या उसके केंद्रीय विचार को पहचानने जैसे कार्य अत्यंत कुशलता से करने लगे हैं। ये लंबे समय से शिक्षा के मूल तत्व रहे हैं। यही बात तेजी से प्रोग्रामिंग, ड्राफ्टिंग आदि तैयार करने पर भी लागू हो रही है। यद्यपि इन गतिविधियों को पाठ्यक्रम से हटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनके उद्देश्य में बदलाव अब जरूरी हो गया है। छात्रों को चीजों के बुनियादी कॉन्सेप्ट और लॉजिक को बेहतर ढंग से समझना होगा।

दलील दी जाती है कि एआई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता को कम कर देगा, क्योंकि यह मांग के अनुसार जानकारी और गाइडेंस उपलब्ध करा सकता है। लेकिन यह धारणा इस मान्यता पर टिकी है कि यूजर्स को पता होता है कि क्या पूछना है और उन्हें मिलने वाले उत्तरों की व्याख्या कैसे करनी है। जबकि असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति ही इससे लाभ पा सकते हैं, और वे तो वैसे भी सफल होते। यदि एआई से समाज को लाभ पहुंचाना है, तो शिक्षा में कम नहीं, ज्यादा निवेश की जरूरत होगी।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

बिज़नेस भास्कर
Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ
नई दिल्ली, गुरुवार 29 जनवरी, 2026

बिजनेस ब्रीफ

बीईएल का मुनाफा 21% बढ़कर ₹1,590 करोड़

मुंबई | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 20.8% बढ़कर 1,590 करोड़ रु. पर पहुंच गया। यह एक साल पहले समान तिमाही में 1,316 करोड़ था। बीती तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 24% बढ़कर 7,122 करोड़ हो गई। यह एक साल पहले समान तिमाही में 5,756 करोड़ थी। नतीजे आने के बाद बीएसई पर कंपनी के शेयर 10% उछलकर 52 हफ्तों की ऊंचाई 458 पर पहुंच गए।

बाजार में कमजोरी, बोट ने दूसरी बार टाला आईपीओ

नई दिल्ली | कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने सेबी से मंजूरी मिलने के बावजूद अपना आईपीओ एक बार फिर टाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने बाजार के हालात और आंतरिक तैयारियों की समीक्षा के लिए पब्लिक इश्यू पर फिलहाल रोका है। यह बोट की दूसरी आईपीओ कोशिश है। इससे पहले जनवरी 2022 में 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कमजोर बाजार और वैल्यूएशन में गिरावट के चलते टाल दी गई थी।

सॉफ्टबैंक ओपनएआई में 2.7 लाख करोड़ लगाएगा

न्यूयॉर्क | जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप ओपनएआई में 30 अरब डॉलर (2.7 लाख करोड़ रुपए) तक अतिरिक्त निवेश पर बातचीत कर रही है। यह निवेश 100 अरब डॉलर के फंडिंग राउंड का हिस्सा हो सकता है, जिससे ओपनएआई का वैल्यूएशन करीब 830 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। दिसंबर में सॉफ्टबैंक ने ओपनएआई में 41 अरब डॉलर (3.7 लाख करोड़ रुपए) निवेश कर 11% हिस्सेदारी ली थी। रिपोर्ट के बाद टोक्यो में सॉफ्टबैंक के शेयर 3.5% चढ़े।

एसबीआई कार्ड: प्रॉफिट 45% बढ़ा, 557 करोड़

नई दिल्ली | एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 45% सालाना वृद्धि के साथ 557 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। यह पिछले साल की समान अवधि में 383 करोड़ रुपए था। डिजिटल ट्रांजेक्शन और त्योहारी सीजन में कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल से कंपनी की कुल आय भी 12% बढ़कर 5,353 करोड़ रु. पर पहुंच गई। यह पिछले साल समान तिमाही में 4,767 करोड़ थी।

जॉब्स मार्केट के नए हब • इंदौर, जयपुर, सूरत, ठाणे जैसे टियर-2 शहरों में कंपनियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल रही हैं, क्वालिटी जॉब पैदा हो रहे

टियर-2 शहरों में सीनियर लेवल पर 28 लाख का पैकेज, मेट्रो के करीब

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

इंदौर, जयपुर, सूरत, ठाणे, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे टियर-2 शहर अब कमाई के मामले में टियर-1 शहरों को टक्कर दे रहे हैं। इन शहरों में सीनियर लेवल के प्रोफेशनल्स का औसत पैकेज 28.38 लाख तक पहुंच गया है। यह टियर-1 शहरों के औसत 32.40 लाख रुपए के करीब है। रैंडस्टैड एनुअल सैलरी ट्रेंड्स रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक बड़ी कंपनियां अब छोटे शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) खोल रही हैं, जिससे वहां लीडरशिप रोल की मांग बढ़ी है। रैंडस्टैड इंडिया के एमडी और सीईओ विश्वनाथ पीएस का कहना है कि ग्रोथ का यह विकेंद्रीकरण भारतीय रोजगार बाजार का सबसे बड़ा बदलाव है। अब बैंकिंग, टेलीकॉम और एनर्जी जैसे सेक्टर में भी छोटे शहरों में बड़े शहरों जैसी तरक्की मिल रही है।

दबदबा: आईटी में सबसे ज्यादा 35.66 लाख औसत सैलरी

- आईटी सेक्टर वेतन के मामले में सबसे आगे। सीनियर आईटी प्रोफेशनल्स की औसत सैलरी 35.66 लाख रुपए रही।
- मिड-लेवल 20.75 लाख व जूनियर लेवल वाले औसतन 6.65 लाख सालाना कमा रहे हैं।
- मिड लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर को औसतन 17.27 लाख और पीएचपी डेवलपर को 16.86 लाख मिल रहे हैं।
- जावास्क्रिप्ट डेवलपर 16.72 लाख रुपए और प्रोडक्ट मैनेजर 16.25 लाख रुपए का औसत पैकेज पा रहे हैं।
- क्लाउड आर्किटेक्ट की सैलरी भी 16 लाख रुपए के अधिक है।
- एआई, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्युरिटी जैसे एडवांस स्किल्स की मांग सप्लाई से ज्यादा है। लेकिन प्रोफेशनल्स की भारी कमी बनी हुई है।
- कंपनियां अब अनुभव के बजाय स्किल और परफॉर्मेंस के आधार पर भारी-भरकम इंसेंटिव मॉडल अपना रही हैं।
- एनर्जी, यूटिलिटी में सीनियर स्तर पर 24 लाख तक का वेतन मिल रहा है, रियल्टी में औसत वेतन 24 लाख है।

विस्तार: एनर्जी, रियल एस्टेट की मांग बढ़ी

- सैलरी में बढ़ोतरी अब सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है। एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर में सीनियर लेवल पर 24 लाख रुपए तक का पैकेज मिल रहा है।
- आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (आईटीईएस) सेक्टर में 24.70 लाख रुपए और रियल एस्टेट में औसत वेतन 24.11 लाख रुपए पहुंच गया है।

स्थिरता: टियर-1 में औसत वेतन 32 लाख

- वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद महानगरों में सैलरी का ग्राफ स्थिर रहा। यहां जूनियर लेवल का औसत वेतन 5.92 लाख रुपए रहा।
- मिड-लेवल पर वेतन 16.70 लाख रुपए रहा। सीनियर लेवल का पैकेज 32.40 लाख रुपए रहा, जो एक मैच्योर सैलरी साइकल को दर्शाता है।

रणनीति: जीसीसी हब से समीकरण बदले

इंदौर-जयपुर जैसे शहर अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। यहां इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स से जुड़े जटिल काम हो रहे हैं। इन भूमिकाओं के लिए हाई-स्किल्ड लीडर्स की जरूरत है, जिससे कंपनियां योग्यता पर पैसा खर्च कर रही हैं।

बचत: छोटे शहरों में 30% तक बड़ी बचत

महानगरों के मुकाबले टियर-2 शहरों में रहना सस्ता है। टियर-2 शहरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की 'इन-हैंड'' बचत महानगरों के मुकाबले 20 से 30% तक ज्यादा हो रही है। यही वजह है कि अब सीनियर टैलेंट वेल्थ क्रिएशन के लिए छोटे शहरों का रुख कर रहा है।

ट्रेड डील का असर • बाजार दूसरे दिन चढ़ा, सेंसेक्स एक बार फिर 82,000 पार

जिन सेक्टरों को ईयू डील से लाभ, उनके टॉप-5 शेयर अभी रिकॉर्ड ऊंचाई से 46% तक नीचे

भास्कर न्यूज | मुंबई

यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भारत का व्यापार समझौता असर दिखाने लगा है। शेयर बाजार में बुधवार को सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 82,349 पर पहुंचा। निफ्टी 167 अंकों की तेजी के साथ 25,343 पर बंद हुआ। बीएसई पर सर्वाधिक कैपिटल गुड्स इंडेक्स में 5.3% तेजी दर्ज की गई। 4% बढ़त के साथ ऑयल-गैस इंडेक्स दूसरे स्थान पर और इंडस्ट्रियल्स इंडेक्स 3.5% तेजी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। निफ्टी के स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 2.26% उछाल आया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स भी 1.66% बढ़त पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स (0.6%) के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा तेजी है। बहरहाल, जिन सेक्टरों को यूरोप से ट्रेड डील का लाभ मिलने वाला है, उनके टॉप-5 शेयर अभी रिकॉर्ड ऊंचाई से 46% तक नीचे हैं।

कोटक म्यूचुअल फंड में सीनियर फंड मैनेजर शिवानी कुरियन के मुताबिक ईयू डील से बाजार को ट्रिगर मिला है। यूरोपीय संघ के देशों को भारत सालाना 7 लाख करोड़ का निर्यात करता है। इसलिए बड़ा फर्क पड़ेगा। भारतीय टेक्सटाइल व अपैरल कंपनियां बिना किसी टैक्स के निर्यात कर पाएंगी, जैसा कि बांग्लादेश जैसे देशों की कंपनियां करती हैं।

भास्कर रिसर्च डील से फायदे वाले 4 प्रमुख सेक्टरों के शेयर काफी सस्ते

टेक्सटाइल

शेयर	मौजूदा भाव	ऊंचाई से नीचे
पेज इंडस्ट्रीज	₹32,617	35%
केपीआर मिल	₹927	33%
ट्राइडेंट	₹26	26%
वर्धमान टेक्सटाइल्स	₹413	23%
वेलस्पन लिविंग	₹35	19%

जेम्स-ज्वेलरी

शेयर	मौजूदा भाव	ऊंचाई से नीचे
पीसी ज्वेलर्स	₹10.5	46%
सेनको गोल्ड	₹315	42%
कल्याण ज्वेलर्स	₹368	40%
थंगामायिल ज्वेलरी	₹3,590	13%
टाइटन कंपनी	₹3977	8%

फुट वियर

शेयर	मौजूदा भाव	ऊंचाई से नीचे
बाटा इंडिया	₹854	40%
रिलैक्सो फुटवियर्स	₹379	37%
लिबर्टी शूज	₹260	33%
मेट्रो ब्रांड्स	₹1021	24%
कैंपस एक्टिववियर	₹253	20%

हैवी-इंडस्ट्री

शेयर	मौजूदा भाव	ऊंचाई से नीचे
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स	₹4,626	22%
एबीबी इंडिया	₹5,046	20%
सीमेंस	₹2,980	18%
एलएंडटी	₹3,794	10%
बीईएल	₹453	1%

नोट: शेयरों में गिरावट 52 हफ्तों की ऊंचाई से, स्रोत: बीएसई

ईयू डील का फायदा दिखने में वक्त लगेगा, ऐसे में अमेरिका के साथ डील हुई तो तेज रिकवरी

भास्कर एक्सपर्ट
सनी अग्रवाल, रिसर्च हेड, एसबीआई सिक्युरिटीज

यह ईयू डील बाजार के लिए यह 'पॉजिटिव संकेत' है, लेकिन असली मुनाफा नंबर्स में दिखने में 2-3 साल लगेंगे। यूरोप सालाना 264 अरब डॉलर का टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 7 अरब डॉलर है। इसी तरह लेदर-फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स और जेम्स-ज्वेलरी और अन्य सेक्टरों में भी हमारी हिस्सेदारी 1-2% है, जिसे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। टेक्सटाइल, जूलरी कंपनियां अभी अमेरिकी टैरिफ के चलते दबाव में हैं। जब तक अमेरिका साथ डील नहीं हो जाती, तब तक 'इवेंट' के आधार पर निवेश करना जल्दबाजी हो सकता है। इस डील का बड़ा फायदा यह है कि भारत में फैक्ट्री लगाना आसान होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की गति को रफ्तार मिलेगी। यूरोप खासकर जर्मनी से आने वाली हाई-एंड मशीनरी (जैसे सेमीकंडक्टर मशीन, बॉयलर आदि) सस्ती होगी। इससे भारत में प्लांट लगाने की लागत कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी।

बजट से पहले डिफेंस, रेलवे और इंफ्रा में मोमेंटम बढ़ा

- *मंथली-वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद बुधवार को नए सीरीज के पहले दिन सेलिंग प्रेशर कम रहा।*
- *बाजार काफी समय से गिर रहा था। ओवरसोल्ड था, जिससे निचले स्तरों पर थोड़ी वैल्यू बाइंग शुरू हुई।*
- *आगामी बजट के मद्देनजर डिफेंस, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में तेजी का माहौल है।*
- *बीईएल जैसी कंपनियों के अच्छे नतीजों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।*

टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी जैसे सेक्टरों के शेयर चढ़ेंगे

यूरोप के साथ ट्रेड डील से भारत के टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी, लेदर-फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, रबर और खिलौनों से जुड़ी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। आगामी महीनों और वर्षों (2027) में इन्हीं सेक्टरों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी जा सकती है।

- डॉ. वीके विजयकुमार,
मुख्य निवेश रणनीतिकार, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स

ट्रेंड्स • 'गोल्ड लोन' में 10 राज्यों का शेयर 90%

गोल्ड लोन 2 वर्ष में डबल, इसमें दक्षिण भारत का हिस्सा 76%

भास्कर न्यूज | मुंबई

सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच भारत में गोल्ड लोन का बाजार बढ़ रहा है। नवंबर 2025 तक के एक साल में गोल्ड लोन के वितरण में 42% का उछाल देखा गया, जबकि इससे पिछले साल 39% की वृद्धि थी। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो नवंबर 2023 के 7.9 लाख करोड़ से बढ़कर नवंबर 2025 में 15.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षित कोलैटरल और बढ़ी हुई लोन पात्रता के कारण बैंकों और ग्राहकों, दोनों का रुझान इस ओर बढ़ा है। गोल्ड लोन का 76% हिस्सा दक्षिणी राज्यों में है और शीर्ष 10 राज्यों की कुल बकाया राशि में 90% हिस्सेदारी है। तमिलनाडु 3.56 लाख करोड़ के साथ सबसे बड़ा बाजार है। गुजरात में गोल्ड लोन लेने की रफ्तार (66.8%) सबसे तेज है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में बकाया ऋण का अनुपात अधिक है, जो भविष्य में फाइनेंशियल सिस्टम का तनाव बढ़ा सकता है।

तमिलनाडु 3.56 लाख करोड़ के साथ सबसे आगे, गुजरात में ग्रोथ सबसे तेज

राज्य	बकाया राशि	कुल हिस्सा	सालाना वृद्धि
तमिलनाडु	3.56	22.8%	34.6%
आंध्र प्रदेश	1.99	12.8%	31.8%
कर्नाटक	2.20	14.1%	51.5%
तेलंगाना	1.58	10.1%	34.9%
केरल	1.51	9.7%	33.3%
महाराष्ट्र	0.91	5.8%	53.6%
गुजरात	0.68	4.4%	66.8%
राजस्थान	0.40	2.5%	45.4%
उत्तर प्रदेश	0.54	3.5%	46.8%
ओडिशा	0.28	1.8%	55.6%
शीर्ष 10 राज्य	14.16	90.8%	42.4%
अखिल भारतीय	15.62	100.0%	41.9%

*बकाया राशि लाख करोड़ में

2.5 लाख+ कर्ज का हिस्सा सर्वाधिक 36%

- सक्रिय लोन 10% बढ़ा, पर लोन वैल्यू 42% बढ़ी। यानी लोग सोने पर बड़ा लोन ले रहे हैं।
- 2.5 लाख+ कर्ज अब कुल बुक का आधा है, जो मार्च 2023 में 36.4% थे।
- 50,000 से कम लोन का शेयर पोर्टफोलियो वैल्यू के मामले में घटकर मात्र 7.5% रह गई है।
- 25-35 वर्ष और 35-45 वर्ष के आयु वर्ग के लोग गोल्ड लोन बाजार के सबसे बड़े ग्राहक हैं।

चांदी 3.6 लाख पार, जनवरी में अब तक 1,31,401 रुपए बढ़े दाम

चांदी की कीमत बुधवार को 17,257 रु. बढ़कर 3,61,821 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 4,926 रुपए और महंगा होकर 1,58,901 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। असल में बाजार को आशंका है कि इस साल के बजट में सरकार सोने-चांदी के आयात पर शुल्क बढ़ाया जा सकता है। इनकी बढ़ती कीमतों के बीच व्यापार घाटा कम करके रुपए में स्थिरता लाना उद्देश्य हो सकता है। जनवरी माह में अब तक चांदी 131401 रुपए (57.03%) महंगी, 24 कैरेट सोना 30632 रुपए (23%) प्रति 10 ग्राम महंगी हुई है।

कार्बन टैक्स का मामला...

यूरोप में फंसा भारतीय स्टील, कारण ऑर्डर रद्द

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

यूरोपीय संघ के नए कार्बन टैक्स नियमों ने भारतीय स्टील निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अनुपालन रिपोर्ट न होने से यूरोपीय बंदरगाहों पर भारत की 10 बड़ी खेप रोक दी गई हैं। इससे न केवल माल जब्त हो रहा है, बल्कि लागत से ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं। दरअसल, ईयू ने 1 जनवरी से अधिक कार्बन खपत वाले स्टील और सीमेंट पर 'कार्बन शुल्क' अनिवार्य कर दिया है। इससे निर्यातकों की लागत कई गुना बढ़ गई है। मुंबई के एक मामले में 7,000 टन स्टील का ऑर्डर इसलिए रद्द हो गया क्योंकि टैक्स के कारण लागत 6 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। मुक्त व्यापार समझौते में भी भारत को इस पर छूट नहीं मिली है। इसका बड़ा असर लुधियाना, मुंबई के 30 हजार छोटे उद्योगों पर पड़ा है, जिनका 45% निर्यात यूरोप को होता है।

टेक सपोर्ट • एआई बूम से अमेरिकी बाजार में नया रिकॉर्ड

एसएंडपी 500 पहली बार 7,000 पार, दो साल में 40 फीसदी उछाल

भास्कर न्यूज | न्यूयॉर्क

अमेरिकी शेयर बाजार में बुधवार को नया इतिहास बना, जब एसएंडपी 500 इंडेक्स पहली बार 7,000 अंक के स्तर को पार कर गया। बाजार को यह मजबूती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर बढ़ते निवेशक भरोसे, बिग टेक कंपनियों की मजबूत कमाई की उम्मीदों और आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं से मिली।

पिछले कुछ वर्षों में एसएंडपी 500 की रफ्तार काफी तेज हुई है। 4,000 से 5,000 अंक तक पहुंचने में जहां करीब तीन साल लगे थे, वहीं 5,000 से 6,000 पहुंचने में करीब 9 महीने लगे। अब 7,000 अंक तक का सफर करीब 14 महीनों में तय हुआ था। एसएंडपी500 ने नवंबर 2024 में 6000 का स्तर छुआ था। यानी करीब 2 साल में यह मार्केट इंडेक्स 40 फीसदी बढ़ चुका है। एआई से जुड़ी कंपनियां जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट इस तेजी की अगुवाई कर रही हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर का एसएंडपी 500 में करीब 50% वेटेज है, जिससे इसका असर पूरे बाजार पर साफ दिख रहा है।

दरें घटेंगी!... एसएंडपी500 का मुनाफा 15% बढ़ने की उम्मीद

निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरें घटा सकता है, हालांकि मौजूदा बैठक में ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार, 2026 में एसएंडपी 500 यानी अमेरिकी टॉप 500 कंपनियों के मुनाफे में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। एआई के दम पर टेक सेक्टर अमेरिकी कॉरपोरेट ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है।

बजट • हेल्थ इंश्योरेंस पर मिले ज्यादा छूट

स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए करने की उठी मांग

अक्षरा श्रीवास्तव | नई दिल्ली

इस बार उपभोक्ता बजट को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। पिछले बजट से संतुष्टि के बावजूद इस बार आर्थिक सुस्ती, आय की स्थिरता और भविष्य की तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ी है। यही वजह है कि लोग खर्च को लेकर ज्यादा सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। कैंटा के इंडिया यूनियन बजट सर्वे-2026 रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स से आगे बढ़कर अब उपभोक्ताओं की सोच में सतर्कता दिख रही है। महंगाई, नौकरी की सुरक्षा और वैश्विक अनिश्चितताओं ने घरेलू फैसलों को प्रभावित किया है। गैर-जरूरी खर्चों में कटौती हो रही है। सर्वे में शामिल उपभोक्ताओं का मानना है कि सरकार को टैक्स राहत के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा और स्पष्ट नीतिगत दिशा पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग का भरोसा मजबूत हो सके। सर्वे के अनुसार, मध्यम वर्ग के बीच व्यक्तिगत टैक्स सुधारों की मांग बनी हुई है। लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 80 के तहत मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस पर ज्यादा छूट और रिबेट की मांग भी की जा रही है।

भरोसा • आदित्य बिड़ला ग्रुप का बड़ा दांव

वोडा आइडिया 3 साल में 45,000 करोड़ लगाएगी

भास्कर न्यूज | मुंबई

वोडाफोन आइडिया (वीआई) ने बुधवार को अपनी वीआई 2.0 रणनीति के तहत अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश (कैपेक्स) की योजना पेश की। कंपनी का लक्ष्य इस दौरान डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तीन गुना वृद्धि और लगातार सब्सक्राइबर जोड़ना है। मुंबई में आयोजित एनालिस्ट मीट में कंपनी ने बताया कि पिछले छह क्वार्टर में किए गए 18,000 करोड़ के निवेश को जोड़ने पर कुल नेटवर्क निवेश साढ़े चार साल में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। सीईओ अभिजीत किशोर ने कहा कि फिलहाल इक्विटी जुटाने का इरादा नहीं है। अगले 12-30 महीनों में 20,000 से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में 5जी कवरेज विस्तार किया जाएगा। उधर, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा- एजीआर मुद्दे का समाधान निर्णायक मोड़ है। पहली बार वर्षों में धुंध साफ हुई है। अब कंपनी सर्वाइवल से आगे बढ़कर स्थायी ग्रोथ पर फोकस कर सकती है।

इंडस्ट्री • मैन्युफैक्चरिंग बनी ग्रोथ इंजन

औद्योगिक उत्पादन 2 साल के उच्चतम स्तर 7.8% पर

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर बढ़ा है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के चलते औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर दो साल के उच्चतम स्तर 7.8% पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, दिसंबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 3.7% थी, जिससे इस साल के आंकड़े अधिक मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनोमिस्ट मदन सबनबीस ने कहा, 'दिसंबर में 7.8% की ऊंची वृद्धि मैन्युफैक्चरिंग में रिकवरी और लो-बेस इफेक्ट के कारण संभव हुई। नवंबर-दिसंबर में लगातार मजबूत ग्रोथ जीएसटी रेशनलाइजेशन के बाद अपेक्षित मजबूती और निवेश गतिविधियों को दर्शाती है। यह रफ्तार बनी रही तो पूरे वित्त वर्ष में आईआईपी ग्रोथ 4.5-5% रह सकती है।

मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग सेक्टर में उछाल

सेक्टर	दिसं. 25 वृद्धि	दिसं. 2024 वृद्धि
मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन	8.1%	3.7%
माइनिंग उत्पादन	6.8%	2.7%
बिजली उत्पादन	6.3%	6.2%

बिजनेस एंकर रोजमर्रा की छोटी जरूरतों के लिए इंस्टेंट लोन की सुविधा का फायदा उठा रहे भारतीय

क्रेडिट कार्ड लेनदेन 24% बढ़ा, पर प्रति कार्ड औसत खर्च 12% घटा, वजह हम बड़ी खरीदारी में कार्ड का इस्तेमाल करने से बच रहे

सुनयना चड्ढा | नई दिल्ली

देश में क्रेडिट के इस्तेमाल के मामले में दिलचस्प ट्रेंड देखा जा रहा है। लोगों की जेब से क्रेडिट कार्ड बार-बार निकल रहे हैं। किराना और ऑनलाइन ऑर्डर जैसी ज्यादातर छोटी-मोटी खरीदारी इसी से हो रही है। लेकिन महीने के अंत में कुल खर्च पिछले साल जितना या थोड़ा ही ज्यादा आ रहा है। बीते दिसंबर में ऐसा ही हुआ। क्रेडिट कार्ड से लेनदेन सालाना 24% बढ़ा, लेकिन कुल खर्च में 9% ही बढ़ोतरी हुई। असित सी. मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अब बड़ी खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं, हालांकि रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए इंस्टेंट लोन की सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। दिसंबर में प्रति क्रेडिट कार्ड औसत खर्च 17,672 रुपए रहा। यह नवंबर के मुकाबले तो 7.6% ज्यादा है, लेकिन पिछले साल दिसंबर की तुलना में 12% कम है। यानी लोग अब कार्ड से सिर्फ 500 रुपए तक के छोटे-छोटे पेमेंट कर रहे हैं। वजह ये भी है कि कुल क्रेडिट कार्ड खर्च में अब ऑनलाइन खरीदारी की हिस्सेदारी 62% हो गई है, जबकि पीओएस पर स्वाइप की हिस्सेदारी घटकर 38% रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रिवॉर्ड्स, क्रेडिट पीरियड और सुविधा इसकी एक वजह हो सकती है।

बीते महीने क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या भी 92 लाख बढ़कर 11.58 करोड़ हो गई। सालाना ग्रतो 7.2% रही। इस मामले में मिड-साइज बैंकों ने तेज ग्रोथ दिखाई है। मसलन फेडरल बैंक की कार्ड ग्रोथ 77% रही। बैंक ज्यादा कार्ड जारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही नियम भी सख्त कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने 15 जनवरी 2026 से फीस, रिवॉर्ड्स, एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स और इंटरनेशनल यूज चार्जेस बढ़ा दिए हैं। नतीजतन अब लोग "डिफेंसिव" मोड में हैं। कार्ड रखते हैं, पर सिर्फ इमरजेंसी, छोटे पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स के लिए। 2025 पूरे साल क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 23.2 लाख करोड़ रुपए रहा।

दिसंबर में क्रेडिट कार्ड ग्रोथ फ्लैट, दो तिहाई खरीदारी ऑनलाइन

क्रेडिट कार्ड से खर्च 9% बढ़ा
कुल खर्च: 2,04,600 करोड़
मासिक वृद्धि: 8.4%
वार्षिक वृद्धि: 8.8%

लेनदेन में भी 24% बढ़ोतरी
कुल लेनदेन: 53.7 करोड़
मासिक वृद्धि: 7.3%
सालाना वृद्धि: 24.2%

पर कार्ड 1% भी नहीं बढ़े
कुल कार्ड: 11.6 करोड़
मासिक वृद्धि: 0.86%
सालाना वृद्धि: 0.79%

प्रति कार्ड औसत खर्च स्थिर
औसत कार्ड खर्च: 17,672
मासिक गिरावट: -12.5%
सालाना वृद्धि: +4.1%

उछाल • त्योहारों पर नकदी की मांग बढ़ी, कर्नाटक सबसे आगे

एटीएम से कैश निकासी का टूटा रिकॉर्ड, हर महीने औसतन 1.26 करोड़ रु. निकले

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भारतीयों के बीच आज के डिजिटल दौर में नकदी (कैश) का मोह कम नहीं हो रहा है। देश में कैश लेनदेन की रफ्तार डिजिटल भुगतान के साथ-साथ मजबूती से बढ़ रही है। सीएमएस कंजम्पशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में त्योहारों के सीजन के दौरान एटीएम से कैश निकालने का रिकॉर्ड टूट गया। इसका मासिक औसत 1.26 करोड़ रुपए प्रति एटीएम तक पहुंच गया। जून में यह 1.12 करोड़ रुपए के साथ साल के सबसे निचले स्तर पर था। इससे साफ है कि मानसून के बाद खरीदारी में 12% का जबरदस्त उछाल आया। नकदी की बढ़ती डिमांड इस बात का प्रमाण है कि छोटे और बड़े दोनों बाजारों में लोगों की खर्च करने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ा है।

निकासी: एटीएम से एक बार में औसतन 5,835 निकाल रहे लोग: एटीएम से निकाली जाने वाली औसत राशि (टिकट साइज) में भी निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। साल 2025 में औसत टिकट साइज 4.5% बढ़कर 5,835 रुपए हो गया है। त्योहारों के दौरान अक्टूबर 2025 में यह और भी बढ़कर 5,846 रुपए तक पहुंच गया था। यह 2024 में 5,586 रुपए और 2023 मे 5,471 रुपए था।

दबदबा: कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1.73 करोड़ की निकासी

देश में एटीएम से कैश निकालने के मामले में कर्नाटक सबसे आगे रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में प्रति एटीएम मासिक औसत निकासी 1.73 करोड़ रु. रही। इसके बाद पश्चिम बंगाल (1.65 करोड़) और तमिलनाडु (1.62 करोड़) का नंबर रहा। दिल्ली में यह आंकड़ा 1.30 करोड़ रु. रहा।

जो अस्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को खो देते हैं,
वे न तो स्वतंत्र होने लायक हैं और न सुरक्षित होने लायक
– बैंजामिन फ्रैंकलिन

हादसे के सबक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की एक विमान हादसे में मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। इस त्रासदी ने न केवल देश के एक कुशल नेता को छीन लिया, बल्कि उन दर्दनाक हादसों की कड़वी यादें भी ताजा कर दीं, जिनमें पहले भी देश ने कई राजनीतिक दिग्गजों और प्रमुख हस्तियों को असमय खोया है। पुणे जिले के बारामती में हुए इस हादसे की अब कई कोणों से जांच की जा रही है, मगर सवाल है कि इससे पहले हुई ऐसी दुर्घटनाओं से क्या सरकारी तंत्र ने कोई सबक नहीं लिया? आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त हवाई अड्डे पर दृश्यता कम थी। अगर स्थिति वास्तव में जोखिमपूर्ण थी, तो विमान को उतरने की अनुमति क्यों दी गई? दूसरा, यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में क्या ऐसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे जिला के बारामती में हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीचे आने के बाद उसमें धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई। इससे पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस नेता संजय गांधी, वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया, वर्ष 2011 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, वर्ष 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वर्ष 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे दिग्गजों को भी देश ने विमान दुर्घटनाओं में खोया है। कहा जा रहा है कि अजित पवार के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो जवाब 'नहीं' था। इसके बाद विमान ने आसमान में ही एक चक्कर लगाया। इससे स्पष्ट है कि हवाई अड्डे पर परिस्थितियां विमान को उतारने के अनुकूल नहीं थीं। यह दावा भी किया जा रहा है कि दूसरी बार पूछे जाने पर पायलट ने सकारात्मक जवाब दिया। मगर सवाल है कि क्या किसी तरह के जोखिम की आशंका के बीच विमान को उतारने की अनुमति दी जा सकती है?

अजित पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उपमुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार की छत्रछाया से बाहर निकल कर उन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी के नाम और चिह्न के साथ-साथ दल के ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद वे राजग नीत महायुति में शामिल हो गए थे। उनके नेतृत्व वाली राकांपा ने हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए निकाय चुनाव में शरद पवार की अगुआई वाली पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इसके बाद सियासी गलियारों में अजित पवार और शरद पवार के बीच नजदीकियां बढ़ने की अटकलें भी जोर पकड़ रही थीं। ऐसे में विपक्षी दल इस हादसे की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस विमान दुर्घटना की निष्पक्ष और गहन जांच हो, ताकि हादसे के असली कारण सामने आ सकें। सरकारी तंत्र को भी इस तरह के हादसों से सबक लेकर व्यवस्था में जरूरी सुधार करने चाहिए, ताकि भविष्य में और कोई विमान दुर्घटना न हो।

नियमों का विरोध

इससे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज के आधुनिक परिवेश में भी समाज में जातिगत भेदभाव की धारणा बनी हुई है। यहां तक कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जाति के आधार पर भेदभाव के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम जारी किए हैं। मगर इनको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो कुछ अधिकारी भी इन नियमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही नहीं, अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है। सवाल है कि आखिर यूजीसी के इन नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल, कुछ लोगों को आशंका है कि आयोग के नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि न तो किसी के साथ भेदभाव होने दिया जाएगा और न ही नियमों के बेजा इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।

गौरतलब है कि यूजीसी ने नियमों का जो नया प्रारूप जारी किया है, उसे लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों के मामले में सजा का कोई प्रावधान नहीं है और नियमों का पालन न करने पर संस्थान पर कार्रवाई की जा सकती है। इन नियमों के विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली के एक नगर मजिस्ट्रेट और अयोध्या में एक जीएसटी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी, यह नए नियमों में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसमें दोराय नहीं कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो आशंकाएं पैदा हुई हैं, उनका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस मसले पर संयम और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।

आर्थिक असमानता की गहराती खाई

भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मगर विकास का मूल्यांकन जीडीपी की वृद्धि दर से करना बेमानी है, क्योंकि यह आंकड़ा संपत्ति के संतुलित वितरण की नहीं, बल्कि औसत आय की तस्वीर पेश करता है।

संकल्प मिश्रा

आज जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो इन चमकदार आंकड़ों के समांतर खड़ा आर्थिक असमानता का सच चिंताजनक है। यह एक गहरा विरोधाभास है कि जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर अमीर और गरीब के बीच की खाई ऐतिहासिक रूप से चौड़ी हो गई है। विकास का मूल्यांकन केवल जीडीपी की वृद्धि दर से करना बेमानी है, क्योंकि यह आंकड़ा संपत्ति के वितरण की नहीं, बल्कि औसत आय की तस्वीर पेश करता है। जमीनी सच्चाई यह है कि देश की बढ़ती संपदा का एक बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर अति-धनाढ्यों की तिजोरियों में जा रहा है, जबकि श्रमशक्ति का एक विशाल वर्ग आज भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत है। यह असमानता केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस समावेशी विकास के दावों पर एक गंभीर सवाल है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है।

इस असमानता का सबसे भयानक रूप हमें कोविड महामारी के बाद के समय में देखने को मिला। वह एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया रुक गई थी, लेकिन संपत्ति का खेल नहीं रुका। एक तरफ लाखों मध्य और निम्न-वर्गीय परिवारों की जमा-पूंजी इलाज, प्राणवायु और बेरोजगारी की भेंट चढ़ गई। करोड़ों लोग, जो अपनी मेहनत से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके थे, वापस उसके नीचे धकेल दिए गए। छोटे व्यापार बंद हो गए, नौकरियां चली गईं और प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामूहिक विवेक को झकझोर गईं। दूसरी तरफ, ठीक इसी कालखंड में देश के शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति में ऐतिहासिक और अकल्पनीय वृद्धि दर्ज की गई। जब आम आदमी कर्ज की मासिक किस्तें चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब शेयर बाजार कुलांचे भर रहा था। अर्थशास्त्रियों ने इसे 'विषम सुधार' का नाम दिया। यह एक ऐसी स्थिति थी, जहां अर्थव्यवस्था दो विपरीत दिशाओं में बंट गई। एक तरफ संगठित और अमीर वर्ग ऊपर की ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ असंगठित और गरीब वर्ग रसातल में जा रहा था।

जब एक आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त होकर अपनी थाली से सब्जियां और दाल कम करने पर मजबूर होता है और उसी वक्त देश में महंगी गाड़ियों तथा विलासिता की वस्तुओं की बिक्री के नए कीर्तिमान बनते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि समाज का संतुलन बिगड़ चुका है। इस असंतुलन की जड़ें हमारी नीतियों और कर-प्रणाली में भी गहरी धंसी हुई हैं। पिछले कुछ दशकों में उदारीकरण के नाम पर हमने जिस पूंजीवादी ढांचे को अपनाया, उसका मूल मंत्र था- 'रिसाव का सिद्धांत'। यह माना गया था कि अगर हम ऊपर के लोगों और बड़े निगमित ढांचों को समृद्ध करेंगे, उन्हें करों में छूट देंगे, तो वे निवेश करेंगे और उसका लाभ रिस-रिस कर रोजगार तथा वेतन के रूप में नीचे तक पहुंचेगा। इसके विपरीत संपत्ति का जमावड़ा ऊपर ही रुक गया और नीचे केवल बूंदें ही पहुंचीं। मुनाफे का उपयोग पुनर्निवेश और रोजगार सृजन के बजाय वित्तीय बाजारों में सट्टेबाजी और निजी संपत्ति बढ़ाने में किया गया।

हमारी कर प्रणाली, विशेष रूप से 'वस्तु एवं सेवा कर' यानी अप्रत्यक्ष करों का ढांचा, इस आग में घी डालने का काम करता है। अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, क्योंकि वे गरीब और अमीर पर लगभग एक समान बोझ डालते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कर संग्रह का बड़ा हिस्सा निचले और मध्य वर्ग की जेब से आता है। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को दी जाने वाली लाखों-करोड़ों रुपए की कर छूट और कर्ज माफी को अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए 'प्रोत्साहन' का नाम दिया जाता है। दूसरी ओर, जब किसानों की कर्ज माफी, वृद्धावस्था पेंशन या गरीबों के लिए राशन की बात आती है, तो उसे 'मुफ्त की रेवड़ी' कहकर अपमानित किया जाता है। यह दोहरा मापदंड देश की अर्थव्यवस्था और समाज में असंतुलन का कारण बनता है। असमानता का यह जहर सिर्फ बैंक खातों और आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह धीरे-धीरे समाज की नसों में उतर कर 'अवसरों की समानता' को भी खत्म कर देता है। इसका सबसे ज्यादा और दूरगामी असर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी शिक्षा और बेहतर इलाज हर नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए, न कि केवल उन लोगों का विशेषाधिकार जो इसे खरीद सकें। लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों के लिए एक महंगा सौदा बन चुकी हैं। जब एक गरीब परिवार का प्रतिभाशाली बच्चा केवल संसाधनों, अतिरिक्त शिक्षण और अच्छी किताबों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो देश केवल एक व्यक्ति का भविष्य नहीं खोता, बल्कि अपनी एक संभावना को खो देता है।

इतिहास गवाह है कि जब धन का अत्यधिक संकेंद्रण होता है, तो सत्ता और राजनीति भी उसी धन के प्रभाव में आ जाती है। ऐसे में नीतियां आम जनता, किसान और मजदूर के हितों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों के मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बनाई जाने लगती हैं। आज चुनाव, जो लोकतंत्र का उत्सव माने जाते हैं, इतने महंगे हो गए हैं कि एक सामान्य नागरिक के लिए इसमें भाग लेना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। राजनीतिक दलों का बड़े चंदे पर निर्भर होने से यह संभावना ज्यादा होती है कि चुनाव जीतने के बाद उनकी वफादारी जनता के प्रति कम और चंदा देने वालों के प्रति अधिक होगी। यह 'पूंजीवाद' का वह दौर है, जहां बाजार और सरकार के बीच की रेखा धुंधली नजर आती है।

हमें ग्रामीण भारत की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां आज भी देश की बहुसंख्यक आबादी निवास करती है। शहरों में चमकती गगनचुंबी इमारतें, द्रुतगामी रेल, चौड़े राजमार्ग और बड़े बाजार एक अलग कहानी कहते हैं, जबकि गांवों में पसरा सन्नाटा और मायूसी दूसरी कहानी बयां करती है। खेती, जो कभी सम्मान का पेशा थी, आज घाटे का सौदा बनकर रह गई है। खाद, बीज और ईंधन की लागत बढ़ रही है, लेकिन फसल का उचित 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं मिल पा रहा है। गांवों से शहरों की ओर हो रहा लोगों का अनियंत्रित पलायन इसी आर्थिक मजबूरी का परिणाम है। यह पलायन शहरों के बुनियादी ढांचे पर भी दबाव डाल रहा है और एक नए तरह के शहरी वर्ग-संघर्ष को जन्म दे रहा है।

तकनीक और वैज्ञानिक क्रांति ने भी अनजाने में ही सही, असमानता की एक नई परत जोड़ दी है। इसे 'तकनीकी खाई' या 'डिजिटल विभाजन' कहा जा रहा है। आज की दुनिया में सूचना ही शक्ति है, और यह शक्ति उनके पास है, जिनके पास आधुनिक संचार यंत्र, संगणक और तीव्र गति वाली इंटरनेट सुविधाएं हैं। ऐसे में सबसे पहले हमें विकास की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। सकल घरेलू उत्पाद से आगे बढ़कर हमें 'मानव विकास', 'खुशहाली' और 'असमानता के स्तर' को प्रगति का मुख्य पैमाना बनाना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी खर्च को एक बड़े हिस्से तक बढ़ाना होगा। साथ ही कर प्रणाली में भी सुधार करना होगा। रोजगार के मोर्चे पर हमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना होगा। उचित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा, जहां हर किसी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो?

> **जब एक आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त होकर अपनी थाली से सब्जियां और दाल कम करने पर मजबूर होता है और उसी वक्त विलासिता की वस्तुओं की बिक्री के नए कीर्तिमान बनते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि समाज का संतुलन बिगड़ चुका है। इस असंतुलन की जड़ें हमारी नीतियों और कर-प्रणाली में गहरी धंसी हुई हैं। पिछले कुछ दशकों में उदारीकरण के नाम पर हमने जिस पूंजीवादी ढांचे को अपनाया, उसका मूल मंत्र था- 'रिसाव का सिद्धांत'। यह माना गया था कि अगर हम उच्च तबके और बड़े निगमित ढांचों को समृद्ध करेंगे, तो उसका लाभ रिस-रिस कर नीचे तक पहुंचेगा।**

उपहार का सरोकार

अंब्रेश रंजन कुमार

उपहार या भेंट अपने आप में विशेष होता है। हम किसी मित्र या फिर बहुत ही विशेष शख्स के लिए बड़े चाव और सुकून से कुछ खास सामान खरीदते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि यह पाने वाले की पसंद का हो। इसे खरीदते समय हमारे मस्तिष्क में यह जरूर चल रहा होता है कि अमुक सामान जो खास व्यक्ति के लिए खरीदा जा रहा है, वह उसकी पसंद का हो, वह उसका उपयोग करेगा। कई बार यह पसंद हमें पहले से पता होती है, तो कई बार हम खोज-बीन कर इस बात का पता लगाकर सामान खरीदते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि भेंट की राशि की समीक्षा नहीं की जाती। मगर गाहे-बगाहे भेंट के सामान और उनकी उपयोगिता की समालोचना हम कर ही लेते हैं। सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर शादियों, जन्मदिन या अन्य ऐसे आयोजनों पर प्राप्त उपहार की बात करें, तो आयोजन की समाप्ति के बाद प्रत्येक उपहार को खोलकर उसे देखने की उत्सुकता अलग ही होती है। भेंट एक तरह से ऐसे आयोजनों का एक अनिवार्य घटक है, जिसके बगैर आयोजन की पूर्णता अधूरी समझी जाती है।

भेंट में औपचारिकताओं और भावनाओं के अलग-अलग स्तरों का समावेश होता है। अक्सर रिश्तेदारों या मित्रों के यहां मिलने जाने से पहले कुछ सामान हम साथ ले जाने के लिए खरीद लेते हैं और यह भी जेहन में रखते हैं कि अगर उनके घर में बच्चे हों तो भेंट का स्वरूप हम क्या रखें। पुराने दिनों में गांव में यह परिपाटी हुआ करती थी कि किसी रिश्तेदार के यहां कोई महिला या बच्चे या फिर अन्य सदस्य साथ आते थे, तो उनकी विदाई से पहले उनके लिए खास कपड़े खरीदे जाते थे। बगैर नए कपड़ों के उन्हें विदा नहीं किया जाता था। यह एक तरह से सम्मान से भी जुड़ी बात होती थी। हमारे समाज में भेंट का एक स्वरूप और रिवाज यह भी है कि मान लीजिए कि हम किसी बर्तन में अपने जानने वाले को कुछ पकवान देते हैं और यह मानकर कि वह बर्तन हमें पकवान खाली कर वापस कर दिया जाएगा। मगर ऐसा अमूमन होता नहीं है कि वह बर्तन हमें खाली अवस्था में मिले। बदले में हमें यह बर्तन कुछ सामान से भरा हुआ ही मिलता है। अब यह रिवाज हमें किसी किताब में पढ़ाई नहीं गई है, न ही स्कूलों में भेंट संबंधी किसी अध्याय को शामिल किया गया है, लेकिन हमारे सामाजिक ताने-बाने में यह चीज गहराई से रम गई है कि हम इस परंपरा का पालन जरूर करते हैं।

वास्तव में भेंट किसी अवसर विशेष में बंधा नहीं होता है, न ही इसकी कोई सीमा तय है। अब किसी के यहां किसी दूर प्रदेश से कोई अपना मिलने आता है, तो हम शहर विशेष की कोई खास और प्रसिद्ध चीज उन्हें भेंट करते हैं और वापसी की यात्रा के समय यह भी ध्यान में रखते हैं कि यात्रा में उन्हें किसी जरूरी सामान की कमी न हो। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम हर संभव छोटी-मोटी चीजों से उनका थैला भर देते हैं। ऐसे में मेहमान को सौंपे गए ये सामान भी भेंट की श्रेणी में ही माने जाते हैं। साथ जाने वाले ये भेंट हमारे एहसास को भी साथ-साथ लिए चलते हैं।

इसके अलावा, हम जब कभी नई जगह पर सैर-सपाटे के लिए निकलते हैं, तो वहां के प्रसिद्ध खान-पान, पहनावे, उपयोग की चीजें भी अपने मुताबिक खरीदते हैं, पर हमारी यह खरीद स्वयं तक सीमित नहीं होती। हम अपने परिवारजनों, मित्रों आदि के लिए भी खरीदारी करते हैं। ऐसे में कई बार हमारा सामान रखने का थैला भी हमारे ढोने की क्षमता से बाहर हो जाता है, पर हम इस वजन की परवाह ही कब करते हैं। भेंट किए जाने वाले ऐसे उपहारों में हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, जो हमारे सामान के वजन को कम कर देती हैं या इसे साथ ले जाने की हमारी क्षमता को बढ़ा देती हैं। एक बात और कहा जा सकता है कि इन वस्तुओं को सही सलामत ले जाने की जितनी फिक्र हमें होती है। यह साथ ले जाने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कोई और नहीं।

खुद से खरीदे गए उपहार की बात ही अलग होती है। इसमें हम धन से अधिक किसी के लिए अपने समय और विवेक को समर्पित करते हैं। उपहार अपेक्षाओं से परे भी होते हैं और अमूमन आश्चर्यजनक सुखद अनुभव भी दे जाते हैं। हम किसी खास व्यक्ति को ही उपहार देना पसंद करते हैं और वह भी उनसे कुछ पाने की इच्छा के बगैर। पर हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी अति विशेष क्षण आते हैं, जब हमारे द्वारा दिए गए उपहार के बदले हमें एक अलग रूप में इसी तरह कुछ नवाजा जाता है, तो यह स्वयं में एक पूर्णता के भाव का सृजन करता है, जिसे शब्दों में बयां करना किसी दौर में संभव नहीं होता है। ऐसे क्षण जीवन के विशेष पल के रूप में याद की तरह बस जाते हैं और उम्र भर के लिए घर कर जाते हैं। इस तरह से मानव जीवन में उपहार का सरोकार समय और किसी भी मोल से परे है। बंधनों को मजबूत करते उपहार प्राचीन समाज से लेकर कारपोरेट जगत रूपी समाज में भी उतने ही प्रचलित और आपसी समन्वय को बेहतर करने के माध्यम हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **हम किसी खास व्यक्ति को ही उपहार देना पसंद करते हैं और वह भी उनसे कुछ पाने की इच्छा के बगैर। पर हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी विशेष क्षण आते हैं, जब हमारे उपहार के बदले हमें एक अलग रूप में इसी तरह कुछ नवाजा जाता है, तो यह स्वयं में एक पूर्णता के भाव का सृजन करता है, जिसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं होता है।**

शिक्षा के नाम पर

फरीदाबाद में चार वर्ष की मासूम बच्ची की हत्या उस भयावह मानसिकता का आईना है जो आज हमारे समाज में 'अनुशासन' और 'सफलता' के नाम पर पनप रही है। पढ़ाई में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने पर बेटी को इस हद तक पीटना कि उसकी जान चली जाए, यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम शिक्षा को संवेदनशीलता से नहीं, बल्कि हिंसा और भय से जोड़ चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसी मानसिकता अपवाद नहीं रह गई है। घरों में बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि असफलता ठीक नहीं और इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह भय धीरे-धीरे बच्चों के मन में स्थायी तनाव बन जाता है। जब यही बच्चे आगे चल कर प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में उतरते हैं, तो असफलता का डर उन्हें भीतर से तोड़ देता है। कई मामलों में यही डर आत्महत्या जैसे भयावह कदम की ओर ले जाता है। यदि अभिभावक ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा डर बन जाएंगे, तो उनसे सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? फरीदाबाद की घटना हमें वक्त रहते संभलने और बच्चों के पति संवदेनशीलता बरतने की चेतावनी देती है।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

मांझे के जोखिम

पिछले कुछ वर्षों से चीनी मांझे का प्रचलन बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि इस मांझे से कई बार हादसे हो चुके हैं। कई लोगों की जान तक जा चुकी है। शासन को इस मांझे की बिक्री करने और खरीदने वालों पर नकेल कसनी चाहिए। जब यह प्रतिबंधित है, तो चोरी-छिपे ऊंचे दाम पर क्यों और किस तरह बेचा या खरीदी जा रहा है। यह प्रशासन की विफलता है। इससे आसमान में उड़ते परिंदे तक घायल हो रहे हैं। सवाल है कि इन सब परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है। पतंगबाजों को भी यह बात समझाने की जरूरत है कि वे गैर इरादतन अपराध में फंस रहे हैं। पहले भी बच्चे और जवान मकर क्रांति पर्व के दो महीने पहले से ही खास डोर और पतंगें लेकर घर की छतों पर चढ़ कर या खुले में पतंग उड़ाते हुए आनंदित होते थे, लेकिन मजाल है कि उन धागों से किसी परिंदे का पंख कटा हो या कोई व्यक्ति जख्मी हुआ हो।

– प्रेमनारायण पोरवाल, उज्जैन

खेल पर सियासत

बांग्लादेश का अस्तित्व भारत के ऐतिहासिक सहयोग और बलिदान का परिणाम है। वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश को राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बावजूद आज बांग्लादेश की नीतियों में भारत के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाई देती। चिंताजनक यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लगातार हो रहे अत्याचार मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। धर्म के आधार पर हिंसा और भेदभाव किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते। खेल जैसे सौहार्द और मैत्री के माध्यम को राजनीति का शिकार बनाना बांग्लादेश की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। भारत ने सदैव पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का मार्ग अपनाया है। हमें बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए रखनी होगी।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

साझेदारी का विस्तार

'सहयोग की राह' (संपादकीय, 27 जनवरी) पढ़ा। यह नए भारत की बदलती तस्वीर पर सार्थक टिप्पणी है। बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता केवल आर्थिक करार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है। यह समझौता ऐसे समय आकार ले रहा है, जब संरक्षणवादी नीतियों और शुल्क संघर्ष ने वैश्विक व्यापार को अस्थिर किया है। अमेरिका की सख्त शुल्क नीति के बीच यूरोपीय संघ भारत के लिए एक भरोसेमंद और विविधतापूर्ण बाजार बन सकता है। रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग से दोनों पक्षों की रणनीतिक विश्वसनीयता बढ़ेगी, जबकि वस्त्र, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। भारतीय पेशेवरों की आवाजाही सुगम होने से मानव संसाधन सहयोग भी मजबूत होगा।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

तथ्य

भारत के ब्लू-कालर भर्ती क्षेत्र में औपचारिक डिग्री की तुलना में व्यावहारिक कौशल को प्राथमिकता दी जा रही है। अब नियोक्ता औपचारिक शिक्षा या डिग्री के बजाय व्यावहारिक कौशल, काम करने की तत्परता और आन-फील्ड अनुभव को अधिक तरजीह दे रहे हैं। हाल ही में जारी एक रपट के अनुसार, कई प्रमुख क्षेत्रों में अब बिना किसी शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। भर्ती के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ब्लू-कालर नौकरियों का सृजन अब केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रह गया है। वर्तमान में दिल्ली 26 फीसद के साथ नौकरी के विज्ञापनों में सबसे आगे है, लेकिन मांग अब तेजी से टियर-दो और टियर-तीन शहरों की ओर बढ़ रही है।

इग्नू ने पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और आनलाइन माध्यम से संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने के इच्छुक छात्र 31 जनवरी 2026 तक पुनः पंजीकरण कर सकते हैं। पहले यह अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने आवेदन की समय-सीमा आगे बढ़ा दी है। पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी है। उम्मीदवारों को ओडीएल और आनलाइन कार्यक्रमों के लिए आवेदन करते समय 300 रुपए का पुनः पंजीकरण शुल्क आनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

सूचनापट्ट

एनसीएचएम जेईई

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने होटल प्रबंधन संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एनसीएचएम जेईई) 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मार्च 2026 कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब इस तिथि तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी है। परीक्षा 25 अप्रैल 2026 को देशभर के 120 परीक्षा नगरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार इस प्रकार है: सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग: 1000 रुपए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 700 रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और थर्ड जेंडर: 450 रुपए। भुगतान केवल आनलाइन माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे, जो पांच अलग-अलग खंडों में विभाजित होंगे।

अंतिम तिथि : 25 मार्च, 2026

पीएचडी

भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ ने 2026 शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने प्रबंधन में डाक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पूर्णकालिक कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्नत प्रबंधन अनुसंधान के लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करना है। लगभग 4.5 वर्षों में पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया, यह कार्यक्रम डिग्री के लिए आवश्यक मुख्य शोध गतिविधियों के अलावा, अकादमिक, कापोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक संस्थानों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए शोध स्नातकों को तैयार करता है। इच्छुक आवेदकों को जल्द से जल्द आवेदन करने और सभी पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया आईआईएम लखनऊ पीएचडी कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

अंतिम तिथि : 16 फरवरी, 2026

वायुसेना अग्निवीर

भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत अविवाहित पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को चार वर्ष तक सेवा का अवसर मिलेगा। आवेदन केवल वायु सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट के माध्यम से किए जाएंगे। पंजीकरण 12 जनवरी से शुरू होकर एक फरवरी 2026 को रात ग्यारह बजे तक चलेगा। आनलाइन परीक्षा 30 और 31 मार्च को होगी। पात्रता के अनुसार अभ्यर्थी का जन्म एक जनवरी 2006 से एक जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। अधिकतम आयु इक्कीस वर्ष निर्धारित है। विज्ञान वर्ग से बारहवीं उत्तीर्ण तथा अन्य निर्धारित योग्यताएं आवश्यक हैं। चयन तीन चरणों में होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभ में तीस हजार रुपए मासिक वेतन और चार वर्ष बाद सेवा निधि दी जाएगी। चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीर को लगभग दस लाख चार हजार रुपये का सेवा निधि पैकेज एकमुश्त दिया जाएगा। यह राशि पूरी तरह कर मुक्त होगी और इसमें सरकार व अभ्यर्थी दोनों का योगदान शामिल होगा। सेवा समाप्ति के बाद अग्निवीर को सेवा अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। भारतीय वायु सेना में हर बैच से पच्चीस फीसद तक अग्निवीरों को प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर स्थायी कैडर में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

अंतिम तिथि : 1 फरवरी, 2026

रेलवे ग्रुप डी भर्ती

रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती 2026 का नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से देशभर में लगभग 22000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह अवसर दसवीं पास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से योग्य अभ्यर्थियों के लिए है। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी 2026 तक चलेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सकीय जांच के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 23500 रुपए मासिक वेतन, भत्ते, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार की संभावना और भविष्य में पदोन्नति का अवसर मिलेगा। ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क वर्ग के आधार पर निर्धारित किया गया है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क पांच सौ रुपए रखा गया है। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क दो सौ पचास रुपए निर्धारित है।

अंतिम तिथि : 20 फरवरी, 2026

फुटवियर में नई मांगों से बढ़ते अवसर

विशेषज्ञ की कलम से

भारत आज विश्व के प्रमुख जूता उत्पादक देशों में शामिल है और इस क्षेत्र में आने वाले वर्षों में तेज विस्तार की संभावना है। बदलती जीवनशैली, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और खेल गतिविधियों में वृद्धि के कारण जूतों की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2030 तक इस उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि (करीब 15%) का अनुमान है, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं। भारतीय फुटवियर उद्योग में अब आधुनिक तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। उत्पादन प्रक्रिया में स्वचालित मशीनों, बुद्धिमान तकनीक और डिजिटल डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर हुई है और समय व लागत की बचत भी हो रही है। जूतों के डिजाइन, फिटिंग और निर्माण में नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र अधिक तकनीक आधारित बनता जा रहा है।

भारतीय फुटवियर इंडस्ट्री में लगभग 45 लाख लोग काम करते हैं। काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट की एक रपट के अनुसार भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात में लगभग 25 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की। इसका लक्ष्य 2030 तक कुल कारोबार को 39 अरब डालर तक पहुंचाना है। रपट के अनुसार, भारतीय फुटवियर कंपनियों के साथ साझेदारी के लिए चीनी निवेशकों की रुचि भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे इस क्षेत्र की भविष्य की संभावनाएं और मजबूत हो रही हैं। वहीं देश में नाइकी, प्यूमा, एडिडास, क्राक्स और स्केचर्स जैसी कंपनियां दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। एक रपट की मानें, तो 2027 तक सिर्फ तमिलनाडु में इससे संबंधित लगभग 1,35,000 कुशल कामगारों की जरूरत होगी, जिनमें से करीब 10% तकनीकी और प्रबंधन पदों के लिए होंगे। भारतीय फुटवियर इंडस्ट्री में संभावनाएं तो है, लेकिन रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता है। आर्थोपेडिक फुटवियर, स्मार्ट फुटवियर की भरपूर मांग है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीपल असिस्टिंग फुटवियर वूमन सेफ्टी फुटवियर, जीपीएस ट्रैकिंग वाले किड्स स्मार्ट फुटवियर डेवलप कर मार्केट में मौजूद गैप को भरा जा सकता है।

एआइ व डिजिटल भूमिकाएं

एआइ फिटिंग स्पेशलिस्ट : कस्टमाइज्ड जूतों के लिए पैर के आकार और आराम के हिसाब से जूतों के डिजाइन और फिटिंग सुनिश्चित करना। बायोमेकेनिक्स और स्पोर्ट्स साइंस में दक्ष हों।

प्रमुख संस्थान और पाठ्यक्रम

- नैशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद -बीडेस, एमडेस (एनआइडी डीएटी प्रवेश परीक्षा से प्रवेश)
- फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा - बीडेस, एमडेस
- सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआइ), चेन्नई व आगरा - पोस्ट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स।
- नैशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी, दिल्ली, बीडेस इन लेदर डिजाइन
- दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा - फुटवियर टेक्नोलाजी में बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट

आइटीआइ छात्रों के लिए मौके

नैशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआइटीएस) करने से टीचर या इंस्ट्रक्टर बनकर सरकारी या प्राइवेट आइटीआइ में भी करिअर बना सकते हैं। फुटवियर मेकर, मशीन आपरेटर, फिटर, पैकिंग स्टाफ, गुणवत्ता आदि में तकनीकी प्रशिक्षण के काम आती है।

योग्यता

10वीं, 12वीं, डिप्लोमा या ग्रेजुएट छात्र फुटवियर टेक्नोलाजी और डिजाइन से जुड़े लांग-टर्म, मीडियम-टर्म और शार्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं। छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान इंडस्ट्री का अनुभव और प्लेसमेंट के मौके भी मिलते हैं, खासकर सीएफटीआइ जैसे संस्थानों में, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय निर्माताओं के साथ साझेदारी में हैं।

3डी प्रिंटिंग इंजीनियर: कस्टम सोल और जूते बनाने के लिए 3डी प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल । मैकेनिकल / फुटवियर टेक्नोलाजी में विशेषज्ञ की मांग।

वर्चुअल ट्राय-आन डिजाइनर : आनलाइन जूतों का डिजिटल प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। डिजाइन और डिजिटल टेक्नोलाजी में कुशल।

स्मार्ट सेंसर फुटवियर रिसर्चर: स्मार्ट जूतों में सेंसर और बायोमेकेनिकल डाटा जोड़ते हैं। बायोमेकेनिक्स व फिजियोथेरेपी के जानकार।

वेतन

फुटवियर डिजाइनर शुरुआत में सालाना 2 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, जो अनुभव के बाद 10 लाख हो सकता है। फैक्टरी/प्रोडक्शन के पदों पर 15,000 रुपए प्रति माह से शुरुआत संभव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्रबंधन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सप्लाई चेन में वेतन चार लाख सालाना से शुरू होता है।

- आशीष झा, *करिअर परामर्शदाता*

जानें-सीखें

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत शीर्ष-5 में, जानिए वजह

दावोस में हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छिड़ गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत शीर्ष श्रेणी के देशों में शामिल नहीं है, बल्कि उसे दूसरे स्तर के देशों के समूह में रखा जाना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद भारत सरकार की ओर से कड़ा प्रतिवाद सामने आया। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैयारी और उसके वास्तविक उपयोग के मामले में पहले समूह में आता है और विश्व में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भारत, अमेरिका और चीन के बाद खड़ा है।

वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक में देशों का मूल्यांकन कई आधारों पर किया जाता है। इनमें शोध और विकास, प्रतिभा और कौशल, निवेश और नवाचार, संगणनात्मक ढांचा, सरकारी नीतियां और तकनीक को अपनाने की गति शामिल हैं। इन मानकों पर भारत शीर्ष तीन देशों में जगह बनाने में सफल रहा है। यह इस बात का संकेत है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने तकनीकी विकास की मजबूत नींव तैयार की है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल सूचकांक यह दर्शाता है कि किसी देश की कार्यशक्ति में यह तकनीक कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। भारत में यह कौशल अब केवल बड़ी कंपनियों या अनुसंधान केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और नवाचार से जुड़े युवाओं के बीच तेजी से फैल चुका है। खास बात यह है कि कामकाजी महिलाओं में इसका प्रसार वैश्विक औसत से 1.7 गुना अधिक है, जो भारत की सामाजिक और तकनीकी शक्ति को दर्शाता है।

वैश्विक सूचकांक में अमेरिका 78.6 के साथ पहले, चीन 36.95 के साथ दूसरे और भारत 21.59 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं कौशल सूचकांक में भारत 2.8 अंकों के साथ आगे है, जबकि अमेरिका और जर्मनी उससे पीछे हैं। इससे स्पष्ट है कि केवल शोध और महंगे संसाधनों के बजाय उपयोग के आधार पर भारत की स्थिति मजबूत है।

दो स्तरों में बंटी वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तस्वीर

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में देशों को दो समूहों में बांटा है। पहले समूह में वे देश हैं, जहां अनुसंधान, सुपरकंप्यूटर और अत्याधुनिक ढांचा अधिक है, जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और यूरोप। दूसरे समूह में वे देश हैं, जहां तकनीक का व्यापक उपयोग आम लोगों के जीवन में हो रहा है। भारत इसी समूह में आता है, जहां सरकारी योजनाओं, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, कृषि और सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। यही व्यापक उपयोग भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

युवा शक्ति डेस्क

आक्रोश

नई दिल्ली में बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के विद्यार्थियों ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि इन नियमों से परिसरों में अराजकता फैल सकती है।

काम पूरा करना ही नहीं, बल्कि उसे यादगार बनाना है असली कला

परामर्श

क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको लंबे समय तक याद रखें और आपकी पहचान एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में बने? यदि हां, तो इसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। कार्यस्थल पर कई लोग केवल अपना निर्धारित काम पूरा करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे आगे बढ़कर सोचते हैं। वे न केवल अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथियों की मदद करते हैं, नई बातें सीखते हैं और हर अवसर को स्वयं को निखारने का माध्यम बनाते हैं। ऐसे लोग धीरे-धीरे सभी की नजर में आ जाते हैं और एक जिम्मेदार व भरोसेमंद पेशेवर के रूप में पहचाने जाते हैं।

इस यात्रा की पहली सीढ़ी है आत्मचिंतन। थोड़ी देर रुकिए और अपने जीवन पर ईमानदारी से विचार कीजिए। खुद से पूछिए कि आप वास्तव में क्या पाना चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को केवल मन में न रखें, बल्कि उन्हें लिखित रूप दें। जब आप अपने सपनों और उद्देश्यों को कागज पर उतारते हैं, तो वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और उन्हें पाने का रास्ता भी समझ में आने लगता है।

आगे बढ़ने के लिए दूसरों के अनुभवों और राय को सुनना भी उतना ही जरूरी है। अपने भरोसेमंद सहकर्मियों या वरिष्ठों से यह जानने की कोशिश करें कि वे आपके काम और व्यवहार को कैसे देखते हैं। उनकी सच्ची राय आपको अपनी अच्छाइयों और सुधार की जरूरत वाले पहलुओं दोनों से परिचित कराएगी। साथ ही, यह याद रखें कि सफलता अकेले नहीं मिलती। अपनी टीम को साथ लेकर चलना, उनके प्रयासों की सराहना करना और जरूरत के समय सहयोग देना आपको एक बेहतर इंसान और नेतृत्वकर्ता बनाता है।

जेईई एडवांस परीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी

जरूरी जानकारी

केंद्र सरकार देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस की परीक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ-साथ योग्यता आधारित प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी संयुक्त प्रवेश बोर्ड द्वारा की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है, जो छह माह के भीतर परीक्षा सुधार की विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी। इसके बाद प्रायोगिक परिणामों और उनके विश्लेषण के आधार पर इस योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

नई व्यवस्था में जेईई एडवांस परीक्षा वर्ष में एक बार के स्थान पर दो से चार बार आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। परीक्षा कई दिनों तक अलग-अलग समय खंडों में कराई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इससे एक ही दिन में परीक्षा देने से होने वाला मानसिक दबाव कम होगा।

योग्यता आधारित प्रश्नों के शामिल होने से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित से जुड़े प्रश्नों की संख्या घटेगी। इन प्रश्नों का उद्देश्य विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता, गणनात्मक समझ और समस्या समाधान की योग्यता को परखना है। इससे रटंत ज्ञान के बजाय समझ और विवेक पर आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा मिलेगा।

नई व्यवस्था में जेईई एडवांस परीक्षा वर्ष में एक बार के स्थान पर दो से चार बार आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। परीक्षा कई दिनों तक अलग-अलग समय खंडों में कराई जाएगी।

इस बदलाव की आवश्यकता नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें परीक्षा से जुड़े मानसिक तनाव को कम करने पर विशेष बल दिया गया है। सीमित सीटों और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण विद्यार्थी और अभिभावक भारी दबाव में रहते हैं। कम उम्र से ही अतिरिक्त पढ़ाई का बोझ बच्चों पर डाल दिया जाता है, जिससे उनका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा प्रणाली में सुधार कर विद्यार्थियों का तनाव कम करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

फेलोशिप प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल खुला, दो साल का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड (एनबीईएमएस) ने 14 जनवरी 2026 को फेलोशिप प्रवेश परीक्षा (एफईटी) 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस परीक्षा के माध्यम से वर्ष 2025 सत्र के लिए फेलो आफ नेशनल बोर्ड (एफएनबी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 शाम 5:00 बजे से शुरू होकर 3 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस फेलोशिप में उम्मीदवारों को प्रतिमाह लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक वजीफा मिलेगा। वजीफे की राशि एनबीईएमएस के नियमों के अनुसार परिवर्तित भी की जा सकती है।

प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होगी और यह पूर्णकालिक रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार अस्पताल में काम करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे, साथ ही क्लास, रिकार्ड रखना और समय-समय पर टेस्ट भी होंगे। एफईटी-2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के नागरिक या ओसीआइ कार्डधारी होना चाहिए। एफपीआइएस पाठ्यक्रम के लिए विदेशी नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास चयनित फेलोशिप के लिए एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच, डीएनबी या डीआरएनबी जैसी मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र में आपरेशन सिंदूर को लेकर कहा

विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य व पराक्रम देखा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा जब देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके साथ ही कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा।

संसद के बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है। आपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को

संसद के बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है।

स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है।

मुर्मू ने विकसित भारत का संकल्प, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर, सांसदों से एकमत होने का आ''ान करते हुए कहा, 'विभिन्न मतों, अलग-अलग विचारों के बीच, यह सर्वमान्य है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है।' उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि इन सभी नेताओं का यह मत रहा कि लोकतंत्र में विषयों पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे हैं। हमारे संविधान की भावना भी यही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, किरेन रिजीजू सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्री, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा सहित विपक्षी दलों के कई नेता तथा सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विभिन्न सांसद मौजूद थे।

मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2026 के साथ ही हमारा देश इस सदी के दूसरे पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए, सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार हैं। सुरक्षाबलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है और माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर आठ जिलों तक सिमट गई है। यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए विनियम पर कुछ वर्गों की आपत्तियों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है तथा 'सबका साथ, सबका विकास' का दृष्टिकोण हर नागरिक के जीवन में बदलाव ला रहा है।

विपक्षी दलों ने जी राम जी अधिनियम का विरोध किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

विपक्षी सदस्यों ने बुधवार को संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के दौरान 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' का विरोध करते हुए नारेबाजी की, जिसकी सरकार ने कड़ी निंदा की और कहा कि विपक्ष को इस आचरण के लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजीजू ने विपक्ष को निशाने पर लिया।

रिजीजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों ने अपने आचरण से देश को शर्मिंदा किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नारे लगाकर सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबासाहेब भीमराव आंबडेकर, बिरसा मुंडा, भूपेन हजारिका, गुरु तेग बहादुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भी अपमान किया। नड्डा ने कहा कि जिस तरह से इन लोगों ने संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया, वह बेहद निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वह पर्याप्त नहीं है। उन्हें संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने जैसे ही संसद के संयुक्त सत्र में अपना संबोधन शुरू किया, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम' के खिलाफ नारे लगाए और इसे वापस लेने की मांग की। इसके बाद जब अपने अभिभाषण में मुर्मू ने नए कानून का उल्लेख किया तो विपक्षी सदस्य फिर से नारे लगाने लगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे सहित विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और कानून के प्रति विरोध जताया।

राष्ट्रपति मुर्मू अपने संबोधन के दौरान एक पल के लिए रुकीं, हालांकि फिर उन्होंने संबोधन जारी रखा। विपक्ष के विरोध पर नड्डा ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने आदतन संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया, वह पूरी तरह से निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जब राष्ट्रपति अपने संबोधन में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मनाने और बंकिम बाबू के कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थीं, तो कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन ने हंगामा खड़ा कर दिया और नारे लगाने लगे।

इंदौर में दूषित पेयजल से 29वीं मौत का दावा

बेटे ने कहा, पिता को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस तक नहीं भेजी गई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों ने बुधवार को कहा कि उसे दूषित पेयजल से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप के कारण जान गंवानी पड़ी है। ताजा मामले को मिलाकर स्थानीय लोगों ने महीना भर पहले फैले इस प्रकोप में अब तक कुल 29 लोगों की मौत का दावा किया है।

हालांकि, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में 27 जनवरी (मंगलवार) को राज्य सरकार की पेश 'मृत्यु लेखा' रपट में संभावना जताई गई है कि भागीरथपुरा में 16 लोगों की मौत का संबंध इस इलाके में दूषित पेयजल के कारण फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से हो सकता है। परिजनों के मुताबिक भागीरथपुरा में रहने वाले खूबचंद बंधैया (62) ने उल्टी-दस्त के इलाज के दौरान अपने घर में मंगलवार को आखिरी सांस ली। उनका बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। बंधैया के बेटे रोहित ने बताया कि दूषित पानी पीने के कारण मेरे पिता को पिछले 15-20 दिन से उल्टी-दस्त की शिकायत थी। हम उन्हें भागीरथपुरा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां उन्हें दवाइयां दी गई थीं। हमारे घर में चल रहे इलाज के दौरान उनकी मंगलवार को मृत्यु हो गई।

रोहित ने दावा किया कि उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों से कहा था कि उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन उनके घर एंबुलेंस नहीं भेजी गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भागीरथपुरा की पेयजल त्रासदी की न्यायिक जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग गठित किया है। उच्च न्यायालय ने इस आयोग को न्यायिक जांच की कार्यवाही शुरू होने की तारीख से चार हफ्ते के भीतर अंतरिम रपट पेश करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से उल्टी-दस्त का प्रकोप दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, भागीरथपुरा में 51 नलकूपों में दूषित पानी मिला और पानी की जांच रपट में इसमें 'ई-कोलाई' जीवाणु के बारे में पता चला।

मौसम

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बुधवार को बर्फबारी के बाद गंगोत्री राजमार्ग पर जमी बर्फ को हटाते कर्मचारी।

मतदाताओं के नाम जोड़ना और हटाना सूची संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा : कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण का हिस्सा है। न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली 19 याचिकाओं के एक समूह पर अंतिम सुनवाई फिर शुरू की।

आधार कार्ड को पहचान के एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जालसाजी की आशंका मात्र 12 अंकों वाले बायोमेट्रिक पहचान पत्र को खारिज करने का आधार नहीं बन सकती। यह देखते हुए कि पासपोर्ट भी सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाली निजी एजंसियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि यदि कोई दस्तावेज कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे जारी करने में एक निजी संस्था शामिल है। जब याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने मतदाता सूची से नामों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने का आरोप लगाया, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नामों को जोड़ना और हटाना मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने 12 अगस्त को इस मामले में अंतिम बहस शुरू की थी, जिसमें उसने कहा था कि मतदाता सूची में नामों को शामिल करना या हटाना निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है। आयोग ने एसआइआर कवायद का बचाव करते हुए कहा है कि आधार और मतदाता पहचान पत्रों को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई घटक दलों के नेताओं ने बुधवार को संसद के बजट सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कार्यालय में हुई बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, द्रमुक नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान और कुछ अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दल मनरेगा, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर), विदेश नीति और कुछ अन्य विषय उठाएंगे तथा सरकार से जवाब मांगेंगे।

विपक्षी दल मनरेगा, विशेष गहन पुनरीक्षण, विदेश नीति और कुछ अन्य विषय उठाएंगे तथा सरकार से जवाब मांगेंगे।

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर दो अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट एक फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। इसी चरण में केंद्रीय बजट पर भी चर्चा होगी। इसके बाद सदन की बैठक दोबारा नौ मार्च को शुरू होगी और इस दूसरे चरण की समाप्ति के लिए दो अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है।

भारत-यूरोपीय संघ समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

युवाओं के लिए लाखों अवसर पैदा होंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत द्वारा कई देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और एक दिन पहले दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते से लाखों भारतीय युवाओं के लिए अवसर के अनगिनत द्वार खुलेंगे।

उन्होंने दिल्ली छावनी में वार्षिक 'राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत के युवाओं को बहुत भरोसे से देख रही है और इसका कारण कौशल और संस्कार है। मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था, 'यही समय है, सही समय है'। देश के युवाओं के लिए यह अधिकतम अवसरों का समय है। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को इस अवधि का 'अधिक से अधिक लाभ' मिले।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका एक उदाहरण आपने कल ही देखा। भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। इससे पहले, भारत ने ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और मारीशस जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन सभी से हमारे लाखों युवाओं के लिए अवसर के अनगिनत द्वार खुलेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक अभिभाषण ने हाल के समय में भारत की उल्लेखनीय विकास यात्रा पर प्रकाश डाला और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाई। मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई।

मोदी ने कहा कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के सदस्यों को दिए गए राष्ट्रपति के प्रेरक अभिभाषण के साथ हुई। उन्होंने कहा कि भारत की संसदीय परंपराओं में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह उस नीतिगत दिशा और सामूहिक संकल्प पर प्रकाश डालता है, जो आने वाले महीनों में राष्ट्र की विकास यात्रा का मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज का अभिभाषण व्यापक और ज्ञानवर्धक था। इसने हाल के समय में भारत की उल्लेखनीय विकास यात्रा पर प्रकाश डाला और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा भी दिखाई।

पेज 1 का बाकी

परिवार संभालेगा या मौका मिलेगा किसी वफादार को

गठबंधन में शामिल होने के कुछ ही समय बाद हुआ। उनका छह साल का कार्यकाल अप्रैल 2024 में शुरू हुआ। हालांकि, उनमें विधायी या प्रशासनिक अनुभव की कमी है। पार्टी के अंदर, उन्हें संगठन को स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम नेता के बजाय पवार नाम की एक प्रतीकात्मक संरक्षक के रूप में ज्यादा देखा जाता है। पार्थ पवार (बेटे) पार्थ को 2019 के लोकसभा चुनावों में मावल से मैदान में उतारा गया था, तब उन्हें तीसरी पीढ़ी के पवार के तौर पर पेश किया गया था। यह उसी समय हुआ जब शरद पवार ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था।

उनकी उम्मीदवारी को बड़े पैमाने पर अजित पवार की परिवार में अपनी राजनीतिक विरासत स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। पार्थ की हार और उसके बाद सक्रिय राजनीति से उनके पीछे हटने से वह योजना रुक गई। अपने चचेरे भाई रोहित पवार के उलट, जिन्होंने विधानसभा राजनीति के जरिए अपना आधार बनाया, पार्थ ने कोई चुनावी नेटवर्क या कैडर प्रशंसक नहीं बनाए हैं। हालांकि, उनका उपनाम उन्हें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखता है, लेकिन चुनावी सफलता की कमी उन्हें तुरंत उत्तराधिकारी के बजाय लंबे समय का दावेदार बनाती है।दोस्त प्रफुल्ल पटेल : वे राकांपा के सबसे अनुभवी रणनीतिकार और इसके संस्थापकों में से एक हैं। पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और दिल्ली में शरद पवार के लंबे समय से बातचीत करने वाले, पटेल 2023 के बंटवारे के दौरान अजीत पवार के खेमे में चले गए, जिससे गुट को वैधता और संगठनात्मक गहराई मिली। उनकी ताकत गठबंधन प्रबंधन, राष्ट्रीय सत्ता केंद्रों तक पहुंच और पार्टी मशीनरी की गहरी जानकारी में है। उन्हें एक ऐसे संकटमोचक के रूप में व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है जो संकट के समय पार्टी को एकजुट रख सकते हैं। हालांकि, पटेल कभी भी बड़े जननेता नहीं रहे हैं और महाराष्ट्र में उनका कोई मजबूत चुनावी आधार नहीं है। उनका नेतृत्व प्रबंकीय होगी, जिससे वह लंबे समय की राजनीतिक योजना के बजाय किसी स्थिति को संभालने या अंतरिम भूमिका के लिए अधिक उपयुक्त हैं।सुनील तटकरे : रायगढ़ में जिला राजनीति से ऊपर उठकर, उन्होंने सहकारी क्षेत्र और स्थानीय निकायों के जरिए कोंकण में राकांपा का सबसे मजबूत आधार बनाया। मंत्री के तौर पर, उन्होंने जल संसाधन और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय संभाले, जिससे उन्हें पूरे राज्य का प्रशासनिक अनुभव मिला। 2023 में बंटवारे के बाद, वे अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के महाराष्ट्र ईकाई के अध्यक्ष बने, जिससे उन्हें पार्टी संगठन की जिम्मेदारी मिली। उनकी मुख्य ताकत कैडर और जिला-स्तरीय मशीनरी पर उनके नियंत्रण में है, जो उन्हें एक संगठनात्मक नेता बनाती है। हालांकि, उनका राजनीतिक प्रभाव कोंकण तक ही सीमित है और उनमें अजीत पवार जैसी पूरे राज्य में प्रभाव की कमी है।राकांपा के क्षेत्रीय नेताधनंजय मुंडे : वे अजित पवार के खेमे के उन कुछ नेताओं में से एक हैं जिनकी लोगों के बीच अच्छी पकड़ है।

अजित पवार के करीबी होने के बावजूद, उनके ओबीसी पृष्ठभूमि को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें ऐसी पार्टी में अधिक स्वीकार्यता मिलेगी, जिसे ज्यादातर मराठा वोट बैंक वाली पार्टी माना जाता है। एक क्षेत्रीय नेता जो ज्यादातर बीड तक ही सीमित हैं। उनके कई विवादों के कारण उनके लिए दावेदार बनना मुश्किल है। जनवरी 2025 में बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर हुए बड़े राजनीतिक हंगामे के बाद महाराष्ट्र सरकार से उनका इस्तीफा हुआ था। छगन भुजबल: महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ ओबीसी नेताओं में से एक छगन भुजबल की जड़ें शिवसेना और बाद में राकांपा से जुड़ी हैं। वे उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और पीडब्ल्यू व खाद्य, नागरिक आपूर्ति जैसे बड़े विभागों को संभाल चुके हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में समय बिताने और बाद में राजनीति में लौटने के बाद, उन्होंने पार्टी में फूट के बाद अजित पवार के गुट का साथ दिया। उनकी ताकत उत्तरी महाराष्ट्र में उनके वफादार ओबीसी वोट बैंक और उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव में है। हालांकि, उम्र और पिछले विवादों के कारण भविष्य के नेता के तौर पर उनकी अपील सीमित हो जाती है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत

जाना शुरू करता है। खराब मौसम, अस्थिर लैंडिंग पथ, या रनवे पर यातायात जैसी वजहों से सुरक्षित लैंडिंग पूरी नहीं होने की स्थिति में ऐसा किया जाता है। यह एक आपात स्थिति नहीं, बल्कि एक एहतियाती सुरक्षा कदम है।विमान संचालन की भाषा में ही, 'रीडबैक' एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया है, जिसमें पायलट एटीसी से मिले निर्देशों या संदेश को दोहराता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पायलट ने नियंत्रक के निर्देश ठीक ढंग से समझ लिए हैं।

नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने पुणे में पत्रकारों से कहा कि विमान खराब दृष्यता के बीच जमीन पर उतरने का प्रयास कर रहा था। नागर विमानन मंत्रालय के बयान में वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के लियरजेट 45 के दुर्घटनाग्रस्त होने से चंद मिनट पहले का विवरण दिया। इस दुर्घटना में विमान में सवार पवार समेत सभी पांच लोगों की मौत हो गई। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। वीएसआर वेंचर्स के बेड़े में सात लियरजेट 45 विमान (जिसमें यह दुर्घटनाग्रस्त विमान भी शामिल है), पांच एंबरर 135बीजे विमान, चार किंग एयर बी200 विमान और एक पिलाटस पीसी-12 विमान शामिल हैं। उड़ानों की निगरानी करने वाली 'फ्लाइट रडार' के अनुसार, विमान ने मुंबई से सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी और सुबह लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर यह रडार से गायब हो गया।

डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि विमान में पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी और एक परिचारिका, चालक दल के दो सदस्यों (कैप्टन और सह-पायलट) समेत पांच लोग सवार थे। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। विमान में सवार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा और दो बेटे पार्थ और जय हैं। सुनेत्रा राज्यसभा सदस्य हैं।

अजित पवार की अगुआई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए निकाय चुनाव में अपने चाचा शरद पवार की राकांपा (शरद गुट) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के विभिन्न दलों के कई अन्य नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। बारामती पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार के निधन को दुखद और अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जनवरी तक तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। गुरुवार को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

राकांपा के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह पूर्वाह्न 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। राकांपा (शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार बारामती हवाई अड्डे और मेडिकल कालेज पहुंचे, जहां पर दुर्घटनास्थल से अजित पवार के शव को लाया गया था। राकांपा के संस्थापक शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले अपने चचेरे भाई के निधन पर अत्यंत शोकाकुल दिखाई दीं।

एकजुट राकांपा से राजनीति में हो सकती थी हलचल

साक्षात्कार में कहा था कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं। दोनों राकांपा अब साथ हैं। हमारे परिवार में सभी तनाव खत्म हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में बात और आगे बढ़ी कि एकजुट राकांपा महाराष्ट्र में महायुति के तहत गठबंधन कर सकती है, जिसमें परिवार और गुटों के हितों को समायोजित करने के लिए एक सावधानी से संतुलित व्यवस्था होगी।

इसमें यह अटकल भी शामिल है कि शरद पवार के पौत्र रोहित पवार को राज्य सरकार में जगह मिल सकती है, जबकि अजित पवार की पत्नी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किसी भूमिका के लिए विचार किया जा सकता है। इस तरह के विलय के राष्ट्रीय नतीजे भी होते। 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में भाजपा को झटका लगने के बाद, पवार के दोनों गुटों के एक साथ आने से संसद में संख्या बढ़ सकती थी। आठ सांसदों के साथ, इस गठबंधन के पास भाजपा के महाराष्ट्र के सांसदों की संख्या से एक सांसद कम होता। राज्य में अजित पवार का संगठनात्मक नियंत्रण, उनके चाचा की बची हुई राष्ट्रीय पहचान के साथ मिलकर, सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक संभावित स्थिर शक्ति के रूप में देखा जा रहा था। अब यह पूरा राजनीतिक हिसाब-किताब गड़बड़ा गया है। दुख के अलावा, पवार की मौत से एक अहम शख्सियत खत्म हो गई, जिसे कई लोग भाजपा और पवार परिवार के कुछ हिस्सों के बीच और खुद राकांपा के दोनों गुटों के बीच एक पुल के तौर पर देखते थे। भले ही वह पुल कितना भी कमजोर क्यों न हो, उनके गुट के पास अधिक विधायी ताकत थी और सरकार में एक मजबूत जगह थी, जबकि शरद पवार के खेमे के पास प्रतीकात्मक अधिकार और एक अलग समर्थन आधार था।

अजित पवार के बिना, यह सवाल उठता है कि उनके गुट का नेतृत्व कौन करेगा, यह कितना एकजुट रहेगा, और क्या शरद पवार के गुट के साथ फिर से जुड़ने की गति बनी रहेगी। महाराष्ट्र के एक राजनेता ने कहा कि यह और भी तेज हो सकता है क्योंकि राकांपा को नेतृत्व संकट महसूस हो रहा है। पार्टी पवार परिवार से बहुत करीब से जुड़ी हुई है और पार्टी में अजित दादा की जगह लेने वाला कोई नहीं है। भाजपा और उसके महायुति सहयोगियों के लिए भी, यह घटना राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण राज्य में गठबंधन के गणित को जटिल बनाती है। अब वह अनिश्चितता, उत्तराधिकार के संघर्ष और नई बातचीत का रास्ता खोलता है। अजित पवार की मौत न केवल उनके समर्थकों के लिए एक व्यक्तिगत और संगठनात्मक नुकसान है। इसने एक राजनीतिक पुनर्गठन की दिशा को भी अचानक बदल दिया है जो आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की सत्ता संरचना को नया आकार दे सकता था।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पवार के निधन के बाद राकांपा में नेतृत्व का संकट गहरा सकता है, क्योंकि पार्टी में कोई स्पष्ट दूसरा चेहरा नहीं है। पवार की मौत से न सिर्फ राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में खालीपन पैदा हो गया है, बल्कि राकांपा के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है।

यूजीसी नियमों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी

किया। वकील ने कहा कि सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। मेरा मुकदमा 'राहुल दीवान एवं अन्य बनाम भारत सरकार' है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि खामियां दूर कर दी जाएं। हम इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 के तहत इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांगजन और महिलाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि नए नियमों में जाति-आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव तक सीमित कर दिया गया है। इन नियमों के खिलाफ कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जहां छात्र समूह और संगठन इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

राजहंस माझा निजला...

वाडवडिलांच्या नावे ओळखले जात असताना स्वतःच्या स्वतंत्र चेहऱ्याची आस प्रत्यक्षात आणणे अवघड. अजितदादा आता कोठे स्वतःचे नेतृत्वपीठ उभे करतील अशी शक्यता दिसत होती.

आता कोठे नेतृत्व फुलू लागेल असे वाटत असताना अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू हृदयास घरे पाडतो खरेच. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, आर. आर. पाटील अशा ऐन भरात असलेल्या नेत्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर आता महाराष्ट्राने आज अजित पवारांसारखा मोहरा गमावला. त्यांच्या निधनाने या राज्याचे काय आणि किती नुकसान होणार आहे याचा अंदाज येण्यास काही काळ निश्चित जावा लागेल हे मान्य. परंतु आज त्यांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा न घेणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल.

याचे कारण असे की केवळ शरद पवार यांचा पुतण्या इतकीच त्यांची ओळख नव्हती. ज्या घरात सुनील गावस्कर असतात, ज्या घरात अमिताभ बच्चन असतात आणि ज्या घरांत शरद पवार असतात त्या घरांतील पुढच्या पिढीस स्वतःची ओळख निर्माण करणे अशक्यप्राय, कमालीचे जीवघेणे ठरते. एक तर आपला समाज 'सांगे वडिलांची कीर्ती, तो एक मूर्ख' भले म्हणत असेल. पण हे या समाजाचे ग्रांथिक शहाणपण प्रत्यक्ष वर्तनात कधीही आढळत नाही. त्यामुळे रोहन गावस्कर, अभिषेक बच्चन वा अजित पवार यांना या समाजात त्यांच्या वाडवडिलांच्या नावेच ओळखले जाते. असे असताना स्वतःच्या स्वतंत्र चेहऱ्याची आस बाळगणे आणि ती प्रत्यक्षात आणणे ही बाब अत्यंत अवघड. अजितदादांनी हे अवघडलेपण नेहमीच अनुभवले आणि आता कोठे ते त्यातून बाहेर पडून स्वतःचे नेतृत्वपीठ उभे करतील अशी शक्यता दिसत होती. पण त्याआधीच ते गेले. फांदी फुटण्याची शक्यता दिसत असतानाच एखाद्या वृक्षाच्या मुळावर घाव घातला जावा, तसे हे. जे झाले ते अविश्वसनीयरीत्या दुर्दैवी.

राजकारण्यांचे वर्गीकरण दोन गटांत होते. एक केवळ राजकारणी आणि दुसरे काही एक लांबचे पाहणारे, स्वतःचा अभ्यास असणारे, प्रशासन समजावून घेणारे, विषयाचा अभ्यास करणारे असतात. अजितदादा कोणत्या वर्गातील या प्रश्नाचे उत्तर त्यांचे कडवे टीकाकार आणि 'पवार' या आडनावाची नकोशी असणारेही देतील. महाराष्ट्राच्या इतिहासात राज्याचे वीज महामंडळ नफा पाहू शकले, ते अजितदादांमुळे. शेतकऱ्यांचे, ग्राहकांचे लांगूलचालन हा राजकीय धर्म मानला जात असताना अजितदादा 'गुमान वीज बिल भरा' असा सज्जड इशारा आपल्या खास खर्जातून देण्यास कमी करत नसत. हा इशारा फक्त कागदोपत्री नसे. पुढे जाऊन वीज बिल थकवणाऱ्या ग्राहकांची वीज खुशाल तोडा, असा त्यांचा आदेश होता आणि तो प्रत्यक्षात येऊ लागल्याचे पाहिल्यावर वीज बिलांची थकबाकी आपसूक वसूल झाली. त्या वेळी अजितदादा आपल्या अधिकाऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. अगदी अलीकडे गेल्या निवडणुकांतही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आस असताना अजितदादा त्यांना 'कर्ज फेडावे लागेल' असे बजावण्यास कमी करत नव्हते. नंतर 'लाडक्या बहिणीं'ची अव्यवहार्यता सांगण्याचे धैर्य दाखवले ते अजितदादांनीच. स्वतःच्या खात्यातील विषयांवर त्यांची इतकी घट्ट मांड असे की उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकालात त्यांनी एकनाथ शिंदे आणि अन्यांच्या खर्चावर नियंत्रण आणण्याची हिंमत दाखवली. त्याचमुळे ठाकरे यांची साथसंगत सोडून शिंदे आणि कंपूने भाजपशी घरोबा करण्यामागील एक कारण अजितदादा हे होते हे विसरता येणार नाही. त्याचमुळे भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांकडील अर्थ खात्यास हात लावला नाही. अन्य अनेकांची नाराजी ओढवून अर्थ खाते अजितदादांकडेच राहिले.

काका शरद पवार यांच्याकडून अजितदादांनी जे काही मोजके गुण घेतले त्यातील हा एक. मंत्रालयात सकाळी साताच्या ठोक्याला ते हजर असत. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच्या नोंदी वाचणे,

स्पष्टवक्तेपणा, सडेतोडपणा, निःसंदिग्धपणा, प्रशासनावर पकड, विषयाचा बारकाईने अभ्यास, अर्थकारणाची जाण, वक्तशीरपणा अशा किती तरी गुणांमुळे त्यांचे राजकारण इतरांपेक्षा वेगळे ठरले.

निर्णयाचा मसुदा अभ्यासणे, त्याचे शब्दप्रयोग, त्याची कार्यकक्षा इत्यादी बारीकसारीक गोष्टीत अजितदादांना गती होती आणि हे मुद्दे ते कधीही नजरेआड करत नसत. मंत्रिमंडळ बैठकीत एखादा निर्णय झाल्यानंतर त्याचे इतिवृत्त वाचणे आणि त्या निर्णयाचा पाठपुरावा करणे ही त्यांची सवय होती. हे आपोआप होणारे नाही. त्यास कष्ट करावे लागतात आणि प्रयत्नांचे सातत्य लागते. ते अजितदादांकडे होते. त्यामुळे अन्य अनेक राजकारण्यांप्रमाणे नोकरशहा अजितदादांच्या बाबत कधीच वरचढ ठरू शकले नाहीत. उलट नोकरशहांसाठी अजितदादा हे काका शरदरावांप्रमाणे आदर्श होते. जे काही करायचे ते निःसंदिग्धपणे आणि जे काही होईल त्याची मालकी घ्यायची तीही निःसंदिग्धपणे. संशय, गोंधळ यांस जागा ठेवायची नाही आणि कागदी घोडे नाचवायचे नाहीत हा पवार कुटुंबाचा खाक्या त्यांनी इमानेइतबारे पाळला.

काकांकडून न घेतलेल्या एका गुणाने मात्र अजितदादांचा घात केला. मुत्सद्देगिरी त्यांना जमली नाही आणि 'थंडा करके खाओ' हे ते कधी शिकले नाहीत. त्याचे मूळ लहानपणी घरात झालेल्या त्यांच्या कोडकौतुकात असणार. मुलगा म्हणून लहानग्या आणि तरुण अजितलाही घरी अतिरिक्त मान होता. पण त्यातून त्यांचा 'मी म्हणेन ती पूर्व' असा स्वभाव घडला असणार. त्यामुळे राजकारण हे बहुतांश वेळी भावनिक असते, ही बाब त्यांनी दुर्लक्षली. स्पष्टवक्तेपणा हा अन्य क्षेत्रांत भले सद्गुण असेल. पण राजकारणात मात्र तो दुर्गुणच ठरतो. अजितदादांनी या वास्तवाची फिकीर केली नाही; हे खरे. पण या वास्तवाकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांचे अतोनात नुकसान झाले हेही खरे. अजितदादांच्या लोकप्रियता प्रसारास त्यामुळे मर्यादा आल्या. माणसे फटकळ व्यक्तींपासून स्वतःस चार हात दूर ठेवतात. अजितदादांपासून त्यामुळे अनेकांनी हा दुरावा अनुभवला. तो मिटवण्याची गरज कधी अजितदादांना वाटली ना कधी त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले.

पार्श्वभूमीमुळे असेल; पण सत्ता हे त्यांच्यासाठी साध्य ठरत गेले, साधन राहिले नाही. वास्तविक ज्यांनी त्यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला त्यांना अजितदादांनी जाहीर आव्हान देत आरोप सिद्ध करा; नपेक्षा मागे घ्या, असे आव्हान देणे अधिक मर्दुमकीचे ठरले असते. अजितदादांनी ही संधी दवडली आणि वर उलट असे आरोप करणाऱ्यांच्या दरबारात स्वतःला सादर करण्यात कमीपणा मानला नाही. वास्तविक अजितदादांना आपल्या कळपात ओढणे ही केंद्रातील सत्ताधीश भाजपची मानसिक गरज होती. राजकीय नव्हे. हा फरक अजितदादांना ओळखता आला नाही. कदाचित केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा टाळणे हे त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आणि प्राधान्याचे असावे. विकास हे कारण भले त्यांनी पुढे केले असेल. पण त्यावर शेंबड्या पोराचाही विश्वास नव्हता. कारण सत्तेशिवायही विकास कसा होऊ शकतो याचे उदाहरण त्यांच्या काकांनी घालून दिलेले होते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही अजितदादांची राजकीय अपरिहार्यता होती. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या ज्येष्ठापासून ते उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या अनुक्रमे अननुभवी आणि कनिष्ठ मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली काम करण्यात त्यांना कमीपणा वाटला नाही. आताही ते देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू साथीदार मानले जात. कारण मुख्यमंत्र्यांविरोधात कारवाया, काड्या आणि कागाळ्या करण्याचा कुटिरोद्योग त्यांनी कधीही केला नाही. अर्थात तसे करण्याखेरीज त्यांस पर्यायही नव्हता, हेही खरे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांच्यापासून त्यांचा पक्ष दूर करणे ही भाजपची गरज होती. ती अजितदादांनी पूर्ण केली.

त्याचमुळे त्यानंतरच्या प्रत्येक राजकीय चाचणीत यशस्वी होणे ही त्यांची गरज बनली. यशाचा अभाव त्यांना परवडणारा नव्हता. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांत या यशाने हुलकावणी दिल्यानंतर अजितदादा आगामी जिल्हा परिषदांसाठी अधिक त्वेषाने कामाला लागले. या अपघाताचे कारण ठरलेला विमानप्रवास त्यामुळेच त्यांना करावा लागला. जे झाले ते दुर्दैवी. पण यानिमित्ताने तरी राजकारणात अतोनात वाढलेल्या स्पर्धेचा (कॉम्पिटेटिव्ह पॉलिटिक्स) संबंधित विचार करणार आहेत की नाही? राजकारण हे सर्वस्व नाही आणि त्यातील यश हे तर अजिबातच नाही. जगण्याच्या अनेक अंगांतील ते एक. पण ते जगण्याचे प्रयोजन बनत असल्याचे अलीकडे दिसून येते. काव्यशास्त्रविनोद, चित्र, संगीत, नाट्य अशा जगणे समृद्ध करणाऱ्या घटकांत या अलीकडच्या राजकारण्यांस कसलीही रुची नाही. पवार घराण्यातील असूनसुद्धा अजितदादांनी ही अंगे काकांकडून घेतली नाहीत, हे खेदाने नमूद करावे लागते. सतत नुसते धावायचे. कसल्या तरी पराजयाच्या भीतीने नुसते धावायचे. पण हा कथित पराजय टाळून मिळवायचे काय याचे उत्तर सोडा; पण या मंडळींस तो प्रश्नही पडत नाही. ''कोणतेही यश अंतिम नसते आणि अपयश जीवघेणे नसते'' असे इंग्लंडास दुसरे महायुद्ध जिंकून देणारे विन्स्टन चर्चिल म्हणत. तरीही अनामिक यशामागे हे सारे धावणारे आपले सांस्कृतिक अपंगत्व तेवढे प्रदर्शित करतात. त्याच यशामागे धावण्यात धन्यता मानताना अजितदादांनी आपले आयुष्य हकनाक गमावले. मुख्यमंत्रीपद हे त्यांचे स्वप्न होते. ते आता कायमचे अपूर्ण राहील.

त्यांच्या मातोश्री हयात आहेत. आपल्या अपत्याची अंतिम यात्रा पाहण्यापेक्षा अधिक दुःखद त्या आईसाठी दुसरे काय असेल? नेत्यावर अपेक्षा लादणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी, उपनेत्यांसाठी भले एक पक्षप्रमुख, आश्वासक उद्धारकर्ता गेला असेल. पण त्या आईस गोविंदाग्रज लिहून गेले त्याप्रमाणे ''दुर्दैवनगाच्या शिखरी/ विधवा दुःखी आई/ मांडीवर मेलें मूल/ तो हृदया धक्का बसला/ राजहंस माझा निजला'' असेच वाटेल. 'लोकसत्ता' परिवारातर्फे अजितदादांच्या आप्तेष्टांप्रति सहवेदना.

उत्तम प्रशासक!

डॉ. नितीन करीर
माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने एक कुशल, उत्तम प्रशासक, मंत्री गमावला आहे. १९९०च्या दशकात माझ्या प्रशासकीय सेवेला प्रारंभ झाला, त्याच वेळी अजितदादाही राजकारणात सक्रिय झाले होते. मी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होतो तर ते राज्यमंत्री होते. गेल्या ३० वर्षांत अनेकदा त्यांच्याबरोबर काम करण्याची, त्यांच्याकडून काहीतरी चांगले शिकण्याची संधी मिळाली.

स्पष्टवक्तेपणा, कडक स्वभाव अशी दादांची ओळख. ते स्पष्ट आणि अगदी खरे बोलतात, हातचे काही राखून ठेवत नाहीत अशी त्यांची प्रतिमा. मात्र त्यामागची दुसरी बाजू वेगळी आहे. नियमांना बांधील, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर पराकोटीचा विश्वास, राज्यातील प्रश्नांची उत्तम जाण, सतत लोकांसाठी काम करण्याची तळमळ हे त्यांचे गुण वाखाणण्याजोगे होते.

दादांचा एखाद्या अधिकाऱ्यावर विश्वास बसला की तो एखाद्या प्रकरणाबाबत जे कायदे वगैरे सांगे, त्यासंदर्भात दादा त्या अधिकाऱ्याच्या पद्धतीने काम करीत. एखाद्या अधिकाऱ्याने एखादे काम नियमात बसत नाही असे सांगितले तर दादा त्याच्यावर विश्वास ठेवून संबंधितांना तसे समजावून सांगत, याचा गेल्या कित्येक वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत आम्ही अनेक अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अनुभव घेतला आहे. दादांचे तिसरे गुणवैशिष्ट्य म्हणजे तांत्रिक मुद्दा समजावून घेण्याचा संयम. कोणत्याही विभागाशी सबंधित कोणतीही गोष्ट असेल, त्यातील बारकावे समजावून घेण्याची त्यांची ताकद अफाट होती. त्यांची आणखी एक खासीयत होती, त्यांनी कोणाला भेटीसाठी वेळ दिली, तर ते त्याला त्या वेळी भेटणारच. भेटीचीही त्यांची एक पद्धत होती. ज्या व्यक्तीला वेळ दिली आहे, त्या वेळेत तिला बोलू द्यायचे, भूमिका मांडू द्यायची, तिचे बोलणे शांतपणे ऐकून घ्यायचे आणि नंतर तिला प्रश्न विचारायचे. म्हणजे त्यांनी अर्धा तास वेळ दिला असेल तर त्यातील २५ मिनिटे तिच्या हक्काची आणि शेवटच्या पाच मिनिटांत ते तिला प्रश्न विचारणार, समजून घेणार आणि लगेच निर्णयही घेणार. इतका संयम फार कमी राजकारण्यांकडे दिसून येतो.

कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकून घेणे, समजावून घेणे ही दादांची आणखी एक खासीयत. वित्त विभागाचा सचिव असताना मी अनेक वेळा मी हा अनुभव घेतला. एखाद्या विषयावरचे सादरीकरण अतिशय बोगस आहे, ते कशाला पाहता असे सुचविले तरी दादा ते शांतपणे ऐकून घ्यायचे. त्याला मांडायचे आहे ते मांडू द्या, बोलू द्या. त्यातून काय घ्यायचे हे मी पाहतो असे ते सांगायचे. त्या वेळेत त्यांचे लक्ष केवळ त्या विषयावर असायचे. त्या वेळी ते फोन बघणार नाहीत, कोणाशी बोलणार नाहीत. वेळेची शिस्त पाळण्यात त्यांचा हात कोणीच धरू शकत नसे. पहिली बैठक १० वाजता, दुसरी १०.०५. तिसरी १०.१२ मिनिटांनी होणार असेल आणि तुम्ही दिलेल्या वेळेत पोहोचणार नसाल तर त्यांच्या कार्यालयातील लोक सतत फोन करून बैठकीच्या वेळेची आठवण करून देत.

अफाट स्मरणशक्ती ही दादांना लाभलेली आणखी एक दैवी देणगी होती. उदाहरणार्थ २० वर्षांपूर्वी एखाद्या कृषी महाविद्यायात गेले असताना तेथे पाहिलेल्या संशोधनाची माहिती ते कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना

प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी यांच्यातील संबंध कसे असावेत याचा दादा वस्तुपाठ होते. सर्व अधिकाऱ्यांशी ते समान न्यायाने, आपुलकीने वागायचे.

देत. विशेषतः कृषी आणि पशुसंवर्धन विषयावरील त्यांच्याइतकी माहिती अन्य कोणाकडे असेल असे वाटत नाही. जलसंपदा विभागाचीही त्यांना प्रचंड जाण होती. अजितदादा कुशल प्रशासकही होते. प्रशासकीयदृष्ट्या कोणताही विषय नीट समजून घेणारे, सबंधितांशी चर्चा करून पटकन निर्णय घेणारे दादा आगळेवेगळे होते. बऱ्याच वेळा ते सकाळी सकाळी फोन करत. अहो कमिशनर, माझ्यासमोर हे अमुक-तमुक बसलेले आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. तुम्ही स्पीकर फोनवर आहात हे ते आवर्जून सांगणार. समोरच्या व्यक्तीचे बोलणे झाल्यावर आपण आपले मत मांडायचे. ते ऐकून मग दादा समोरच्या व्यक्तीलाही ते समजावून सांगत आणि तेथेच निर्णय घेऊन विषयाचा तुकडा पाडत. त्यानंतर तो विषय बंद अशी दादांची अफाट निर्णयक्षमता होती.

राजकारणापलीकडे दादांचा नाट्य, कला, साहित्य, संस्कृती याकडे त्यांचा कल नाही, त्यांना त्याची आवड नाही असे म्हटले जायचे. पण याची दुसरी बाजू अशी की, दादांचे सर्व लक्ष प्रशासकीय काम आणि राजकारणावर केंद्रित असे. या दोन्ही गोष्टींवरील त्यांचा फोकस तिळमात्रही ढळला नाही. राजकारण, समाजकारणावरील दादांचे लक्ष इतके तीव्र होते की, ते पहाटेपासूनच क्षेत्रीय पाहणीच्या कामाला लागायचे. मग तो करोनाचा काळ असो वा एखाद्या कार्यालयात, सरकारी इमारतीला दिलेली भेट असो. स्वतः जाऊन त्या भागाची पाहणी करणे, त्यातील त्रुटी दाखवून देणे, स्वच्छतेला प्राधान्य देणे, दिवसभराचे काम वेळेत करणे आणि रात्री लवकर काम संपवणे ही त्यांची पद्धत आम्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी खूपच लाभदायक होती.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा दादांचा गाढा अभ्यास होता. आतापर्यंत ११ वेळा त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पाची तयारीही त्यांनी सुरू केली होती. अर्थसंकल्पातील आकडे कोठून येतात. त्या आकड्यांच्या मागे काय गणिते आहेत, त्या गणितांच्या मागे कोणते प्रकल्प आहेत आणि त्या प्रकल्पांच्या मागे कोणते लोक आहेत... म्हणजेच कोणाला या प्रकल्पांचा लाभ होणार आणि कोण बाधित होणार हे समजणे सोपे नसते. त्यात खूप बारकावे असतात. शिवाय अर्थसंकल्पात आकड्यांचा खेळही मोठा असतो. मात्र या सर्व बाबींची दादांना उत्तम जाण आणि ज्ञान होते. त्यामुळे व्यय समितीच्या बैठकीत निर्णय लगेच व्हायचे. त्यांना कोणता प्रकल्प किती महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी किती निधीची गरज आहे. कोणत्या प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे याची सखोल माहिती असायची.

जलसंधारण हा त्यांच्या आवडीचा विषय. राज्यातील नद्या, त्या कुठून कुठे आणि किती महिने वाहतात याची सर्व माहिती अजितदादांना होती. मला नदीकाठी घर बांधायचे होते. दादांची वेळ घेऊन त्यांना कल्पना सांगितली. त्या वेळी दादांनी सर्व नद्यांची, त्यांच्या पाणीसाठ्याची महिती सांगितली. पुढील तीन वर्षांत नद्यांची काय परिस्थिती असेल, माझे बजेट आणि गरजा याचा विचार करून कुठे घर बांधावे याची त्यांनी माहिती दिली. जलसंधारणाबाबतचे त्यांचे ज्ञान अफलातूनच होते. नुसती माहिती असून उपयोग नाही तर त्याचे विश्लेषण करून या माहितीचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याचे असाधारण कौशल्य त्यांच्याकडे होते.

स्पष्टवक्तेपणाच्या, फटकळ बोलण्याच्या सवयीमुळे त्यांच्या या असाधारण बाबी लोकांसमोर आल्या नसतील. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबत विचार केल्यास दादा म्हणजे राज्यातील उत्कृष्ट प्रशासक मंत्री असे अधिकारी सांगतील. कोणताही विषय समजून घेण्याचा संयम, समजून घेतलेली गोष्ट कायम ध्यानात ठेवणे, कठोर निर्णयक्षमता, एकदा निर्णय घेतला की त्याला बांधील राहणे, अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे दादांचे गुण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नेहमीच प्रोत्साहन देणारे वाटायचे.

कितीही चिडचिड झाली, त्रास झाला तरी लोकांना भेटण्याचे, त्यांच्या अडचणी ऐकून घेण्याचे दादांनी कधी थांबवले नाही. कृपया कोणी चपला काढू नयेत ही त्यांच्या बंगल्याच्या दर्शनी लावलेली पाटी खूप काही सांगून जाते. येणारा माणूस कोणत्या पक्षाचा, जातीचा आहे, गरीब आहे की श्रीमंत आहे असा विचार न करता येईल त्याचा प्रश्न कसा सुटेल याकडे दादांचा कटाक्ष असे. त्यांच्या स्वीय साहाय्यकांनाही कायम सतर्क रहावे लागत असे. कारण येणाऱ्या प्रत्येकाचे काम मार्गी लावणे याकडे दादांचा कटाक्ष असे.

गेल्या काही दिवसांत दादांची तीव्र विनोदबुद्धी हा त्यांचा आणखी एक गुण लोकांसमोर आला. सार्वजनिक ठिकाणी, व्यासपीठावर त्यांना कोणी तरी ओरडून सांगावे, 'आय लव्ह यू' आणि व्यासपीठावरूनच 'हेच घरी जाऊन तुझ्या बायकोला का सांगत नाहीस' असे त्यांनी म्हणावे. दादांचा हा हजरजबाबीपणा, समयसूचकता, लोकांना हसविण्याची वृत्ती हा नवा पैलू अलीकडच्या काळात फार उभारून आला होता. कर्मकांडापासून दूर राहण्याची, अंधश्रद्धेला थारा न देण्याची दादांची वृत्ती अन्य राजकारण्यांसाठी वस्तुपाठ होती.

प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी यांच्यातील संबंध कसे असावेत याचा दादा वस्तुपाठ होते. काही अधिकाऱ्यांबरोबरच्या मैत्रीसबंधांचा अपवाद वगळता अजितदादांचे प्रशासनाबरोबरचे संबंध व्यावसायिक होते. सर्व अधिकाऱ्यांशी ते समान न्यायाने, आपुलकीने वागत. एखाद्या मंत्र्याने सांगितलेल्या दहा कामांपैकी नऊ केली आणि एक केले नाही तर तो नाराज झाल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. अजितदादा मात्र याला अपवाद होते. त्यांनी सांगितलेल्या कामांपैकी काही कामांना अधिकारी नाही म्हणाले तरी ते नाराज होत नसत. त्यांचे हे स्वभावगुण राज्याच्या सध्याच्या परिस्थितीत खूपच दिशादर्शक आणि दिलासादायक होते. आज महाराष्ट्र ज्या परिस्थितीत आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या गुणांचा उपयोग झाला असता. मात्र नियतीलाच ते मान्य नसावे.

शब्दांकन– संजय बापट

अजित पवार नावाचे वलय...

उल्हास पवार
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, माजी आमदार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त धक्कादायक आणि अत्यंत वेदनादायी आहे. अजितदादांनी राजकारणात आपल्या कृतीतून ठसा उमटवला. त्याहीपेक्षा प्रशासनात एक दबदबा निर्माण केला. प्रशासनावर त्यांची उत्तम पकड होती. सध्या बऱ्याच नेत्यांमध्ये विषयाच्या आकलनाचा अभाव दिसतो. मात्र, एखादा विषय ताबडतोब समजून घेऊन त्याची पूर्तता करण्याचे कसब अजितदादांकडे होते. ही क्षमता दिवंगत मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, विलासराव देशमुख आणि शरद पवार यांच्याकडे असल्याचे मी पाहिले आहे. ही मंडळी आपल्या अफलातून आकलनशक्तीच्या जोरावर कोणताही विषय मार्गी लावायची. विषय कोणताही असेल, तो क्षणात समजून घेण्याची कला अजितदादांच्या अंगी होती. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ऐन तारुण्यात काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. त्यातून हे व्यक्तिमत्त्व घडले होते.

अगदी सुरुवातीच्या काळात तरुण वयात ते खासदार झाले. त्यांना राजकीय वारसा असला, तरी आपले वेगळेपण जपणे महत्त्वाचे असते. अजितदादांनी त्यांच्या कर्तृत्वातून हा वारसा आणि वेगळेपणा जपला. बुद्धिमत्ता, स्मरणशक्ती आणि आकलनशक्तीच्या जोरावर जी माणसे आपला ठसा उमटवतात, त्यामध्ये अजितदादांचे नाव घ्यायला लागेल.

अजितदादांचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे वक्तशीरपणा. मंत्रिमंडळाची बैठक असेल, एखाद्याला भेटीची वेळ दिली असेल किंवा त्यांच्या खात्याची बैठक असेल, तर वेळेच्या अगोदर ते पोहोचायचे. अनेक समारंभांमध्ये हे त्यांचे वेगळेपण मी पाहिले आहे. अनेक राजकारणी हे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी वेळेवर जात नसल्याचा अनुभव नागरिकांना येतो. मात्र अजितदादा हे कोणत्याही कार्यक्रमाला वेळेवर किंवा वेळेच्या अगोदर जायचे. सध्याच्या काळात ही गोष्ट दुर्मीळ झाल्यासारखी झाली आहे. मात्र अजितदादा हे कायमच वेळेत यायचे. अजितदादांनी शरद पवार यांचे काही गुण आत्मसात केले. त्यापैकी हा एक होता. शरदराव हे सकाळी साडेसात वाजता तयार असतात. रात्री कितीही जागरण झाले तरी ते सकाळी नागरिकांच्या भेटीसाठी तयार असतात. शरदरावांच्या सान्निध्यामध्ये १९७० ते १९७८ पर्यंत मी सावलीसारखा त्यांच्याबरोबर फिरलो आहे. त्यांचा हा गुण मी जवळून पाहिला आहे.

अजितदादांना मी पहिल्यांदा पाहिले तो १९७० चा काळ असेल. तेव्हा ते १० ते ११ वर्षांचे होते. शरद पवारांबरोबर माझा मुक्कामही रामटेकला असायचा. मी आऊट हाऊसमध्ये एक खोलीत राहात होतो. तेव्हापासून मी अजितदादांना पाहत आलो. बारामतीला अनेक वेळा मी शरदरावांबरोबर गेलो, अंबराईच्या जुन्या घरी मी अजितदादांना पाहत आलो. अजितदादांचे वडील, त्यांना घरातील सर्व जण 'तात्या' म्हणायचे. अजितदादांच्या वडिलांचे शरदरावांवर अतिशय प्रेम. या कुटुंबात सामंजस्य आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील हे आदर्श कुटुंब म्हटले पाहिजे. मोठे कुटुंब असतानाही हा सगळा परिवार एकत्र राहतो.

एखादा शब्द चुकून गेला, तर माफी मागण्याचे धाडस त्यांच्यात होते. चूक झाल्यावर ते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीजवळ बसले होते. त्यांच्या प्रामाणिकपणाला सलाम केला पाहिजे.

महिला राजकारणात फारशा नसायच्या, त्या काळात शरदरावांच्या आई तेव्हाच्या लोकल बोर्डाच्या सदस्या होत्या. वेगवेगळ्या विचारसरणीची माणसे कुटुंबात असली तरी त्यांच्यात प्रेम आणि सामंजस्याची भावना आहे. संत गाडगे महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि सत्यशोधक समाज यांचा वारसा या कुटुंबामध्ये आहे, त्यामुळे धर्मांधता, जातीयता हा विषय त्यांच्या कुटुंबात नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबात प्रत्येकाला मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अजितदादा हे थोडे आक्रमक होते. पण त्याचा अर्थ कोणाचा तरी अपमान करणे असा नव्हता. आक्रमकतेचा अर्थ ठरलेली गोष्ट न घाबरता अमलात आणणे. ही धडाडी त्यांच्यामध्ये कायम होती.

अजितदादांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे वक्तृत्व आणि व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण. शरद पवार यांनी जसे स्वतःला घडवले, त्याप्रमाणे अजित पवार यांनी स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व घडवले. एखादे व्यक्तिमत्त्व हे शिबीर घेऊन विकसित करता येत नाही. त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. ते शरद पवार यांनी केले, तसेच अजित पवार यांनी केले.

अजितदादांना आवाजाची देणगी होती. त्यांचा आवाज पहाडी होता. तेच त्यांचे वेगळेपण होते. अशा आवाजातून बोललेले कधी कधी समोरच्याला उद्धट वाटते. तसा समज अजितदादांबाबत अनेकांचा व्हायचा. ते कोणाचाही अपमान करत नसत. मात्र एखादी गोष्ट होणार नसेल तर ते स्पष्टपणे सांगायचे. तसेच काम होणार असेल तर तेही स्पष्टपणे सांगायचे, हे मी पाहिलेले आहे. त्यांनी एखादे काम करायचे ठरवले तर ते शंभर टक्के करून दाखवायचे. 'करतो', 'बघतो', हे शब्द त्यांच्या शब्दकोशात नव्हते. तो त्यांचा स्वभावच नव्हता.

त्यांनी राज्य सहकारी बँक अत्यंत यशस्वीपणे चालवली. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. भूविकास बँकेच्या माध्यमातूनही मदत केली. राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँक आणि विविध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ते काम करत राहिले. कित्येक वर्षे त्यांनी पुण्याचे नेतृत्व केले. ते करताना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र शेतकऱ्यांचे दुःख पाहिल्यानंतर, थोडेसे नियमात बदल करून ते मदत करत राहिले. त्यासाठी त्यांनी कधीही हात मागे घेतला नाही, हे या ठिकाणी सांगितले पाहिजे. अनेक सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या अशा सहकारातल्या विविध संस्था जिवंत ठेवणे, त्यांना पाठबळ देणे आणि सहकार टिकवण्याचे काम अजितदादांनी केले.

महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे सहकाराचे असलेले जाळे. देशात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि काही प्रमाणात आंध्र प्रदेश अशी तीन-चार राज्ये वगळता अन्य ठिकाणी सहकार प्रभावी दिसत नाही. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक यांनी सहकार क्षेत्र हे केवळ जपले नाही, तर ते जोपासले आणि हरितक्रांतीच्या दृष्टीने वाटचाल केली. त्यांना योग्य तो न्याय देण्याचे काम आणि योग्य ते संतुलन ठेवण्याचे काम धाडसाने ज्या मोजक्या लोकांनी केले त्यामध्ये अजितदादांचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल.

अजित पवार यांनी राज्य सरकारमध्ये विविध खाती सांभाळली; पण अर्थ खाते त्यांनी अधिक सक्षमपणे सांभाळले. कुणी कितीही टीका- टिप्पणी केली, तरी ते निर्णयावर ठाम असायचे. अर्थसंकल्पामध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्या चाकोरीतच त्यांनी काम केले. निर्णय घेण्याची अत्यंत कठोर क्षमताही अजित दादांमध्ये होती. कोणतेही खाते असले, तरी विषय समजून घेऊन निर्णय घ्यायचे, हे त्यांचे विशेष होते.

बोलण्याची कला त्यांनी आत्मसात केली होती. अलीकडे त्यांची भाषणे ऐकताना ते अधिकाधिक प्रगल्भ झालेले दिसून यायचे. शैलीदार वक्तृत्व, मार्मिक टिप्पणी करत विनोदाची झालर देऊन श्रोत्यांना आपलेसे करायचे. निवडणुकीची सभा असली, तर त्या ठिकाणी कसे बोलायचे, गंभीर प्रश्न असल्यास कशी भूमिका मांडायची. प्रशासनाशी कसा संवाद साधायचा हे त्यांनी अतिशय उत्तम प्रकारे जपले. अनेक नेत्यांमध्ये अभावाने ही गोष्ट आढळते. एखाद्या नेतृत्वाबद्दल आदर व्यक्त करणे किंवा मूल्यमापन करताना आपले मत व्यक्त करणे, यामध्ये त्यांनी कधीच माघार घेतली नाही.

तुमचे आवडते मुख्यमंत्री कोण, असा प्रश्न विचारताच ते क्षणात म्हणायचे, विलासराव देशमुख! त्यांनी हे अनेकदा सांगितले. ते खासगीत कधी कधी म्हणायचे, मुख्यमंत्र्यांना सहकार समजला पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांना शेती समजली पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांना उद्योग समजला पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांना शैक्षणिक वातावरण कसे आहे, ते समजले पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीची थोडी तरी माहिती हवी. विलासरावांकडे गेल्यावर ते एका क्षणात समजून जातात. विलासरावांबद्दल त्यांना खरोखरच खूप आदर होता. अलीकडच्या काळात, एका नेत्याने निवडणुकीच्या दरम्यान विलासरावांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले, तेव्हा लातूरमध्ये जाऊन तिथे आपला उमेदार असतानाही ते विलासरावांबद्दल स्पष्ट बोलले. लोकशाहीमध्ये हे फार महत्त्वाचे आहे.

कधी कधी एखादा शब्द चुकून गेला, तर माफी मागण्याचे तेवढेच धाडस त्यांच्यामध्ये होते. चूक झाल्यावर ते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीजवळ बसले होते. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल खरंच सलामच केला पाहिजे. ते रोखठोक बोलायचे. त्यांच्याकडे बोथटपणा नव्हता. योग्य व्यक्तींबद्दल त्यांच्या मनात अत्यंत आदर होता.

दबदबा असलेले नेते खूप झाले. मला नेहमी वाटायचे की, अजित दादा हे भविष्यात दिल्लीत वलय निर्माण करतील. नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव यांच्याप्रमाणे दिल्लीत अजित पवार नावाचे वलय निर्माण होऊ लागले होते.

पुण्यात माजी नगरसेवक अप्पा रेणुसे यांच्या संस्थेच्या वतीने दरवर्षी गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. त्यात अजित दादांच्या हस्ते माझा सत्कार करण्यात येणार होता. मात्र, कामाच्या व्यापामुळे दोन वेळा हा कार्यक्रम त्यांना पुढे ढकलावा लागला. आता मात्र, तो सत्कार राहूनच गेला...

शब्दांकन– सुजित तांबडे

चिपळुणमध्ये २१ जणांची माघार

उमरोली जिल्हा परिषदेसाठी बंडखोरी कायम

जिल्हा परिषद गटासाठी रिंगणात असलेले उमेदवार

लोकसत्ता वार्ताहर

चिपळूण : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी एकत्रीत ११६ पैकी २१ उमेदवारांनी मंगळवारी माघार घेतली. यात जिल्हा परिषदेच्या सहा तर पंचायत समितीच्या ११ उमेदवारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे उमरोली जिल्हा परिषद गटात बंडखोरी कायम राहिली असून येथील लढतीकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या नऊ गटांत ४४ उमेदवारांनी तर पंचायत समितीच्या १८ गणांत ७२ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते. अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी जिल्हा परिषदेच्या शिरगांव गटातून राधीका नयनेश नारकर, उमरोली गटातून अजित सदाशिव थरवळ व नंदकुमार रामचंद्र थरवळ, वहाळ गटातून आर्या विठ्ठल जाधव, कोकरे गटातून पुनम संतोष चव्हाण व किशोर भालचंद्र घाग या सहा जणांनी माघार घेतली.

पंचायत समितीच्या कळवंडे गणातून सारिका सागर चिले, पेढे गणातून रोशन सुनील आंब्रे, खेर्डीतून संदेश संजय मोहिते, अलोरेतून प्रवीण गंगाराम पेंढारे, पिंपळी खुर्दमधून पूजा प्रकाश पालकर व जयश्री विश्वनाथ सकपाळ, वेहेळे मधून संजय सीताराम जाबरे, शिरगांवमधून साक्षी अजित लाड, मांडकीमधून प्रमोद खेडेकर, निवळीतून स्नेहश्री सुर्वे, वहाळमधून सुमित पाध्ये, शशिकांत घेवडे व प्रीतेश जावळे आणि कोकरे गणातून नारायणी निलेश खापरे व पूनम संतोष चव्हाण आदींनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेतली आहे. या निवडणुकीत वहाळ, कोकरे, पेढे, खेर्डी, मांडकी आणि उमरोली गटांत बंडखोरी झाली होती. अपक्षांचे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी नेत्यांच्या खटाटोपाला अखेरच्या दिवशी यश आले. मात्र युतीत उमरोली गटात बंडखोरी कायम राहिली आहे.

- कळवंडे गट - गौतमी निलेश चव्हाण आदवडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सामिया सलिम तांबे (ठाकरे गट), मयुरी मिलिंद शिर्के (शिवसेना), ॲड. गीता विकास जाधव (वंचित बहुजन आघाडी)
- पेढे गट - मानसी महेश भोसले (ठाकरे गट), दीप्ती दीपक महाडिक (भाजप), सानवी स्वप्नील शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- खेर्डी गट - स्वरा निलेश जावळे (ठाकरे गट), दिशा दशरथ दाभोळकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस), रावी सतीश मोरे (भाजप)
- अलोरे गट - गायत्री गणेश कदम (राष्ट्रवादी काँग्रेस), विनया

विनोद झगडे (शिंदे गट)

- शिरगांव गट - दिक्षा दत्ता कांबळी (शिंदे गट), अमिता अरुण मोडक (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष), नेहा सुरेश रहाटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- सावर्डे गट - ममता जयराम खांबे (ठाकरे), पूजा शेखर निकम (राष्ट्रवादी काँग्रेस), धनश्री रवींद्र शिंदे (शिंदे गट)
- उमरोली गट - निलेश अनंत चव्हाण (राष्ट्रवादी काँग्रेस), प्रमोद सुरेश निवळकर (ठाकरे), योगेश चंद्रकांत शिर्के (भाजप), योगेश यशवंत खांडेकर (अपक्ष)
- वहाळ गट - पूर्वा सुभाष जाधव (ठाकरे), आदिती हरिश्चंद्र भागडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), शिवानी संदीप सावंत (शिंदे गट)
- कोकरे गट - सिद्धार्थ ताराबाई लक्ष्मण कदम (शिंदे गट), संजय राजाराम कदम (राष्ट्रवादी काँग्रेस), संतोष बंडाजी चव्हाण (ठाकरे गट), विलास भागोजी डिके (बसपा)

रायगड जिल्ह्यातही शोकाकुल वातावरण

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

अलिबाग : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या अचानक निधनाने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. अजित पवार यांच्या अकाली, अपघाती मृत्यूने रायगड जिल्हयात देखील शोकाकुल वातावरण पहायला मिळाले. जिल्हयातील प्रमुख नेत्यांनी तातडीने बारामतीकडे धाव घेतली. बुधवारी सकाळीच अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची माहिती मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे हे तातडीने बारामतीकडे रवाना झाले. शेकाप नेते जयंत पाटील यांनीही बारामती गाठली. अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल जिल्हयात हळहळ व्यक्त होत आहे. जिल्हयाच्या काही भागात आज बंद पाळण्यात आला. शाळांना सुटी देण्यात आली तसेच शासकीय कार्यालयासमोरील राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर आणण्यात आला. सर्व सरकारी कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी अजित पवार यांच्या निधनानिमित्त शोक व्यक्त केला आहे. एक निर्भीड आणि स्पष्टवक्ता नेता आपल्यातून निघून गेला ही मनाला वेदना देणारी बाब आहे. असा प्रसंग कुणावरही येवू नये. मी संपूर्ण रायगड जिल्हयाच्या वतीने अजित पवार यांना आदरांजली वाहतो, अशा शब्दांत गोगावले यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी आपल्या भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त करत सांगितले की मी सकाळीच ही बातमी ऐकली आणि सुन्न झालो. अजित पवार हे स्पष्टवक्ते, प्रामाणिक नेते आणि दिलेला शब्द पाळणारे व्यक्तिमत्व होते. राज्य स्तरावर विविध संस्थाबरोबर काम करताना त्यांची जवळीक कायम राहिली. अजित दादासोबत अनेक संस्था वर काम करताना निर्णय प्रक्रियेत मला ते सहभागी करून घेत. त्यांचा मोकळेपणा महाराष्ट्राला कधीच विसरणार नाही, असे जयंत पाटील म्हणाले.

> अजितदादांच्या जाण्याने महाराष्ट्राने एक ठाम निर्णय घेणारा आणि सामान्य माणसाच्या वेदनांशी नाते जपणारा खंबीर नेता गमावला आहे. संघर्षाच्या काळातही मागे न हटणारा हा लोकनेता पुढील पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरेल.
>
> **- नारायण राणे,** खासदार, माजी मुख्यमंत्री

> प्रशासनावर असलेली पकड, निर्णयक्षमता आणि कामातील कमालीची शिस्त हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांचा कामाचा वेग आणि नेतृत्वाचा ठसा जवळून अनुभवता आला.
>
> **- नितेश राणे,** बंदरविकास मंत्री

> अजितदादा स्पष्टवक्ते असले तरी मनातून अत्यंत प्रेमळ होते. मी राष्ट्रवादीत असताना त्यांनी माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवला होता. राजकीय घडामोडींच्या काळातही 'हा आम्ही घडवलेला कार्यकर्ता आहे', असे म्हणत त्यांनी माझे कौतुक केले होते. त्यांच्या जाण्याने मी माझा मार्गदर्शक गमावला आहे.
>
> **- आ. दीपक केसरकर,** माजी मंत्री

> अजितदादा हे माझे केवळ सहकारी नसून कौटुंबिक मित्र होते. सिंधुदुर्गची राजधानी 'ओरोस' उभारण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. त्यांच्यात राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची पूर्ण क्षमता होती, मात्र काळाने त्यांच्यावर दुर्दैवी घाला घातला.
>
> **- प्रवीण भोसले,** माजी राज्यमंत्री

कामाच्या दर्जासाठी आग्रह

विविध विकास कामांच्या भूमिपूजन, उदघाटनांच्या निमित्ताने असेल किंवा राजकीय मेळावे, प्रचार सभांसाठी अजित पवार अधूनमधून रायगड जिल्हयात येत असत. त्यांना कामे दर्जेदार लागत. अनेकदा ते कामांबाबत ठेकेदारांना उद्घाटनाच्या वेळी सुनावत असत. खासदार सुनील तटकरे मंत्री आदिती तटकरे यांनाही त्यांनी अनेकदा कामाच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना केल्या होत्या . केवळ निधी मागू नका, कामं दर्जेदार करा असं ते नेहमी सांगत.

...आणि स्वप्न अधुरे राहिले

परिसरातील तरुणांना चांगले शरीर कमावता यावे यासाठी अलिबाग तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष जयेंद्र भगत यांच्या प्रयत्नातून अलिबाग तालुक्यातील वाडगाव येथे व्यायाम शाळा बांधण्यात आली.सुनील तटकरे यांच्या खासदार निधीतून ५० लाख रुपये खर्चून ही भव्य इमारत उभी करण्यात आली आहे. या इमारतीचे उदघाटन अद्याप झालेले नाही. उदघाटन अजित पवार यांच्या हस्तेच करायचे, असा जयेंद्र भगत यांचा हट्ट होता परंतु हे स्वप्न आता अधुरे राहिल्याची खंत आणि रुखरुख लागून राहिल्याचे जयेंद्र भगत यांनी सांगितले.

१५० उमेदवारांची माघार

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. जिल्हा परिषदेच्या ५६ जागांसाठी दाखल झालेल्या २२६ अर्जांपैकी ४९ उमेदवारांनी, तर ९ पंचायत समितींच्या ११२ जागांसाठी दाखल झालेल्या ४४४ अर्जांपैकी १०१ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने मंगळवारी निवडणूक रिंगणाचे चित्र स्पष्ट झाले. जिल्हा परिषदेसाठी ४९, तर पंचायत समितीसाठी १०१ उमेदवारांनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेतल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्ह्यात सर्वाधिक बंडखोरीचा फटका चिपळूण, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी तालुक्यांना बसला. दापोली तालुक्यात पंचायत समितीच्या तब्बल २५ गणांत बंडखोरीचे चित्र दिसून आले. राजापूर, चिपळूण आणि मंडणगड तालुक्यांतही मोठ्या प्रमाणात अपक्ष व बंडखोर उमेदवार रिंगणात टिकून आहेत. संगमेश्वरमध्ये जि. प.चे ३ व पं. स.चे १०, लांजामध्ये अनुक्रमे ४ व ५, रत्नागिरीत ८ व ८, मंडणगडमध्ये ६ व ६, राजापुरात ४ व १६, चिपळूणमध्ये ६ व १५, गुहागरमध्ये २ व ३, तर दापोलीत जि. प.चे ८ व पं. स.चे २५ उमेदवार रिंगणात कायम आहेत. बंडखोरी रोखण्यासाठी काही ठिकाणी वरिष्ठ नेत्यांना यश आले असले, तरी नाराज इच्छुकांनी 'निवडणूक लढवायचीच' अशी भूमिका घेतल्याने येत्या काळात निवडणूक अधिकच चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निवडणुकीत ३५९ उमेदवार रिंगणात

लोकसत्ता वार्ताहर

सावंतवाडी : अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर प्रशासनाने २७ जानेवारी रोजी अंतिम अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या उर्वरित जागांसाठी ११५ उमेदवार, तर पंचायत समितीसाठी २४४ उमेदवार रिंगणात आहेत.

जिल्हा परिषदेसाठी कुडाळ तालुक्यात सर्वाधिक २२, तर वैभववाडीत सर्वात कमी ५ उमेदवार आहेत. पंचायत समितीसाठी सावंतवाडीत सर्वाधिक ५५, तर वैभववाडीत सर्वात कमी १४ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. २३ ते २७ जानेवारी दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता अनेक ठिकाणी थेट किंवा तिरंगी लढतीचे चित्र पाहायला मिळणार आहे.

विशेषतः काही ठिकाणी महायुतीमध्ये खदखद असल्याने सरळ लढत होत आहे. ठाकरे गटाचे उमेदवार अनेक ठिकाणी रिंगणात उतरले नसल्याने महायुतीच्या भाजप आणि शिंदे गट यांच्यात लढत होत आहे.

या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि काँग्रेस पक्षाचे राजकीय वर्तुळात चिंताजनक चित्र आहे.

अजितदादांच्या निधनाने राजकारणात मोठी पोकळी -सामंत

रत्नागिरी : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली असून त्यांच्या निकटवर्तीय नेते, कार्यकर्ते आणि सहकाऱ्यांना प्रचंड धक्का बसला आहे. या दुःखद घटनेवर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे उद्योग मंत्री तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी अजितदादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, अजितदादांचे नेतृत्व रोखठोक आणि 'ऑन द स्पॉट' निर्णय घेणारे होते. गेल्या २० ते २५ वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय प्रवासातील महत्त्वाचा काळ अजितदादांच्या सहवासात गेला. संघटनेत काम करण्याची संधी असो किंवा उद्योग मंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मार्गदर्शन असो, अजितदादांनी नेहमीच मोलाचे सहकार्य केले.''माझ्या राजकीय जीवनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अजितदादांनी मला महाराष्ट्रभर फिरण्याची संधी दिली. त्यामुळेच माझा चेहरा संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचला. माझे आणि त्यांचे संबंध केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते आपुलकीचे होते,'' असे सामंत यांनी सांगितले.

सर्वपक्षीय श्रद्धांजली

अलिबाग : आज सकाळीच अजित पवारांच्या अपघाती निधनाची बातमी येताच प्रचार थंडावला. सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचारासाठी पूर्वनियोजीत मेळावे, सभा रद्द करत अजित पवार यांच्या निधनानिमित्त आदरांजली वाहिली. हर्षवर्धन सपकाळ आणि जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत अलिबागच्या चोंढी येथील सभादेखील रद्द करण्यात आली. सकाळी महाविकास आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते एकत्र आले. एक जनसेवक हरपला असून महाराष्ट्र पोरका झाल्याची झाल्याची भावना राजाभाऊ ठाकूर यांनी व्यक्त केली. सर्वपक्षीय राजकीय कार्यक्रम, प्रचार सभा रद्द केल्याचे अमित नाईक यांनी सांगितले. श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अलिबाग येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयात सभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुतीची बिनविरोध सलामी

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत भाजप-शिंदे गटाची मुसंडी

लोकसत्ता वार्ताहर

सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीने मतदानापूर्वीच मोठी मुसंडी मारली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निवडणूक रणनीतीमुळे जिल्हा परिषदेचे ८, तर विविध पंचायत समित्यांचे १७ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत.

या यशामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर महायुतीचे, विशेषतः भाजपचे वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

५० सदस्य संख्या असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत महायुतीचे ८ उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. यात भाजपचे ७ आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या एका उमेदवाराचा समावेश आहे.

विजयी उमेदवार (जिल्हा परिषद)

भाजप -प्राची इस्वालकर (खारेपाटण), प्रमोद कामत (बांदा), सुयोगी रवींद्र घाडी (पडेल), अवनी अमोल तेली (बापर्डे), अनुराधा महेश नारकर (पोंगुर्ले), सावी गंगाराम लोके (किंजवडे), प्रमोद पुंडलिक रावराणे (कोळपे). शिवसेना (शिंदे गट): रुहिता राजेश तांबे (जाणवली).

पंचायत समित्यांमध्ये कमळ

जिल्ह्यातील १०० पंचायत समिती गणांपैकी १७ जागांवर महायुतीने बिनविरोध विजय मिळवला आहे. यामध्ये भाजपचे १६ आणि शिंदे गटाचा १ सदस्य आहे. प्रामुख्याने कणकवली आणि देवगड तालुक्यात प्रत्येकी ६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे.

तालुकानिहाय बिनविरोध निवडी

कणकवली : सोनू सावंत (वरवडे), हर्षदा वाळके (नांदगाव), महेश्वरी चव्हाण (जाणवली), संजना राणे (बिडवाडी), दिव्या पेडणेकर (हरकुळ बु.), सायली कृपाळ (नाटळ). देवगड : अंकुश ठूकरूल (पडेल), गणेश राणे (नाडण), संजना लाड (बापर्डे), समृद्धी चव्हाण (फणसगाव), शीतल तावडे (शिरगाव), ऋतुजा खाजनवाडकर (कोटकामते). साधना नकाशे (कोकिसरे-वैभववाडी), संकेत धुरी (आसोली-वेंगुर्ले), सीमा परुळेकर (अडवली-मालडी, मालवण), महेश धुरी (शेर्ले-सावंतवाडी).
शिवसेना (शिंदे गट): गणेश प्रसाद गवस (कोलझर-दोडामार्ग) बिनविरोध ठरले आहेत.

टीडब्ल्यूजे घोटाळा; संचालक संकेश घागला अटक

चिपळूण : हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करून गेल्या अनेक दिवसांपासून फरार असलेला टीडब्ल्यूजे कंपनीचा संचालक संकेश घाग याला अखेर चिपळूण पोलिसांनी अटक करत बेड्या ठोकल्या. या अटकेने चिपळूण तालुक्यात खळबळ उडाली असून फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदारांमध्ये न्याय मिळण्याची आशा पुन्हा जागी झाली आहे.

संकेश घाग याच्या अटकेचे वृत्त शहरात वाऱ्यासारखे पसरताच न्यायालय परिसरात गुंतवणूकदारांनी मंगळवारी मोठी गर्दी केली होती. अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेला हा आरोपी पोलिसांच्या सततच्या शोधमोहिमेनंतर अखेर हाती लागला. चिपळूण पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयात हजर केले. टीडब्ल्यूजे कंपनीच्या माध्यमातून आकर्षक परतावाच्या आमिष दाखवून हजारो गुंतवणूकदारांकडून हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक उकळण्यात आली होती. मात्र ठरलेल्या कालावधीनंतर ना परतावा मिळाला, ना मूळ रक्कम. यानंतर कंपनीचे एमडी समीर नार्वेकर, संचालक अचानक गायब झाले आणि गुंतवणूकदारांची मोठी फसवणूक झाल्याचे उघड झाले.

टीडब्ल्यूजेच्या फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदारांनी वेळोवेळी आंदोलन, मोर्चे, निवेदने देत न्यायासाठी आवाज उठवला. मात्र दीर्घकाळ कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने नाराजीचे वातावरण होते. अखेर चिपळूण पोलिसांनी तपासाला गती देत संकेश घाग याला शोधून काढले आणि अटक केली. या अटकेनंतर गुंतवणूकदारांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून, आता तरी आपले अडकलेले पैसे परत मिळावेत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आणखी कोणकोण सामील आहेत, कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचा नेमका मागोवा काय आहे, तसेच फसवणूक केलेली रक्कम कुठे गुंतवण्यात आली. याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. टीडब्ल्यूजे घोटाळ्यातील ही अटक महत्त्वाची मानली जात आहे.

हातखंबा शाळेजवळ सिमेंट ट्रक उलटल्याने महामार्ग ठप्प

लोकसत्ता प्रतिनिधी

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील हातखंबा शाळेजवळ आज बुधवारी सिमेंट वाहून नेणारा मोठा ट्रक उलटल्याने महामार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली. अपघातामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. याचा प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. पोलीस प्रशासनाने तीन ते चार तासांच्या अथक प्रयत्नाने येथील वाहतूक सुरळीत करण्यात यश मिळविले.

सिमेंटची पोती घेऊन जाणारा ट्रक हातखंबा शाळेच्या परिसरातील वळणावर आला असता चालकाचा ताबा सुटल्याने पलटी झाला. ट्रक रस्त्याच्या मधोमध आडवा झाल्याने महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.

या अपघातात ट्रकचे मोठे नुकसान झाले असले तरी सुदैवाने चालक आणि क्लिनर सुखरूप आहेत. अपघाताच्या वेळी आसपास अन्य कोणतेही वाहन किंवा पादचारी नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. दरम्यान, महामार्गावर दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत सध्या संथ गतीने एकेरी वाहतूक सुरू केली आहे. क्रेनच्या साहाय्याने अपघातग्रस्त ट्रक बाजूला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. लवकरच वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. स्थानिक पोलीस आणि महामार्ग पोलीस घटनास्थळी दाखल होवून वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले. प्रवाशांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले. तसेच पोलीस प्रशासनाने तीन ते चार तासांच्या अथक प्रयत्नाने येथील वाहतूक सुरळीत करण्यात यश मिळविले.

विणीसाठी ऑलिव्ह रिडले कासव श्रीवर्धन किनाऱ्यावर

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

श्रीवर्धन : विणीच्या हंगामासाठी ऑलिव्ह रिडले कासव श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत मादी कासव अंडी घालण्यासाठी किनाऱ्यावर येत असतात. या कासवांच्या संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

ऑलिव्ह रिडले कासवाची मादी अंडी घालण्यासाठी अनेकदा त्याच समुद्रकिनाऱ्यावर परततात, असे भारतीय वन्यजीव संस्थान यांच्या निष्कर्षातून स्पष्ट झाले आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील किनारपट्टीवर मादी कासव अनेक वर्षे विणीच्या हंगामात येत असतात. ऑलिव्ह रिडले कासव रात्रीच्या वेळी समुद्रकिनाऱ्यावर येऊन वाळूत साधारण दिड ते दोन फूट खोल खड्डा खणून १०० ते १५० अंडी घालते.अंडी वाळूने झाकून ती पुन्हा समुद्रात निघून जाते ती कायमची.अंडी वाळूत नैसर्गिकरीत्या उबतात. अंड्यांच्या उबवणी साठी लागणारे तापमान वाळूच्या तापमानावर अवलंबून असते.परंतु , अनेक वेळा भुकेले श्वान वाळू उकरून अंडी बाहेर काढीत फोडतात तसेच किनाऱ्यावरील मानवी वर्दळ यामुळे वाळू दबून अंडी फुटण्याचा धोका उत्पन्न होण्याची शक्यता असते.या कारणास्तव ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन होणे गरजेचे आहे. श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर, मारळ आणि दिवेआगर या किनाऱ्यावर ऑलिव्ह रिडले मादी कासव हंगामात विणीसाठी दरवर्षी येत असतात. ऑलिव्ह रिडले कासव जेव्हा विणीसाठी येतात तेव्हा तो परिसर हंगामापुरता 'रेड झोन' म्हणून घोषित करावा व त्या परिसरात कुंपण टाकावे. ओल्या वाळूवरील मानवी वर्दळ व सॅन्ड बाईक यामुळे वाळू टणक होते. परिणामी मादी कासव अशा ठिकाणी येणे टाळतात. योग्य उपाययोजना आखल्यास संवर्धन होऊ शकेल, कासव मित्र शैलेंद्र ठाकूर म्हणाले.

> **ऑलिव्ह रिडले प्रजातीचे कासव मोठ्या संख्येने अनेक किनाऱ्यांवर विणीच्या हंगामासाठी येत असतात. त्यांना रायगडमध्ये 'माहेरवाशिणी' संबोधले जाते.**

'माहेरवाशिणी'

ऑलिव्ह रिडले कासव मादींना प्रेमाने 'माहेरवाशिणी' म्हणतात. ऑलिव्ह रिडले कासवांची मादी अंडी घालण्यासाठी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून नेमकी त्याच किनाऱ्यावर येते, जिथे तिचा स्वतःचा जन्म झाला आहे. ज्याप्रमाणे एक मुलगी लग्नानंतर काही काळासाठी आपल्या माहेरी येते, त्याचप्रमाणे या कासव माद्या प्रजननाच्या काळात किनाऱ्यावर येतात. हा 'परतीचा प्रवास' त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. कासव मित्र , स्थानिक आपुलकीने अंड्यांचे संरक्षण, संवर्धन करतात आणि पिल्ले अंड्यातून बाहेर आल्यावर त्यांना सुरक्षितपणे समुद्रात सोडतात. या कारणास्तव ऑलिव्ह रिडले मादी कासवाला 'माहेरवाशीण' म्हटले जाते.

सव्वा कोटीची सायबर फसवणूक

रत्नागिरी : बेंगळुरू पोलीस व नवी दिल्ली येथील सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून तसेच डिजिटल अरेस्ट केल्याचे सांगत एका व्यक्तीची तब्बल १ कोटी २३ लाख रुपयांची सायबर फसवणूक केल्याप्रकरणी रत्नागिरी सायबर पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. संबंधित आरोपीने फिर्यादी यांना त्यांच्या कॅनरा बँक, माटुंगा (मुंबई) येथील खात्यातून ३ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची भीती घातली. या प्रकरणात 'डिजिटल अरेस्ट' केल्याचे सांगत चौकशीच्या नावाखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ ते १९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत वेळोवेळी पैशांची मागणी करून एकूण १ कोटी २३ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार रत्नागिरी सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तपासादरम्यान बँकांकडून प्राप्त आर्थिक माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवण्यात आली. त्यानंतर सायबर पोलिसांचे पथक मुंबई व ठाणे येथे रवाना करण्यात आले. स्थानिक माहितीच्या आधारे मुंबई येथून आरोपीला २३ जानेवारी २०२६ रोजी ताब्यात घेण्यात आले. त्यास न्यायालयासमोर हजर केले असता चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर करण्यात आली आहे.

ही कारवाई नितीन बगाटे व बी. बी. महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलीस ठाण्याच्या स्मिता सुतार, संदीप नाईक, सौरभ कदम, रोहन कदम आणि निलेश शेलार यांनी केली.

करिअर वृत्तांत

पुस्तके ही संस्कृतीमधील दुवे सांधण्याचे माध्यम आहेत.
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
तत्त्वज्ञ, भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती

स्पर्धा परीक्षेच्या प्रांगणात
यूपीएससी
डॉ. सुशील बारी

पॉलिटी - नियोजन

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आजच्या लेखात पॉलिटी या विषयाचे ३० दिवसांचे नियोजन बघणार आहोत . पॉलिटी हा विषय कापरासारखा असून त्याची वारंवार उजळणी करणे अपेक्षित आहे नाही तर आपण पहिल्यांदाच वाचतोय अशी स्थिती निर्माण होते . त्यातील कलमे, घटना दुरुस्त्या आपल्याला आठवत नाहीत .

यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील
पॉलिटीचे महत्त्व लक्षात घेता यासाठी खालीलप्रमाणे आपण नियोजन करू शकतो.

हे ३० दिवसांचे नियोजन करताना असे गृहीत धरले आहे की, तुम्ही याआधी किमान एकदा 'पॉलिटी एनसीईआरटी व इंडियन पॉलिटी - एम. लक्ष्मीकांत' ही पुस्तके वाचलेली असतील. यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी नियोजन करताना अधिकाधिक गुण मिळवून देणारे घटक, रिव्हीजन व गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिका यांचा विचार करून आपण अभ्यास करणार आहोत.

प्रत्येक घटकाचा अभ्यास करताना त्यातील तथ्ये, व्यक्तींची नावे (विशेषतः समित्यांच्या बाबतीत), कलमे, घटनादुरुस्त्या व संकल्पना समजून घ्या. केवळ वाचन वा रट्टा आपल्याला नको असून राज्यघटनेची रचना व महत्त्व समजून घेता यायला हवे. सध्याचे पूर्वपरीक्षेतील प्रश्न बघता आपण विषय समजून घेणे अपेक्षित आहे. तसेच प्रत्येक दिवसाच्या घटकांवर किमान ५० एमसीक्यू तुम्ही सोडविले पाहिजेत.

५ दिवस (१ ते ५) : संविधानाची चौकट व तत्त्वज्ञान
दिवस - १
- संविधान निर्मिती
- संविधान सभा
- संविधानाची वैशिष्ट्ये
- प्रास्ताविका

दिवस - २
- संघ व त्याचे प्रदेश (कलम १-४)
- नागरिकत्व (कलम ५-११)

दिवस - ३
- मूलभूत हक्क (कलम १२-३५)
- वाजवी निर्बंध
- लेखी आदेश रिटस् (अर्थ, व्याप्ती, फरक)

दिवस - ४
- राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम ३६-५१)
- मुलभूत कर्तव्ये (कलम ५१अ)
- मुलभूत हक्क व मुलभूत कर्तव्ये यांची तुलना

दिवस - ५
- संविधान दुरुस्ती (कलम ३६८)
- दुरुस्त्यांचे प्रकार
- महत्त्वाच्या संविधान दुरुस्त्या उदा. ४२ वी, ४४ वी, ५२ वी, ६१ वी, ७३ वी, ७४ वी, ८६ वी, १०१ वी इ.

५ दिवस (६ ते १०) : केंद्र सरकार
दिवस - ६
- राष्ट्रपती : निवडणूक, अधिकार, व्हेटो, पदच्युती
- उपराष्ट्रपती

दिवस - ७
- पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ
- कॅबिनेट विरुद्ध मंत्रिपरिषद
- अटर्नी जनरल

दिवस - ८
- संसद : रचना, अधिवेशन, संसदीय साधने
- कायदे निर्मिती प्रक्रिया

दिवस - ९
- संसदीय विशेषाधिकार
- अर्थसंकल्प, मनी बिल, वित्तीय विधेयक
- संसदीय समित्या

दिवस - १०
- सर्वोच्च न्यायालय : अधिकारक्षेत्र, न्यायाधिश, न्यायिक पुनरावलोकन
- न्यायिक सक्रियता विरुद्ध संयम - इथे फरक व अपवादांवर विशेष लक्ष द्या.

५ दिवस (११ ते १५) : राज्य सरकार व संघराज्य व्यवस्था
दिवस - ११
- राज्यपाल : नेमणूक, अधिकार, स्वविवेकाधिकार
- मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद

दिवस - १२
- राज्य विधानमंडळ
- उच्च न्यायालय : अधिकार व अधिकारक्षेत्र

दिवस - १३
- केंद्र - राज्य संबंध
- विधीमंडळ, प्रशासकीय व आर्थिक संबंध

दिवस - १४
- आंतरराज्य संबंध
- संघराज्य व्यवस्था, सहकारी व स्पर्धात्मक संघराज्यवाद

दिवस - १५
- आणीबाणी तरतुदी (राष्ट्रीय, राज्य, आर्थिक)
- मूलभूत हक्कांवरील व संघराज्य रचनेवरील परिणाम
- यूपीएससीने आणीबाणी व राज्यपाल यांचे संयुक्त प्रश्न विशेषतः विचारले आहेत.

५ दिवस (१६ ते २०): स्थानिक स्वराज्य संस्था व घटनात्मक संस्था
दिवस - १६
- पंचायत राज (७३ वी दुरुस्ती)
- नगरपालिका (७४ वी दुरुस्ती)

दिवस - १७
- निवडणूक आयोग
- यूपीएससी, राज्य लोकसेवा आयोग

दिवस - १८
- नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, वित्त आयोग
- जीएसटी परिषद

दिवस - १९
- राष्ट्रीय आयोग (एससी/एसटी /ओबीसी/महिला/अल्पसंख्याक)

दिवस - २०
- अनुसूचित क्षेत्रे व जमातींसाठी विशेष तरतुदी
- पाचवी व सहावी अनुसूची

५ दिवस (२१ ते २५): असंवैधानिक संस्था व विशेष विषय
दिवस - २१
- वैधानिक संस्था : सेबी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग
- घटनात्मक विरुद्ध वैधानिक विरुद्ध कार्यकारी संस्था यातील फरक

दिवस - २२
- न्यायाधिकरणे
- पक्षांतरविरोधी कायदा

दिवस - २३
- राजभाषा
- राष्ट्रीय चिन्हे
- भाषेसंबंधी घटनात्मक तरतुदी

दिवस - २४
- राजकीय पक्ष
- दबाव गट
- निवडणूक कायदे

दिवस - २५
- सहकारी संस्था
- जनहित याचिका
- अध्यादेश काढण्याचा अधिकार

५ दिवस (२६ - ३०) : संपूर्ण पुनरावृत्ती व चाचण्या
दिवस २६ व २७
- संपूर्ण पॉलिटी रिव्हीजन

दिवस - २८
- १०० प्रश्नांची मॉक टेस्ट व त्याचे विश्लेषण

दिवस - २९
- मागील १५ वर्ष - गतवर्षीच्या प्रश्नांचे विश्लेषण

दिवस - ३०
- पुढील बाबींची उजळणी : कलमे, संस्था, समित्या, घटनादुरुस्त्या

याप्रमाणे पुढील ३० दिवसांसाठी दररोज ४ तास आपण पॉलिटीसाठी दिले तर आपले संपूर्ण पॉलिटी एक महिन्यात तयार होईल. तसेच दररोजचे टार्गेट पूर्ण झाल्यावर १५ ते २० मिनिटे तुम्ही त्यातील महत्त्वाच्या बाबींची उजळणी करायला हवी. शब्दरचनेवर लक्ष द्या. यूपीएससी प्रश्न विचारताना शब्द रचनेचे सापळे लावते तेव्हा आपली पकड अचूक शब्दरचनेवर असावी. पॉलिटीचा अभ्यास करताना स्रोत कमी ठेवून जास्तीत जास्त उजळणी आणि जास्तीत जास्त एमसीक्यू सोडवा.

sushilbari10@gmail.com

नोकरीची संधी
सुहास पाठील

एनएचएआयमध्ये संधी

● **नॅशनल हायवेज ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज) डेप्युटी मॅनेजर (टेक्निकल) पदांची GATE-२०२५ स्कोअरवर आधारित थेट भरती.** पदाचे नाव - डेप्युटी मॅनेजर (टेक्निकल).

एकूण रिक्त पदे - ४० (अजा - ५, अज - २, इमाव - ९, ईडब्ल्यूएस - ४, खुला - २०) (प्रत्येकी १ पद अपंग कॅटेगरी - SLD/ MI आणि MD साठी राखीव)

वेतन श्रेणी - पे-लेव्हल - १० (रु. ५६,१०० १,७७,५००) अंदाजे वेतन दरमहा रु. १.१३ लाख

वयोमर्यादा - (९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी) ३० वर्षे

पात्रता - (९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी) सिव्हील इंजिनीअरिंग पदवी आणि सिव्हील इंजिनीअरिंग डिसिप्लिनमधील गेट २०२५ स्कोअर.

निवड पद्धती - शॉर्ट लिस्टेड उमेदवारांमधून इंटरॅक्शन/ इंटरव्ह्यू घेवून अंतिम निवड केली जाईल. शंकासमाधानासाठी NHAI च्या आयटी डिपार्टमेंट टीमशी ०११-२५०७४१००/ २५०७४२०० विस्तार क्र. १०२८ वर किंवा ई-मेल - वर संपर्क साधा.ऑनलाइन अर्ज http://www. nhai. gov. in या संकेतस्थळावर वर ९ फेब्रुवारी २०२६ (१८.०० वाजे)पर्यंत करावेत.

आयओसीएलमध्ये प्रशिक्षणार्थींची भरती

● **इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि. (IOCL) (भारत सरकारचा एक उपक्रम). IOCL आपल्या ५ झोन्समधील पाइपलाइन डिव्हीजन्समध्ये ३९४ टेक्निकल आणि नॉन-टेक्निकल ट्रेड ॲप्रेंटिस पदांची भरती.**
ट्रेड व झोननिहाय रिक्त पदे - वेस्टर्न रिजन पाइपलाइन्स (WRPL) - १३६ पदे; ईस्टर्न रिजन पाइपलाइन्स (ERPL) - १०१ पदे; नॉदर्न रिजन पाइपलाइन्स (NRPL) - ५४ पदे; सदर्न रिजन पाइपलाइन्स (SRPL) - ४० पदे; साऊथ ईस्टर्न रिजन पाइपलाइन्स (SERPL) - ६३ पदे. (WRPL मध्ये महाराष्ट्र (अहमदनगर, मनमाड आणि सोलापूर), गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यांतील IOCL च्या लोकेशन्सचा समावेश होतो.)

(१) टेक्निशियन ॲप्रेंटिस - मेकॅनिकल -
पात्रता - (दि. ३१ जानेवारी २०२६ रोजी) मेकॅनिकल/ ऑटोमोबाईल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा

(२) टेक्निशियन ॲप्रेंटिस - इलेक्ट्रिकल -
पात्रता - इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग डिप्लोमा.

(३) टेक्निशियन ॲप्रेंटिस - टेली कम्युनिकेशन अँड इन्स्ट्रूमेंटेशन -
पात्रता - इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन/ इन्स्ट्रूमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनीअरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन /इलेक्ट्रॉनिक्स अँड रेडिओ कम्युनिकेशन/ इन्स्ट्रूमेंटेशन अँड प्रोसेस कंट्रोल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा.

(४) ट्रेड ॲप्रेंटिस - असिस्टंट ह्युमन रिसोर्स -
पात्रता - पूर्ण वेळ पदवी उत्तीर्ण.

(५) ट्रेड ॲप्रेंटिस - अकाऊंट्स -
पात्रता - कॉमर्समधील पूर्ण वेळ पदवी उत्तीर्ण.

(६) फ्रेशर ॲप्रेंटिससेस - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर -
पात्रता - किमान १२ वी उत्तीर्ण (परंतु अर्ज करण्याच्या दिवशी उमेदवार पदवीधर नसावा.)

(७) डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (स्किल सर्टिफिकेट होल्डर)
पात्रता - किमान १२ वी उत्तीर्ण (परंतु पदवीधर नसावा.) आणि डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट.

वयोमर्यादा - (३१ जानेवारी २०२६ रोजी) १८-२४ वर्षे. **अर्ज कसा करावा** - टेक्निशियन ॲप्रेंटिसेस आणि ट्रेड ॲप्रेंटिस (असिस्टंट ह्युमन रिसोर्स/अकाऊंटंट) साठी https:// nats. education. gov. in/ student register. php या NATS पोर्टलवर ट्रेड ॲप्रेंटिस - डेटा एन्ट्री ऑपरेटरसाठी https:// www. apprenticeshipindia. gov. in या NAPS पोर्टलवर आपले नाव रजिस्टर करावे. (त्यानंतर संबंधित NATS/ NAPS पोर्टलवर यूजर आयडी/ ई-मेल आयडी वापरून लॉगिन करावे आणि आयओसीएलचा एस्टॅब्लिशमेंट आयडी वापरून अर्ज करावेत. इंडियन ऑईल पाइपलाइन पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी.

वेस्टर्न रिजन पाईपलाईन्स (WRPL) संबंधित शंका wrplapprentice@indianoil. in या ई-मेल आयडीवर ट्रेड कोड लिहून पाठवाव्यात.

शंकासमाधानासाठी पोर्टलवरील FAQ पाहून घ्यावे.

विस्तृत जाहिरात https:// www. iocl. com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मैदानातील करिअर
डॉ. निखिल लाटे

स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट

आपण खेळाडूंना अंतिम रेषा ओलांडताना, विजयाचा आनंद व्यक्त करत उडी मारताना किंवा मैदानावर तासन्तास मेहनत करताना पाहतो, त्यांच्या कौशल्य आणि निर्धाराचे कौतुक करतो . पण प्रत्येक क्रीडा यशाच्या मागे एक टीम असते जी त्यांच्या कामगिरीला आकार देते . त्यात सर्वात महत्त्वाची आणि कमी ओळखली जाणारी व्यक्ती म्हणजे स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट .

स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग कोच हे मुख्य प्रशिक्षकानंतर मैदानावर दुसरे महत्त्वाचे व्यक्ती मानले जातात. स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंगचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शरीराला सर्वोत्तम कामगिरीसाठी तयार करणे आणि दुखापतीचा धोका कमी करणे. हे तज्ज्ञ जिमपुरते मर्यादित न राहता सर्वांगीण प्रशिक्षण कार्यक्रम रचतात,निरीक्षण करतात आणि मार्गदर्शन करतात. ते व्यायामशास्त्र, जीवयांत्रिकी शास्त्र आणि खेळाच्या खास गरजांचा समन्वय साधून खेळाडूंना शक्तिशाली, वेगवान, चपळ आणि सहनशील बनवतात.

उदाहरणार्थ, क्रिकेटरला बॅटिंग-बॉलिंगसाठी शारीरिक शक्ती, मॅरेथॉनरला सहनशक्ती व परिपूर्ण हालचाली लागतात - स्ट्रेंथ कोच हे प्रत्येक खेळाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गरजांनुसार शक्ती, गती, लवचिकता व सुधारणा (रिकव्हरी) यांचा समतोल साधतात.

शास्त्रोक्त मेहनतीचा मेळ

पारंपरिक फिटनेस ट्रेनर्सपेक्षा स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट शास्त्रीय तत्त्वांवर अधिक भर देतात. ते स्नायू, सांधे आणि ऊर्जा प्रणाली तणावाला कसा प्रतिसाद देतात हे अभ्यासतात. मोशन ॲनालिसिस, हार्ट-रेट मॉनिटरिंग आणि लोड मॅनेजमेंटसारखी साधने वापरून, ते प्रशिक्षण इतकेच वाढवतात की जेणेकरून त्याद्वारे खेळाडूंची प्रगती होईल, पण ओव्हरट्रेनिंग होणार नाही.

त्यांचे काम फक्त स्नायूबल वाढवण्यापुरते मर्यादित नाही.

पुढील कामांचाही समावेश होतो -
- सरावांद्वारे गती, चपळता वाढविणे.
- लवचिकता वाढवून दुखापती रोखणे.
- रिकव्हरी प्रोटोकॉल : स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग, विश्रांती - म्हणजे पूर्ण सुधारणा करणे.
- पीरियडायझेशन : स्पर्धेपूर्वी अनेक आठवड्यांचे प्रशिक्षण आखून, ज्यात प्रशिक्षण आठवडे आणि महिने यामध्ये रचले जाते, जेणेकरून मोठ्या स्पर्धेपूर्वी सर्वोत्तम कामगिरी करून खेळाडूला यशाच्या शिखरावर पोहोचवणे.

स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्टचे महत्त्व

दुखापती रोखणे हे स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्टचे सर्वात मोठे काम आहे. खेळांमधील दुखापती खेळाडूंचे करिअर संपवू शकतात, आणि योग्य कंडिशनिंगने त्यापैकी अनेक दुखापती टाळता येतात.

प्रशिक्षण कसे आणि कुठे?

बारावी नंतर तुम्ही स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट होण्याचा प्रवास सुरू करू शकता. त्यासाठी अनेक मार्ग आहेत -
- अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिनमधून भारतातील एक्सरसाइज सायन्स अकादमीद्वारे सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर (सीपीटी) कोर्स सारखा बेसिक ट्रेनर कोर्स करा. तुम्ही ऑस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट (एएससीए) मधूनही बेसिक कोर्स करू शकता - एएससीए लेव्हल १ आणि २
- बेसिक कोर्स केल्यानंतर तुम्ही नॅशनल स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग अकादमी (एनएससीए) मधून सर्टिफाइड स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट (सीएससीएस) सारखा स्पेशलाइज्ड कोर्स करू शकता. हे कोर्स भारतात ईएसए आणि इतर तत्सम संस्थांद्वारे आयोजित केले जातात.
- सीपीटी/एएससीएनंतर सामान्य लोकांना आणि सीएससीएस नंतर खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्याचा अनुभव मिळणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र आणि अनुभवाची एकत्रितपणे संबंधित नोकऱ्या मिळविण्यात आणि खेळाडूंसोबत काम करण्यास मदत होते.

स्थिरता देणारे स्नायू मजबूत करून, हालचालींच्या त्रुटी दुरुस्त करून आणि संतुलन सुधारून हे तज्ज्ञ स्नायू खेचणे, ताणणे, फाटणे आणि स्नायूंचा अतिवापर अशा समस्या कमी करतात.

याबरोबरच कामगिरी सुधारणा देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. १०० मीटर डॅशमध्ये काही मिलीसेकंद कमी करणारा धावपटू, किंवा फुटबॉलपटू अतिरिक्त वेळेतही स्टॅमिना टिकवणारा, हे सर्व काळजीपूर्वक तयार केलेल्या कंडिशनिंग कार्यक्रमामुळे शक्य होते.

भारतीय संदर्भ

भारतात, क्रीडा विज्ञान मुख्य प्रवाहात येत असल्याने या व्यवसायाला ओळख मिळत आहे. क्रिकेट फ्रँचायझी, फुटबॉल क्लब्स आणि ऑलिम्पिक प्रशिक्षण केंद्रे आता स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग तज्ज्ञांना खेळाडूंना सर्वोच्च स्वरूपात ठेवण्यासाठी नियुक्त करतात. विद्यापीठे आणि खासगी अकॅडमीदेखील विशेष अभ्यासक्रम देऊ लागल्या आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्रात इच्छुक तरुणांसाठी मार्ग तयार होत आहेत.

तरीही, सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता कमी आहे. अनेकजण त्यांना जिम ट्रेनर समजतात. दोन्ही भूमिका फिटनेसशी संबंधित असल्या तरी, स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट्सना शरीरशास्त्र, बायोमेकॅनिक्स आणि क्रीडा कामगिरीमध्ये प्रगत शिक्षण मिळालेले असते, त्यामुळे ते उच्च दर्जाच्या क्रीडेसाठी अत्यावश्यक ठरतात.

खेळाडूंपलीकडे...

मजेशीर बाब म्हणजे, त्यांचे कौशल्य फक्त व्यावसायिक खेळाडूंपुरते मर्यादित नाही. रिक्रिएशनल रनर्स, फिटनेस प्रेमी आणि अगदी कॉर्पोरेट कर्मचारी देखील संरचित कंडिशनिंग कार्यक्रमाचा लाभ घेतात. शारीरिक ठेवण सुधारून, दुखापतीचा धोका कमी करून आणि एकूण शारीरिक क्षमता वाढवून, हे तज्ज्ञ समाजात आरोग्यदायी जीवनशैलीला हातभार लावतात.

प्रभावी व्यवसाय

स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट हा फक्त हातात स्टॉपवॉच असलेला कोच नाही. ते शास्त्रज्ञ, नियोजक, प्रेरक आणि खेळाडूंच्या आरोग्याचे रक्षक आहेत. त्यांचे काम अनेकदा दुर्लक्षित राहते, पण त्यांच्याशिवाय अनेक क्रीडा यश शक्य झाले नसते.

म्हणून पुढच्या वेळी तुम्ही पदक विजेत्याला किंवा सामना जिंकणाऱ्या खेळाडूला दाद द्याल, तेव्हा हे लक्षात ठेवा की त्या गौरवाच्या क्षणामागे एक स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग स्पेशालिस्ट उभा आहे.

nikhil@prophysio.co.in
(लेखक क्रीडा शास्त्रज्ञ आणि फिजिओथेरपिस्ट आहेत.)

शब्दकोडे- ३२८

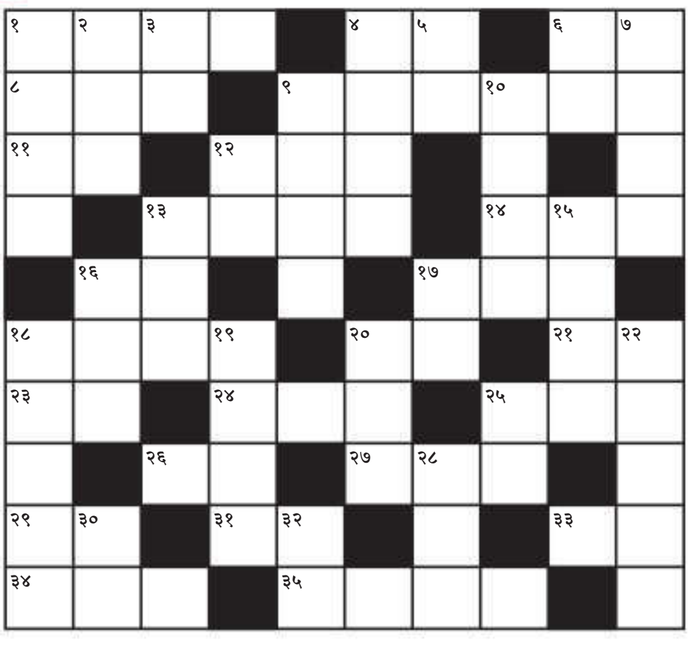

आडवी विधाने : (१) वेळ, आसमंत (४) या प्रकारचा, यासारखा (६) सोंगट्या, बुद्धिबळ ज्यावर मांडतात ते (८) घाई, गडबड (९) प्रतिज्ञा घेऊन (सांगणे) (११) शरीर, काया (१२) नाकात घालायचा दागिना (१३) सार्वभौम राजाची पदवी (१४) एक पालेभाजी (१६) 'आशिकी' चित्रपटाचा दिग्दर्शक (फक्त आडनाव) (१७) पायऱ्या असलेली विहीर (१८) पटकन, जलदीने (२०) म्हैसूरचा वाघ म्हणून ओळखला जाणारा - XX सुलतान (२१) मुलगी, तनया (२३) रान, जंगल (२४) नरम, मऊ (२५) जुन्या जमान्यातील प्रसिद्ध संगीतकार (२६) बारीक, कण (२७) खाष्ट, दुष्ट (२९) लोकांचा समुदाय (३१) मुनी, संन्यासी (३३) ढीग, रास (३४) दडून बसणे (३५) जय जय XXXX समर्थ

उभी विधाने : (१) आधाराविना (२) मुख, चेहरा (३) आजच्या आधीचा दिवस (४) बेअब्रू, बदनामी (५) रोगाची एकाच वेळी लागण होणे, सोबत (६) महाभारताच्या मुख्य १८ भागांपैकी प्रत्येक (७) आल्याचे कळवण्यासाठी दारावर केलेला आवाज (९) थंड करणे, शांत करणे (१०) प्राचीन काळापासून, पूर्वीपासून (१२) चाक (१३) खोड, दुर्व्यसन (१५) किंचित अंश, मागमूस (१६) सदन, गृह (१७) महात्मा गांधींचे टोपण नाव (१८) खारेपाणी, समुद्र (१९) मनोहर, सुंदर (२०) स्वातंत्र्य समरातील जहाल पक्षाचे नेते (फक्त आडनाव) (२२) सोन्याचा पर्वत (२५) व्याधी, आजार (२८) गंगा, भागीरथी (३०) खोटे बोलणे (३२) बाण, नदी – समुद्र यांचा किनारा

- चारू नानल

सुडोकू - ३२८

				६			३	
					४	१	६	
	२	१		५				७
							१	८
	६						४	
५	१							
३				७		६	८	
	८	७	३					
	१			२				

सुडोकू - ३२७ चे उत्तर

१	८	२	६	४	५	७	३	९
७	५	९	२	८	३	६	४	१
४	६	३	७	१	९	८	५	२
५	३	४	९	६	२	१	७	८
२	९	१	४	७	८	५	६	३
८	७	६	५	३	१	९	२	४
३	२	५	१	९	७	४	८	६
९	४	८	३	५	६	२	१	७
६	१	७	८	२	४	३	९	५

शब्दकोडे - ३२७ चे उत्तर

दि	वा	ळे		दि	वा	भी	त		कां
ल	त		कै	ला	स		र	ती	ब
खु		क		सा		अ	तू	ट	
ला	गो	पा	ठ		श	र	द		मो
स	पा	ट		स	ब	ब		आ	ज
	ळ		स्वै		न		ल	च	का
धि		तो	र	ड	म	ल		का	
मा	व	शी		च्यू		पं	खा		तु
	हा	स	रा		खिं	डा	र		र
गौ	ण		त्र	स्त		व	ट	व	ट

अजित पवार का जाना

बारामती के पास एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का आकस्मिक निधन सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं है, यह एक ऐसी क्षति है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उपजे शून्य की भरपायी आसान नहीं होगी। 66 वर्षीय 'दादा' का जाना उस समय हुआ, जब महाराष्ट्र में त्रिशंकु राजनीति आकार ले रही थी। सच कहें, तो एक नए प्रायोगिक दौर से गुजर रही थी। अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन से जुड़े 'कुशल प्रशासक' के रूप में पहचाना जाता था। कई बार सुबह छह बजे मंत्रालय पहुंचकर काम शुरू कर देने की उनकी शैली और कड़क मिजाज ने राज्य के नौकरशाहों व जनता के बीच उनकी 'डिलीवरी मैन' की छवि मजबूत बनाई थी। वह शरद पवार के भतीजे जरूर थे, पर उन्होंने अपनी खुद की सियासी सल्तनत खड़ी की थी। सिंचाई से लेकर वित्त मंत्रालय तक, उनका अनुभव राज्य के बजट और बुनियादी ढांचे पर अमिट छाप छोड़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पहचान उस धुरी की थी, जिसके इर्द-गिर्द पिछले ढाई दशकों के सत्ता समीकरण घूमते रहे।

अजित पवार की असामयिक मृत्यु के कई सशंकित निहितार्थ हैं। उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल उनकी पार्टी एनसीपी के नेतृत्व को लेकर है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार पार्टी की कमान संभालेंगी, ताकि 'पवार' नाम की विरासत बनी रहे या उनके बेटे पार्थ पवार को आगे लाया जाएगा या फिर कोई अन्य? उधर महायुति सरकार की अपनी चिंताएं हैं। अजित पवार वर्तमान भाजपा-शिंदे गठबंधन (महायुति) के एक मजबूत स्तंभ थे। वह इस गठबंधन के भीतर एक संतुलनकारी शक्ति भी थे। उनके जाने से गठबंधन की रणनीति पर असर पड़ेगा। भाजपा के लिए अजित पवार एक ऐसे सेतु थे, जो मराठा राजनीति और सहकारी क्षेत्र को साथ लेकर चलते थे। उनके बिना गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को बनाए रखना एक जटिल काम होगा। खास तौर से उस समय, जब प्रतिद्वंद्वी महाविकास अघाड़ी किसी अवसर की तलाश में हो।

पवार की मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी रिक्तता पैदा हुई है, वहीं इस हादसे से देश की विमानन सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

यह दुर्घटना भारत में विमानन सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है। ऐसे समय में, जब देश में हवाई सेवाओं के विस्तार का काम जोरों पर है और नई विमानन कंपनियां उड़ान अनुमति के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं, यह दुर्घटना एक चेतावनी की तरह है। इस हादसे के संदर्भ में हम यह कहकर संतोष भले कर लें कि 'विजिबिलिटी' पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के पास इसके भी किंचित जवाब हैं। देश में हवाई सेवाओं की दुर्दशा का एक कारण विजिबिलिटी मान भी लें, तो जो दुश्वारियां यात्रियों को हाल ही में 'इंडिगो' की हड़ताल के समय झेलनी पड़ीं, उनके लिए क्या कहेंगे? विमानों में तकनीकी खामियां, पायलटों की भर्ती में गैर-जिम्मेदाराना ढील, हजारों उड़ानों का निरस्त होना कोई आकस्मिक बात नहीं थी। इनके कारण थे, हवाई सेवाओं के संचालकों की बरसों से चली आ रही ढील व टालमटोल का रवैया। इससे भी बड़ी बात थी, उन महकमों की उदासीनता, जिनको इनकी निगरानी करनी थी। खास तौर पर वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले चार्टर्ड विमानों के रखरखाव व डीजीसीए के निगरानी तंत्र पर अब सवाल उठने लाजिमी हैं। यह हादसा सिर्फ एक राजनेता का अंत नहीं है, बल्कि हमारी विमानन नियामक संस्थाओं की जवाबदेही पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है। अब बिना वक्त गंवाए इसे सुधारने की कवायद होनी ही चाहिए।

सत्ता की हर चुनौती मिटाते शी जिनपिंग

जी जी द्विवेदी | सेवानिवृत्त मेजर जनरल

पीएलए में सफाई का उनका अभियान सिर्फ भ्रष्ट जनरलों को हटाने तक सीमित नहीं है, यह कम्युनिस्ट पार्टी व सेना पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की रणनीति भी है।

हाल ही में चीन से एक अहम खबर आई कि वहां के सबसे वरिष्ठ जनरल, पोलित ब्यूरो के सदस्य और देश के सर्वोच्च रक्षा निकाय- केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के उपाध्यक्ष झांग यूशिया व सीएमसी में 'जॉइंट ऑपरेशंस' के मुखिया जनरल ल्यू झेनली पर जांच बैठा दी गई है। इससे चीन के राजनीतिक-सैन्य हलकों में हंगामा खड़ा हो गया और चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वालों के बीच तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं।

चीन का पूरा प्रशासनिक और सैन्य ढांचा अलग तरह का है। पूरी दुनिया में देशों की सेनाएं होती हैं, लेकिन चीन में सेना की कमान कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। इस व्यवस्था को माओत्से तुंग ने सन् 1928 में लागू किया था। तब उन्होंने घोषणा की थी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की सशस्त्र शाखा होगी। इसका मतलब था कि संगीनों पर पूरी तरह से सीसीपी का नियंत्रण रहेगा। पीएलए और सीसीपी के बीच नाभिनाल संबंध है और यही वे दो स्तंभ हैं, जिन पर चीन का पूरा राजनीतिक ढांचा टिका हुआ है। जाहिर है, सीएमसी का अध्यक्ष सीसीपी के महासचिव के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता है। इन्ही दोनों पदों के जरिये कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति का पद केवल राजनीतिक-प्रोटोकॉल के लिए है। वर्तमान में शी जिनपिंग इन तीनों पदों पर काबिज हैं।

जब शी जिनपिंग ने 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी की पांचवीं पीढ़ी के नेता के रूप में सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान चलाया। इस मुहिम के तहत अब तक दो लाख से अधिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। मकसद साफ है, राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करना और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना, ताकि राजनीतिक और सैन्य ढांचे में पूर्ण वफादारी सुनिश्चित की जा सके।

जिनपिंग ने पीएलए को आधुनिक बल बनाने के लिए अभूतपूर्व सैन्य सुधार किए। युद्ध सिद्धांतों को लगातार परिष्कृत किया गया, सेना के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की पहल की गई। इसके लिए रक्षा खर्च में सालाना दहाई अंकों की वृद्धि की जाती है। केवल अपने वफादारों को शीर्ष पदों पर पदोन्नति देकर जिनपिंग ने पीएलए पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सीसीपी की छवि को साफ रखने और अनुशासन बनाए रखने की आड़ में समय-समय पर सेना के आला अधिकारियों को हटाया जाता रहा है। शुरू में माओ ने कई प्रमुख सैन्य जनरलों को हटाया, जिनमें सबसे खास मार्शल लिन बियाओ के साथ उनके उत्तराधिकारी और रक्षा मंत्री जनरल पेंग देहुआई थे। यहां तक कि देंग जियाओ पेंग ने भी माओ के वफादार जनरलों को हटाया। उस समय खासकर 'गैंग ऑफ फोर' समेत कई सैन्य जनरल हटाए गए।

साल 2019 में खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करने के बाद जिनपिंग ने दर्जनों वरिष्ठ जनरलों और रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों को हटाया है। ताजा लहर 2023 से चल रही है। हालांकि, इस प्रक्रिया में अनुभवी, पुराने जनरल और जिनपिंग के लंबे समय से सहयोगी झांग यूशिया के खिलाफ जांच की कार्यवाही चौंकाने वाली बात है। झांग और ल्यू पर जांच की घोषणा पिछले हफ्ते जारी किए गए 30 सेकंड के वीडियो द्वारा की गई। इसके बाद, पीएलए डेली के संपादकीय में झांग और ल्यू पर सीएमसी अध्यक्ष की सर्वोच्च जिम्मेदारी वाली व्यवस्था को गंभीर रूप से कुचलने और कमजोर करने का आरोप लगाया गया। यह बताता है कि दोनों शी जिनपिंग के लिए खतरा बन गए थे। झांग पर अधिकारियों की पदोन्नति में रिश्वत लेने के अलावा चीन के परमाणु हथियारों से संबंधित मुख्य तकनीकी डेटा अमेरिका को लीक करने का भी आरोप है। संयोग से, झांग भी जिनपिंग की तरह एक 'प्रिंसलिंग' हैं, यानी एक क्रांतिकारी के बेटे, जिनके जिनपिंग के साथ एक पीढ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं। दोनों के पिता चीन का गृहयुद्ध एक साथ लड़ चुके हैं।

साफ है, चीन की सेना में भ्रष्टाचार बहुत गहरे तक फैला है और शीर्ष स्तर पर भारी कुप्रबंधन है। जिनपिंग को शायद एहसास हो गया है कि घर की सफाई में पूरी पीढ़ी के नेतृत्व को साफ करना होगा। सीएमसी में शीर्ष स्तर के कई पदों के खाली हो जाने से पीएलए को रणनीतिक योजना बनाने, खरीद और कमांड की निरंतरता को बनाए रखने में बाधा आ सकती है। इससे सेना के आधुनिकीकरण की गति धीमी पड़ सकती है और ताइवान में संभावित जटिल ऑपरेशनों की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि जिनपिंग प्रमुख पदों को भरेंगे और महत्वपूर्ण भूमिकाएं दूसरी पंक्ति के अपने वफादार युवा अधिकारियों को सौंपेंगे, जिससे कमांड ढांचा सीधे उनके नियंत्रण में आ जाएगी।

घरेलू मोर्चे पर इस शुद्धिकरण अभियान के राजनीतिक व रणनीतिक प्रभाव होंगे। ये सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण का संकेत देते हैं, जिससे पार्टी और सेना के बीच का विभाजन पूरी तरह से मिट जाएगा। जिनपिंग के 'कोर' के रूप में उभरने और खुद ऑपरेशनल नियंत्रण संभालने के बाद पोलित ब्यूरो और सीएमसी- दोनों में सामूहिक नेतृत्व का ढांचा कमजोर पड़ गया है। पीएलए के ऊपरी पदों की यह उथल-पुथल चीनी नेतृत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा आक्रामक होने के लिए उकसा सकती है और ताइवान या समुद्री/भूमि सीमा विवाद जैसे तनाव वाले क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीएलए की योजनाओं से सावधान रहना होगा।

शी जिनपिंग का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सफाई अभियान सिर्फ भ्रष्ट जनरलों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चीन की शक्तिशाली सेना पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे यह भी साफ होता है कि पार्टी और सेना पर जिनपिंग का पूरा नियंत्रण है और वह अजेय हैं। सेना के शीर्ष स्तर पर आमूलचूल बदलाव तालमेल को और बेहतर कर सकता है, लेकिन यह सैन्य तैयारी, कमांड और संस्थागत प्रभाव को बाधित कर सकता है, जिससे भविष्य में चीन की रणनीतिक स्थिति प्रभावित होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए स्मार्ट उपभोक्ता बनिए

प्रांजल शर्मा | डिजिटल नीति विशेषज्ञ

देश भर में साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए लोग अपने डिजिटल लेन-देन में स्मार्ट बन रहे हैं। महानगरों के साथ-साथ दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में ग्राहक अब रोजाना के डिजिटल लेन-देन के लिए अलग बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ताकि उनका मुख्य खाता सुरक्षित रहे। भारत में करोड़ों उपभोक्ता अब डिजिटल भुगतान सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी के एक अनुमान के मुताबिक, वित्तीय साल 2025 में 299 खरब रुपये का डिजिटल भुगतान हुआ, जिसके 2030 में 907 खरब तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी पांच साल में लगभग तीन गुना।

जैसे-जैसे भारत में डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, इसमें धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ रहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर भारत में वित्तीय वर्ष 2020 से 2024 के बीच 'साइबर फ्रॉड' के 5,82,000 मामलों में कुल 3,207 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। धोखाधड़ी की घटनाओं और इनके कारण होने वाले नुकसान, दोनों में साल-दर-साल काफी तेज बढ़ोतरी हो रही है। साल 2023 में जहां ऐसी 75,800 घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2024 में ये बढ़कर 2,92,800 की संख्या पर पहुंच गईं। वहीं, 2023 में हुई नुकसान राशि 421.4 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 2,054.6 करोड़ रुपये हो गई। ये आंकड़े डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते जोखिम को दिखाते हैं।

साल 2024 में साइबर धोखाधड़ी की लगभग 2,92,800 घटनाओं में ग्राहकों को 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ।

बैंकिंग उद्योग के एक आकलन के अनुसार, ज्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी कम मूल्य के होते हैं। जैसे-जैसे 'डिजिटल फ्रॉड' के मामले बढ़ रहे हैं, ग्राहक या उपभोक्ता अपने मुख्य बचत खाते या वेतन खाते को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने को लेकर सावधान हो रहे हैं। कई ग्राहक अब रोजाना के लेन-देन के लिए 'पेमेंट्स बैंक' में दूसरा 'अकाउंट' बना रहे हैं। वे अपने मुख्य खाते से थोड़ी रकम 'डिजिटल पेमेंट्स बैंक अकाउंट' में ट्रांसफर कर लेते हैं। इससे उनका मुख्य खाता सुरक्षित रहता है, जबकि पेमेंट बैंक अकाउंट से डिजिटल धोखाधड़ी की आशंका बहुत कम होती है।

पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों से रोजाना इस्तेमाल होने वाले कम राशि के लेन-देन के लिए दूसरे अकाउंट का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पेमेंट बैंक देश के उन इलाकों के डिजिटल समावेशीकरण के लिए शुरू किए गए थे, जहां बैंक नहीं हैं। पेमेंट्स बैंक अब अपने बिजनेस मॉडल की वजह से सभी तबके के ग्राहकों के लिए एक सही विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। पेमेंट बैंक खातों की एक और खास बात यह है कि इनमें न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं होती। ये यूपीआई के साथ जुड़े होते हैं और डेबिट कार्ड भी देते हैं। धोखाधड़ी होने पर, खाता तुरंत संदिग्ध कोशिशों को ब्लॉक कर देता है। यही नहीं, इस्तेमाल न करते समय ग्राहक इस खाते को रोक सकते हैं और भुगतान पर रोजाना की एक सीमा भी लगा सकते हैं।

देश में पेमेंट बैंकों के करोड़ों बचत खाता धारक हैं। उधर, आरबीआई व बैंकिंग उद्योग धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले अवैध खातों को हटाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच पूरी तरह आरबीआई के मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी है, जो डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ सक्रिय है। आरबीआईएच का एआई से लैस तंत्र 'म्यूलहंटर.एआई' हर महीने लगभग 20,000 अवैध बैंक खातों का पता लगा रहा है। ये अवैध खाते धोखाधड़ी वाली राशि के हस्तांतरण में अहम बिचौलिया की भूमिका निभाते हैं।

म्यूलहंटर का एआई मॉडल 20 से भी ज्यादा बैंकों के लेन-देन के पैटर्न पर नजर रख रहा है। आरबीआईएच के सीईओ साहिल किनी के मुताबिक, 'दो महीने में अवैध खातों की शिनाख्त करने की संख्या काफी बढ़ जाएगी। पिछले कुछ महीनों में 85,000 से ज्यादा ऐसे खातों का पता लगाया गया है और उनकी सटीकता 85 से 90 प्रतिशत के बीच है।'

भारतीय ग्राहक व उपभोक्ता यदि डिजिटल बैंकिंग और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का स्मार्ट तरीका अपनाएं, तो देश में डिजिटल धोखाधड़ी को काबू करने में मदद मिल सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

बुद्ध खेल देखते रहे

बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बुद्ध रुककर उन्हें देखने लग जाते हैं। बच्चों ने रेत के घर बनाए हैं। वे लड़ रहे हैं आपस में। कोई कहता है, यह मेरा है। दूसरा कहता है, यह तेरा है, तो दूर रख। अपने मकान को मेरे मकान के करीब मत ला। अपने-अपने रेत के मकान की चारों ओर उन्होंने रेखाएं खींच रखी हैं कि यह मेरा आंगन है, यह मेरा बगीचा है, यह मेरी सीमा है; इसके भीतर कोई न आए।

फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं। एक बच्चे का पैर किसी के मकान पर पड़ गया, तो वह उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसने बाकी को भी पुकारा- भाइयो, तुम भी आओ और इसको दुरुस्त करो, इसको राह पर लाओ। बाकी भी आ गए। न्याय का सवाल है। फिर उन्हें अपना मकान भी बचाना था। सबने मिलकर उस लड़के की खूब मरम्मत की। सांझ हो गई, तो किसी ने जोर से आवाज दी, बच्चो, अब घर चलो, तुम्हारी माताएं राह देख रही हैं। बच्चों ने देखा कि सूरज ढल गया है। वे खेल में इतने तल्लीन हो गए थे कि भूल ही गए थे कि अब घर लौटने का वक्त आ गया।

बुद्ध चुपचाप बच्चों के खेल को देखते रहे। वे बच्चे, जो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, एक-दूसरे से अपने-अपने मकान की रक्षा कर रहे थे, जिन्होंने एक बच्चे की कुटाई कर दी थी, वे खुद अपने मकानों पर कूदने लगे। उन्होंने अपने मकान खुद ही गिरा दिए। खूब हुल्लड़ मचाया और जब सब मकान गिर गए, सारी दीवारें गिर गईं, सब सीमाएं असीम में खोकर एक हो गईं, तब सब अपने-अपने घर की तरफ भागे। मां की याद आ गई। अब घर जाना है, सांझ हो गई है।

बुद्ध ने दूसरे दिन अपने भिक्षुओं से कहा- 'ठीक ऐसा ही संसार है। रेत के घर-सा। मेरा-तेरा, बड़ी लड़ाई, बड़ी कलह, बड़ा द्वेष, बड़ी ईर्ष्या, बड़े संघर्ष, युद्ध, अदालतें और फिर एक दिन सांझ हो आती है। सूरज ढल जाता है, मौत आ जाती है। घर से खबर आती है और फिर जाना पड़ता है। सब यहीं पड़ा रह जाता है। रेत के घर रेत में ही पड़े रह जाते हैं। तो जीवन को एक खेल से अधिक न जानो। खेल की तरह इस जीवन को खेला, तो पूरा आकाश तुम्हारा है। इसके प्रति गंभीर हुए कि स्वयं को खुद ही बंधनों में बांध लिया।'

जिसे यह समझ में आ जाए कि जीवन एक खेल है, उसका सारा तनाव समाप्त हो जाता है। फिर खेल में उसे पूरा मजा आता है। अफसोस! हम ऐसे पागल हैं कि खेल में भी तनाव बना लेते हैं।

जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि हमारा जीवन सिर्फ एक खेल है, सारा तनाव समाप्त हो जाएगा। फिर खेल में पूरा मजा आएगा। अफसोस! हम सब ऐसे पागल हैं कि खेल में भी तनाव बना लेते हैं। तुमने देखा, दो आदमी ताश खेल रहे हों, तो कैसा सिर भारी कर लेते हैं, लड़ने-मारने को उतारू हो जाते हैं? लोग खेल में इतनी गंभीरता ले लेते हैं और साधक वही है, जो गंभीरता को भी खेल में ले।

ओशो

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 29 जनवरी, 1951

राष्ट्रपति की अपील

पिछले सप्ताह 26 जनवरी को हमारे भारतीय गणराज्य की प्रथम वर्षगांठ देश भर में तथा विदेशों में भी बड़ी सादगी से किन्तु उत्साहपूर्वक मनाई गई। ऐसे समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर युद्ध की छाया मंडरा रही है और देश में अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं जनता का जीवन कठिन बना रही हों, तो राष्ट्र के धन का अपव्यय और व्यर्थ का ठाटबाट गरिमा नहीं देता। लेकिन राष्ट्र की प्रगति में गणराज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है और इस राष्ट्रीय त्यौहार को हम जितने भी उत्साह से मनायें उतना कम है।

इस अवसर पर हमारे राष्ट्रपति ने जनता से अपील की कि वह देश के सम्मुख भीतर और बाहर से आई कठिनाइयों का सामना करने के लिए बद्धपरिकर हो जायें और जनता के प्रत्येक वर्ग मजदूरों, किसानों, सेवकों, सिपाहियों, बुद्धिजीवियों तथा उद्योगपतियों का अभिनन्दन करते हुए उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई, जो एक वर्ष पूर्व सबने गणराज्य की न्याय, स्वतंत्रता, समता और बन्धुता का मन्दिर बनाने की की, तथा उसे पूरा करने के लिए सबको आह्वान किया। राष्ट्रपति की यह चेतावनी अर्थपूर्ण है कि हम अपने इस घोषित उद्देश्य में तभी सफल होंगे, जब हम राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और विशेषतः आर्थिक क्षेत्र में अपने को सृजनात्मक कार्य और सामूहिक प्रयास में अनवरत लगाये रखें। हमारी कामना है कि अगले वर्ष जब यह राष्ट्रीय त्यौहार आये, तो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर शान्ति समृद्धि का सूर्य चमक रहा हो और सब देशवासी अबकी बार से भी अधिक उत्साह से उसे मनायें।

प्रधानमंत्री की यूरोप से वापसी : प्रधानमंत्री लन्दन और पेरिस आदि में तीन सप्ताह व्यतीत करके रविवार को स्वदेश लौट आये। राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह ऐसे समय यूरोप पहुंचे थे, जबकि युद्ध और शान्ति का प्रश्न हवा में अधर लटका हुआ था। उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के नेताओं को निर्भीकतापूर्वक यह चेतावनी दी कि वे युद्ध की भाषा का उपयोग करके शांति की खोज न करें। जो लोग दुनिया को एक और महायुद्ध की आग में ढकेलने के लिए उतावले हो रहे हैं, उसको लक्ष्य करके नेहरू जी ने कहा है कि किसी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि संसार में छिड़ने वाले किसी युद्ध के परिणामस्वरूप उसे या उसके देश को कोई लाभ पहुंच सकता है।

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

किसी भी शोध संगठन की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग होते हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन ही उसकी वास्तविक शक्ति हैं। उन्हें सीखने के अवसर देने होंगे, नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपनी होगी और यह विश्वास देना होगा कि उनके विचारों को सुना जाएगा।

सड़कें सुरक्षित कम, जानलेवा ज्यादा

अनुलोम-विलोम

यातायात सुरक्षा

सड़क दुर्घटनाएं भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कार दुर्घटनाओं की है। तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी व लापरवाह ड्राइविंग ने सड़कों को मौत का कुआं बना दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले शीर्ष पांच देशों में भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील और रूस हैं। खराब सड़क बुनियादी ढांचे, तेज गति, यातायात नियमों की अनदेखी और अधिक जनसंख्या से इन देशों में सड़क हादसों और मौतों की दर सबसे अधिक है। भारत की स्थिति अधिक चिंताजनक है। विश्व की केवल एक प्रतिशत कारें भारत में हैं, पर दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली 11 प्रतिशत मौतें यहीं दर्ज होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सड़क हादसों से होने वाली मौतों के मामलों में भारत शीर्ष पर है। यहां हर वर्ष करीब साढ़े चार लाख दुर्घटनाएं होती हैं और औसतन हर तीन से चार मिनट में एक व्यक्ति सड़क पर दम तोड़ देता है। दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में सबसे बड़ी संख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है। यही वह वर्ग है, जिसे देश की सबसे सक्रिय, ऊर्जावान और उत्पादक आबादी माना जाता है। एक युवा की मौत का मतलब केवल एक जान का जाना नहीं, बल्कि संभावनाओं का समाप्त हो जाना है।

वर्ष 2023 में देश में लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 1.72 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.77 लाख मौतों तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के कुल सड़क नेटवर्क का मात्र दो प्रतिशत है, उन पर 31 प्रतिशत मौतें दर्ज की गईं। साल 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52,609 लोग मारे गए। 2025 के पहले छह महीनों में 26,770 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। राज्यवार स्थिति पर नजर डालें, तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सड़क दुर्घटनाओं की मौतों के लिहाज से लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। हादसों के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, लेकिन बीते साल में मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई। 'इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऐंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन' की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में हर साल करीब 24 हजार लोग अपनी जान गंवाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि व्यापक और सतत जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहराता जाएगा।

देवेंद्र सिंह, टिप्पणीकार

नियमों का पालन यात्रियों की भी जिम्मेदारी

आवागमन और व्यापार-व्यवसाय के लिए यातायात व्यवस्था और सड़क-रेल जैसी सुविधाओं की महती भूमिका है। इसके लिए दुनिया भर में समाज और सरकारों के स्तर पर बड़े पैमाने पर सफल प्रयास भी हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में अत्याधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग करते हुए उच्च मानकीकृत सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन, साथ ही इन सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है, जो सबके लिए चिंता की बात है।

भारत में ही देखें, तो आजादी के बाद सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है। गांव-गांव में आबादी की छोटी से छोटी बसाहट तक संपर्क मार्ग से लेकर 14-16 लेन के स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है और ये सड़कें आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भारत का सड़क नेटवर्क माल ढुलाई का लगभग 70 प्रतिशत और यात्री यातायात का 85 प्रतिशत वहन करता है। देश का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा बड़ा है। यह 63.4 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। इस नेटवर्क में 1,46,195 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर राज्य राजमार्ग और स्थानीय सड़कें हैं।

जहां तक दुर्घटनाओं और मौतों की बात है, तो इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार सड़क पर यात्रा करने वालों की है। सरकार हर साल सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाकर लोगों को जागरूक करती है। सरकार ने नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने भी बढ़ाए हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य किया है और ऑटोमैटिक चालान प्रणाली लागू की है। बावजूद इसके, नशे में ड्राइविंग के मामले बढ़े हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि निरंतर मिशन के रूप में लेना होगा। स्पीड सीमा का सख्त पालन, ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार, पर्याप्त रोशनी, बेहतर साइन बोर्ड, हाईवे पेट्रोलिंग और दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। साथ ही, जनता को भी समझना होगा कि सड़क केवल चलने की जगह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का साझा मंच है। हाईवे और एक्सप्रेस-वे विकास के प्रतीक हैं, लेकिन यदि रफ्तार पर लगाम नहीं लगी, तो यही सड़कें मौत की राह बन जाती हैं। जरूरत है संतुलन की- रफ्तार भी हो, लेकिन सुरक्षा के साथ। तभी विकास का यह सफर सही मायनों में सुरक्षित कहा जा सकेगा।

दिनेश मिश्र, टिप्पणीकार

बीते दिसंबर में 7.8 प्रतिशत रही दर, खनन, बिजली और विनिर्माण क्षेत्र ने दी बढ़त

शानदार : औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली, एजेंसी। खनन, विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के दम पर भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर दिसंबर 2025 में दो साल से अधिक के उच्च स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़ा था।

आधिकारिक बयान में कहा गया, 'दिसंबर 2025 में औद्योगिक गति और मजबूत हुई क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7.8 प्रतिशत बढ़कर दो वर्ष से अधिक के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। नवंबर 2025 में इसमें 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने नवंबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के अनुमान को 6.7 प्रतिशत के अस्थायी अनुमान से संशोधित करके 7.2 प्रतिशत कर दिया है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो दिसंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत रही थी।

कारखानों के उत्पादन में तेजी का सफर

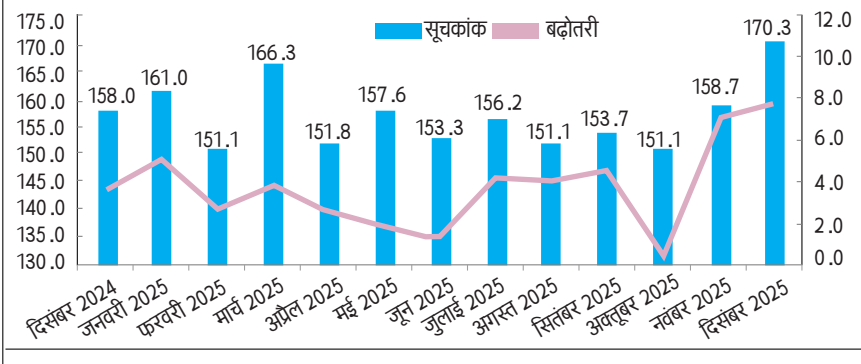

औद्योगिक उत्पादन में तेजी का असर

1 आम आदमी के लिए अच्छी खबर यह कि इससे रोजगार के मौके बढ़ते हैं। फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं। इससे नई भर्तियां होती हैं। अस्थायी मजदूरी से लेकर स्थायी नौकरियों तक मौके बढ़ते हैं।

2 आय और खर्च करने की क्षमता में वृद्धि

नौकरी/ओवरटाइम/बोनस यानी हाथ में ज्यादा पैसा आता है। लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं (मोबाइल, बाइक, कपड़े आदि)

3 महंगाई पर नियंत्रण से लोगों को राहत

चीजों की सप्लाई बढ़ती है जिससे दाम काबू में रहते हैं। रोजमर्रा की वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती रहती हैं। जिससे महंगाई का असर कम होता है।

सरकार की कमाई में वृद्धि

4 कर संग्रह बढ़ता है जिससे सड़क, अस्पताल, शिक्षा, सब्सिडी पर खर्च की गुंजाइश बनती है।

5 शेयर बाजार और निवेश माहौल बेहतर

निवेशकों का विश्वास बढ़ने से आम आदमी के म्यूचुअल फंड/पीएफ को फायदा होता है जिससे आर्थिक भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ता है।

पेंशन को सीधे स्वास्थ्य जरूरतों से जोड़ा जाएगा

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएफआरडीए ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना को एक अलग स्वास्थ्य आधारित योजना के रूप में तैयार किया है। इसका मकसद यह है कि रिटायरमेंट से पहले या बाद में जब भी इलाज के लिए जरूरत पड़े, अंशधारक को कर्ज लेने, बीमा दावे के चक्कर या रिश्तेदारों पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना के जरिये वह अपने ही पेंशन फंड से इलाज का खर्च निकाल सकता है।

इस योजना में कोई भी अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसके पास पहले से एनपीएस का खाता होना चाहिए। वैसे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारी, स्वरोजगार करने वाले लोग और रिटायरमेंट की योजना बना रहे निवेशक सब इसके दायरे में आते हैं। इसमें योगदान की राशि भी अंशधारक अपनी क्षमता के अनुसार तय कर सकता है।

इलाज के लिए पैसा निकालना होगा आसान : इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इलाज खर्च के लिए आंशिक निकासी। अगर किसी को ओपीडी इलाज या अस्पताल में भर्ती होकर खर्च करना पड़ता है, तो वह अपने स्वास्थ्य पेंशन खाते से 25% तक रकम निकाल सकता है। पैसा निकालने से पहले खाते में कम से कम ₹50,000 का कोष होना जरूरी है।

गंभीर बीमारी में पूरी रकम की छूट : अगर किसी अंशधारक को ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसमें इलाज का खर्च कुल कोष के 100% से ज्यादा हो, तो उसे पूरा पैसा एकमुश्त निकालने की अनुमति मिलेगी यानी कैंसर, हार्ट सर्जरी या लंबे इलाज जैसी स्थितियों में रिटायरमेंट की उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

40 साल से ऊपर वालों को खास फायदा

40 साल से ज्यादा उम्र के वे लोग जो सरकारी सेवा में नहीं हैं, उनके लिए इस स्कीम में एक खास सुविधा रखी गई है। ऐसे अंशधारक अपने मौजूदा एनपीएस खाते से 30% तक की रकम स्वास्थ्य पेंशन योजना में ट्रांसफर कर सकते हैं।

पैसा सीधे अस्पताल को ही मिलेगा

इलाज के लिए निकाली गई रकम सीधे टीपीए या अस्पताल को भुगतान के रूप में जाएगी। इससे पैसों के दुरुपयोग की संभावना कम होगी और पूरा सिस्टम ज्यादा पारदर्शी रहेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि पैसा वाकई इलाज में ही खर्च हो।

बाजार 30 S

शेयर बाजार

सेंसेक्स		निफ्टी	
82,344	+487.20	25,342	+167.35

टॉप गेनर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
बीईएल	453.40	8.90
एटर्नल	266.45	5.09

टॉप लूजर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
एशियन पेंट	2510.85	-4.34
मारुति	14876.80	-2.39

टॉप गेनर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
बीईएल	454.25	9.21
ओएनजीसी	268.23	8.18

टॉप लूजर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
टाटा कंज्यूमर	1133.40	-4.55
एशियन पेंट	2512.00	-4.22

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,71,000	+5,000
चांदी	3,85,000	+15,000

करेंसी
डॉलर/रुपया
91.99 -0.31

अंबे क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार खोजा

बैतूल (गोवा)। वेदांता लिमिटेड की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंबे गैस क्षेत्र के नीचे नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह खोज मूल्यांकन कुएं अंबे-2ए में की गई। इस खोज की जानकारी हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और तेल मंत्रालय को दे दी गई है।

अमेजन 16,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी

न्यूयॉर्क। अमेजन करीब 16,000 नौकरियों में कटौती कर रही है। ई-कॉमर्स कंपनी ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी दी। यह छंटनी अक्टूबर में हुई छंटनी के बाद हुई है। उस समय अमेजन ने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कार्यरत कर्मचारियों को पहले कंपनी के भीतर नई भूमिका तलाशने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा।

वोडाफोन पर फैसला एक निर्णायक मोड़ पर

नई दिल्ली। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि वोडाफोन के समायोजित सकल राजस्व देनदारी से जुड़ा फैसला एक निर्णायक मोड़ है, जिससे वह टिकाऊ वृद्धि पर ध्यान दे सकती है। बिड़ला ने कहा कि वोडाफोन आइडिया का अनुभव इस विश्वास को रेखांकित करता है कि कठिन दौर स्थायी नहीं होते, मजबूत कंपनियां टिकती हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले से लंबे समय से बनी अनिश्चितता दूर हुई है और सरकार के निर्णायक हस्तक्षेप से बुनियादी बदलाव आया है।

ओएनजीसी, रिलायंस में संसाधन का करार

बेतूल (गोवा)। अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं गैस खोज को गति देने और परिचालन लागत घटाने की दिशा में एक अहम रणनीतिक कदम उठाते हुए ओएनजीसी और रिलायंस ने ड्रिलिंग रिग, आपूर्ति वाहन और अन्य बुनियादी संसाधनों को साझा करने वाला एक समझौता किया है। यह समझौता लागत अनुकूलन, परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग की दिशा में बड़ा कदम है।

डॉलर के मुकाबले रुपया फिर 92 के स्तर पर

मुंबई। महीने के अंत में डॉलर की मांग आने से बुधवार को रुपया 31 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 91.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपया एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर सूचकांक में नरमी और यूरोप के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापारिक समझौते से मिली राहत से रुपया मजबूती से खुला था।

सोने के बदले कर्ज दो साल में दोगुना

रिपोर्ट

मुंबई, एजेंसी। सोने की कीमतों में तेज उछाल के बीच सुरक्षित माने जाने वाले इस खंड में बैंकों और अन्य कर्जदाताओं की दिलचस्पी बढ़ने से देश में सोने के आभूषण के बदले कर्ज दो साल में करीब दोगुना होकर नवंबर 2025 तक 15.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2025 तक के एक साल में सोने के बदले कर्ज (गोल्ड लोन) में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले नवंबर 2024 तक के वर्ष में इसमें 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इस वजह से नवंबर 2023 में 7.9 लाख करोड़ रुपये पर रहा कुल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो दो साल में बढ़कर 15.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, सोने के बदले कर्ज को लेकर बढ़ते भरोसे के कारण खुदरा कर्ज के कुल पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है। नवंबर 2025 के अंत तक कुल खुदरा ऋण में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 8.1 प्रतिशत थी। क्रिफ हाई मार्क ने कहा कि ऋण पोर्टफोलियो में यह तेज बढ़ोतरी सोने की ऊंची कीमतों और मजबूत गारंटी की वजह से हो रही है।

कर्ज लेने में पुरुष आगे, चुकाने में महिलाएं

रिपोर्ट के मुताबिक, सक्रिय गोल्ड लोन खातों की संख्या में वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रही और इसमें 10.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्ज अब कुल पोर्टफोलियो का लगभग आधा हिस्सा बन चुके हैं जबकि मार्च 2023 में इनकी हिस्सेदारी 36.4 प्रतिशत थी। विश्लेषण में पाया गया कि कुल गोल्ड लोन में 56 प्रतिशत से अधिक कर्ज पुरुष उधारकर्ताओं ने लिए। हालांकि कर्ज चुकाने के मामले में महिला कर्जदारों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है।

नए आधार ऐप से डिजिटल सत्यापन की सुविधा शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। आधार से जुड़े काम अब आसान और ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। नई आधार ऐप आधिकारिक तौर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दी गई है। इस नई ऐप को लाने का ऐलान नवंबर 2025 में किया गया था।

नई ऐप से डिजिटल पहचान मजबूत होगी और भौतिक आधार कार्ड पर निर्भरता कम होगी। अक्सर होटल चेक-इन, सिम कार्ड लेने, सत्यापन जैसे कामों में आधार की फोटो कॉपी देनी पड़ती है, जिससे डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है। इसमें बिना इंटरनेट भी पहचान का सत्यापन किया जा सकता है। ऐप के जरिए केवल जरूरी जानकारी जैसे नाम या उम्र ही साझा की जा सकती है।

इस ऐप के जरिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर को डिजिटल तरीके से बदला जा सकता है। इसके लिए नाममात्र शुल्क देना होगा। वहीं, ऐप से ही अपडेट होगा पता अपडेट कराने के लिए भी लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। डिजिटल रूप से पता बदलने का अनुरोध किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।

ऐप में पांच आधार रखने की सुविधा दी गई है। यह फीचर खासतौर पर परिवारों के लिए उपयोगी है।

'अमेरिका से वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति'

नई, दिल्ली, एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों पक्ष इसको अंतिम रूप देने के करीब हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम चरण में पहुंचाने के दौरान भी भारत ने अमेरिका के साथ वार्ता की गति बनाए रखी।

सूत्रों ने कहा कि भारत-ईयू एफटीए को अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों की मौजूदा स्थिति के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार भी उतना ही अहम है।

छूट 25 लाख से महंगी कार पर

नई एजेंसी। भारत ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए व्यापार समझौते में व्यापक बाजार में बिकने वाली कारों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है और सिर्फ 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली यात्री कारों पर ही आयात शुल्क में क्रमिक छूट दी जाएगी।

एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों पर दी जाने वाली छूट सालाना 2.5 लाख कारों तक ही दी जाएगी। इसके अलावा, यह कोटा मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की पुरानी और मशहूर कार विनिर्माता कंपनियों को दिया जाएगा।

भारत ने डीजल और पेट्रोल कारों के लिए सालाना 1.6 लाख कारों और इलेक्ट्रिक कारों के लिए 90,000 कारों का कोटा दिया है। भारत ने 15,000 यूरो (लागत, बीमा, माल ढुलाई) से कम कीमत वाली कारों पर कोई आयात शुल्क छूट नहीं दी है। इसमें सीमा शुल्क, जीएसटी और सड़क कर जोड़ने के बाद कार की खुदरा कीमत लगभग 25-27 लाख रुपये होती है।

भाकृअनुप-भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (गढ़खटंगा, राँची)
ICAR-INDIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
(Indian Council of Agricultural Research)
Garhkhatanga, Ranchi-834003 | web: http://iiab.icar.gov.in

F.No.:IIAB/3(399)/2025/493
E-Office Comp. No.: 380399
Date: 28.01.2026

विज्ञापन

भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-आईआईएबी) ने कलाकृति के निर्माण और स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और संस्थान में एटीएम की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए ईओआई आमंत्रित की है। योग्य और इच्छुक कंपनियां विस्तृत विज्ञापन के लिए संस्थान की वेबसाइट http://www.icar-iiab.res.in/ पर देखी जा सकती है।

ह०/- सहायक प्रशासनिक अधिकारी

करार से उत्साहित शेयर बाजार दूसरे दिन भी चढ़ा

मुंबई, एजेंसी। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता से बढ़े उत्साह के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 487.20 अंक उछलकर 82,344.68 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान एक समय यह 646.49 अंक की तेजी के साथ 82,503.97 अंक तक पहुंच गया था। वहीं, निफ्टी 167.35 अंक बढ़कर 25,342.75 अंक पर बंद हुआ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए को अंतिम रूप देने से लगभग दो अरब लोगों का बाजार बनेगा और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब एक चौथाई हिस्से को कवर करेगा।

सेंसेक्स में 487 अंक की बढ़त, निफ्टी कुल 167.35 अंक बढ़ा

इस समझौते से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क घटेगा, जबकि ईयू से 97 प्रतिशत आयात पर शुल्क कम होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस और इटर्नल में लिवाली से भी बाजार चढ़े।

एटीएम से निकासी घटी, औसत राशि में बढ़ोतरी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में एटीएम से नगद निकासी में 2025 के दौरान गिरावट देखी गई जबकि प्रति लेनदेन की औसत राशि बढ़ी है।

वित्तीय संस्थानों को लॉजिस्टिक समर्थन और एटीएम संचालन से जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की रिपोर्ट कहती है कि देश के भीतर उपभोक्ता खर्च के लिए नगद का इस्तेमाल अब भी बड़े पैमाने पर हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में एटीएम से मासिक औसत नगद निकासी 2025 में 1.21 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1.30 करोड़ रुपये था। एटीएम से प्रति लेनदेन की औसत राशि 4.5 प्रतिशत बढ़कर 2025 में 5,835 रुपये हो गई, जबकि 2024 में यह 5,586 रुपये थी। सीएमएस ने कहा कि कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में नकद निकासी की प्रवृत्ति अधिक रही, जहां प्रति एटीएम मासिक औसत निकासी 1.30 करोड़ रुपये रही जबकि महानगरों एवं शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 1.18 करोड़ एवं 1.11 करोड़ रुपये थी।

उपभोक्ता खर्च के लिए देश में नगद का इस्तेमाल अब भी बड़े पैमाने पर हो रहा

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर
ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर में निम्नलिखित कार्य नवीन ई-पंजीयन में पंजीकृत ठेकेदार सरल क्र. 01 से 03 हेतु दिनांक 05.02.2026, सरल क्रं. 04 से 08 हेतु 11.02.2026 तक निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	नि.आ.सू. क्र. / दिनांक	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1.	482	जिला जॉजगीर चाम्पा के विकासखण्ड बलौदा अंतर्गत बेलटुकरी से खैजा नहरपार मार्ग लंबाई 0.800 कि.मी. का निर्माण कार्य। द्वितीय आमंत्रण। संभाग चांपा। मद संख्या 64-5054-9002	75.29
2.	483	व्यवहार न्यायालय परिसर सारंगढ़ जिला रायगढ़ वर्तमान जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में शौचालय काम्पलेक्स एवं डिजीटल कम्प्यूटर कक्ष निर्माण कार्य। द्वितीय आमंत्रण। सारंगढ़ संभाग। मद संख्या 67-4059-2450	18.02
3.	484	कया-कमतरा मार्ग के मर्दन नाला पर स्थित पुल के पहुंच मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य एवं घरघोडा लैलूंगा मार्ग राज्य मार्ग क्र. 17 के कि.मी. 63/6 में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त भाग का विशेष मरम्मत का कार्य। द्वितीय आमंत्रण। संभाग, रायगढ़। मद संख्या - 24-5054-4090	28.70
4.	485	लोक निर्माण विभाग हाईकोर्ट उपसंभाग क्रं.-2, बिलासपुर के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय आवासीय परिसर बोदरी बिलासपुर में साधारण मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग क्र. 2, बिलासपुर। मद संख्या 67-2216-2450	100.00
5.	486	लोक निर्माण विभाग हाईकोर्ट उपसंभाग क्रं.-2, बिलासपुर के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय मुख्य भवन बोदरी बिलासपुर में साधारण मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग क्र. 2, बिलासपुर। मद संख्या 67-2059-2449	100.00
6.	487	व्यवहार न्यायालय पाली जिला कोरबा हेतु शौचालय निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग कोरबा। मद संख्या 67-4059-2450	16.90
7.	488	जिला जेल जांजगीर के प्रशासनिक भवन का मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग चांपा। मद संख्या 67-4059-8040	12.97
8.	489	(1) बाबाधाम कोसमनारा में मुख्य भवन के सामने ग्रेनाईट फर्श सहित शेड भवन का निर्माण कार्य (2) बाबाधाम कोसमनारा में आगंतुकों (जनता) के विश्राम एवं भोजन हेतु शेड भवन का निर्माण कार्य (3) बाबाधाम कोसमनारा में शौचालय परिसर भवन का निर्माण कार्य (4) बाबाधाम कोसमनारा में पार्किंग क्षेत्र हेतु स्टैण्ड कांक्रीट का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग रायगढ़। मद संख्या 8443 जमा मद	119.84

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि., बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर

G-252606259/5

संपादकीय जागरण

गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 : माघ शुक्ल - 11 वि. 2082

आत्ममुग्धता पतन की ओर ले जाती है

एक और विमान हादसा

बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत ने देश में हवाई सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने देश में रह-रहकर विमान हादसे होते रहे हैं। इन हादसों में अजीत पवार की तरह कई नेताओं और आम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई से बारामती जा रहा विमान जिस तरह हादसे का शिकार हुआ और उसमें सवार चालक दल के सदस्यों के साथ सभी पांच लोग मारे गए, उसने सुरक्षित हवाई यात्रा को लेकर जो चिंताएं पैदा की हैं, उनका समाधान किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आम और खास लोगों की ओर से चार्टर विमान सेवाओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा विमान किन कारणों से विस्फोट के साथ आग का गोला बन गया। यह स्वाभाविक है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से इस हादसे की जांच होगी और वह ब्लैक बाक्स की पड़ताल पर निर्भर करेगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले 2023 में मुंबई में वीएसआर एविएशन का बाम्बार्डियर लीयरजेट 45 विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था। यह हैरानी की बात है कि अभी इस दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ही सामने आ सकी है। ऐसा क्यों है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

चूंकि अजीत पवार महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता थे और उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर अपना अलग दल बनाया था और वही उसके कर्ता-धर्ता थे, इसलिए यह प्रश्न सतह पर आना स्वाभाविक है कि उनके न रहने पर उनका दल एनसीपी अस्तित्व में बना रहेगा या नहीं और उसकी कमान कौन संभालेगा? एक के बाद एक सरकारों में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार विवादों में भी रहे, लेकिन वे राजनीतिक रूप से सदैव प्रभावी बने रहे। उन्होंने चाचा शरद पवार को चुनौती भी दी और उन पर भारी भी पड़े। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी एनसीपी का प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा था और उन्हें केवल एक सीट मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में उन्होंने 41 सीटें जीत कर अपनी राजनीतिक ताकत का आभास कराया था। उनका निधन महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का कारण बन सकता है। हालांकि संख्याबल के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी की अहमियत तीसरे नंबर की थी, लेकिन उसका महत्व इसलिए था कि वह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के दबदबे को कम करने में सहायक थी। यह किसी से छिपा नहीं कि शिवसेना और भाजपा में खटपट चलती ही रहती है। इस खटपट के बीच एनसीपी संतुलन कायम करने का काम करती थी। पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही थी कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं। देखना है कि अब ऐसा होता या नहीं और होता है तो किस रूप में?

नए शीत युद्ध में भारत के विकल्प

राज शुक्ला

ट्रंप की नीतियों से प्रभावित हो रहे वैश्विक ढांचे में भारत को आधुनिक तकनीक में महारत हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का कायाकल्प करना होगा

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो का 'मुनरो सिद्धांत' बड़ा चर्चित रहा है। इसके मूल में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय शक्तियों के प्रतिरोध एवं अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित करना था। मुनरो सिद्धांत के नए स्वरूप में डोनाल्ड ट्रंप का 'डोनरो सिद्धांत' भी सुर्खियों में है। इसका तात्कालिक लक्ष्य तो पश्चिमी गोलार्ध बताया जा रहा है, लेकिन इसका दूरगामी लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हितों को साधना है। यही ट्रंप के राजनीतिक समर्थक 'मागा' का भी एजेंडा है। डोनरो सिद्धांत एक तरह से अमेरिका और दूसरी ओर चीन-रूस के बीच शीत युद्ध के नए दौर का संकेत है। फिलहाल अमेरिकी खेमा पश्चिमी गोलार्ध में संसाधनों की पहुंच और आर्कटिक क्षेत्र में सामरिक मोर्चेबंदी को मजबूत करने की बात कह रहा है, लेकिन अंततः इसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति के दम पर चीनी प्रभुत्व को रोकना है। यह सिद्धांत नए शक्ति संतुलन पर केंद्रित दिखता है। ट्रंप पश्चिमी दुनिया का नेता बनने से अधिक पश्चिमी गोलार्ध में वर्चस्व के इच्छुक दिखते हैं। उनका नजरिया स्पष्ट है कि पश्चिमी गोलार्ध पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में हो और चीन, रूस एवं ईरान जैसे देश इसे अच्छी तरह से समझ लें। ट्रांस-अटलांटिक व्यवस्था को भी नई परिस्थितियों के अनुरूप नए सिरे से ढाला जा रहा है। ग्रीनलैंड का मुद्दा तनाव के केंद्र में बना ही हुआ है। इस पर ट्रंप किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं। भले ही इससे डेनमार्क जैसा विश्वसनीय सहयोगी छिटक जाए या फिर नाटो के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाए। वे चीन और रूस का डर दिखाकर उस पर काबिज होने को तत्पर हैं। वे अपने समृद्ध यूरोपीय सहयोगियों से भी आर्थिक एवं सामरिक मोर्चे पर अधिक अंशदान को लेकर अड़े हुए हैं।

पश्चिम एशिया में संभावित अमेरिकी प्रतिरोध की धुरी को कुंद करने के बाद ट्रंप अब्राहम समझौते के ऐसे सहयोगियों को साधने में जुटेंगे, जो अपने तेल का मोह छोड़ते हुए स्वयं को इस्लामिक कट्टरवाद से दूर रखकर एआइ, डाटा केंद्रों, नवीकरणीय ऊर्जा और रियल एस्टेट जैसे पहलुओं को लेकर उनकी मंशा के अनुरूप आगे बढ़ें। दूसरे खेमे की बात करें तो चीन-रूस का उद्देश्य चीनी आर्थिक एवं तकनीकी क्षमताओं और रूसी सैन्य क्षमताओं की जुगलबंदी से अमेरिकी शक्ति को चुनौती देना है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक एवं तकनीकी मोर्चे पर चीन का जबरदस्त उभार हुआ है। इसने उसे निर्णायक बढ़त दिलाई है। बीते दिनों इसकी मिसाल तब देखने को भी मिली, जब ट्रंप टैरिफ के जवाब में चीन ने रेयर अर्थ के मुद्दे पर

अवधेश राजपूत

अमेरिका को झुकाते हुए उसे अपना रुख बदलने पर विवश किया। अमेरिकी विद्वान और चीन मामलों के विशेषज्ञ रश डोशी का एक हालिया आकलन दोनों देशों के बीच बढ़ते अंतर को बखूबी रेखांकित करता है, जिसमें पलड़ा चीन के पक्ष में झुका हुआ है। इसे इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका की तुलना में चीन की स्टील उत्पादन क्षमता 13 गुना, सीमेंट उत्पादन 20 गुना, जहाज निर्माण क्षमता 200 गुना अधिक है। चीन अमेरिका के मुकाबले तीन गुना अधिक युद्धपोत बनाने में सक्षम हो गया है। यह विशालकाय विनिर्माता देश विश्व के लगभग आधे रसायन, करीब 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन, तीन-चौथाई बैटरी, 80 प्रतिशत ड्रोन, 90 प्रतिशत सौर पैनल और महत्वपूर्ण हो चले रेयर अर्थ तत्वों के 90 प्रतिशत तक की आपूर्ति करता है। इसके बावजूद अमेरिकी सैन्य क्षमताएं अभी भी कहीं आगे हैं। सीरिया से लेकर ईरान और हाल में वेनेजुएला जैसे उदाहरण इसके प्रमाण हैं।

जैसे-जैसे नए शीत युद्ध में प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे संघर्ष के कई मोर्चे खुलते हुए दिखेंगे, लेकिन निर्णायक अखाड़ा हिंद-प्रशांत क्षेत्र ही बनेगा। इस संदर्भ में ट्रंप को अलग तरह का नेता समझना गलत होगा। वह तो नई चुनौतियों के लिहाज से अमेरिकी शासनकला के शस्त्रों का ही उपयोग कर रहे हैं। इसमें टैरिफ उनका पहला वार था। उनका दावा है कि ऐसे ही अन्य उपायों के जरिये उन्होंने 18 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की राशि जुटाई है। वेनेजुएला पर अपने रुख से न केवल उन्होंने तेल के बड़े भंडार पर अमेरिकी झंडा गाड़ दिया, बल्कि डालर के खिलाफ हो रही मोर्चेबंदी की हवा निकालने का भी प्रयास किया। भविष्य के कई पहलुओं को निर्धारित करने वाली एआइ तकनीक में अमेरिका अग्रणी बना हुआ है। इसलिए भले ही नई प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कुछ संतुलित दिखे, लेकिन डोनरो सिद्धांत बाजी पलटकर अमेरिका को बढ़त दिला सकता है।

इस परिदृश्य में भारत की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? उसे कौन से रणनीतिक एवं सामरिक समायोजन करने होंगे? यदि डोनरो सिद्धांत का वास्तविक उद्देश्य एशिया में चीनी वर्चस्व पर अंकुश है तो यह भारत-अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के अनुकूल ही है। चीन के तेवर स्पष्ट हैं कि एशियाई जंगल में केवल एक ही शेर हो सकता है। अगर इस वन में दो शेरों के लिए जगह बनानी है तो भारत को आंतरिक मोर्चे पर स्वयं को मजबूत बनाते हुए चीन के विरुद्ध चतुराई भरी बाहरी व्यूह रचना करनी होगी। यही इकलौता रास्ता है। इस क्रम में यदि हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में आ रही छोटी-मोटी अड़चनों को पार कर लें तो क्या तकनीकी साझेदारियों, क्षमता निर्माण, बाजार तक पहुंच और प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण के संदर्भ में यह एक बड़ी उछाल होगी? वैश्विक भू-राजनीति की हार्ड पावर और कठोर प्रतिस्पर्धा की ओर झुकाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने में तकनीकी क्षमताओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीकी क्षमताओं जैसे एआइ, क्वांटम, रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणालियां, ऊर्जा, डाटा उपयोग आदि में महारत हासिल करने के लिए सक्रियता के साथ निर्णायक कदम उठाने होंगे। दूसरा, शक्ति के संसाधनों को कहीं अधिक दृढ़ता के साथ संयोजित करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के जारी कायाकल्प की गति कई गुना तेज करनी होगी।

(लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं)

response@jagran.com

सवालों के घेरे में लिव इन संबंध

ऋतु सारस्वत

अदालती निर्णयों से लेकर कई अध्ययन दर्शाते हैं कि लिव इन रिलेशन वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता

हाल में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, 'लिव-इन रिलेशन भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लड़कियां सोचती हैं कि वे माडर्न हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आभास होता है कि यह रिश्ता शादी की तरह कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है।' तमाम अदालतें निरंतर इसके लिए चेता रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अपेक्षाकृत लड़कियों के लिए सामाजिक स्तर पर कहीं अधिक नुकसानदायक है, लेकिन शायद युवाओं के लिए आधुनिक होने का तात्पर्य पश्चिमी संस्कृति को अपनाना हो गया है। उनका यह सोच उन्हें ऐसी स्थितियों में धकेल देता है, जहां से निकलने का हर प्रयास नाकाम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी युगल न्यायालय के दरवाजे खटखटाता हुआ नहीं दिखाई देता।

अगस्त 2023 में 'अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि अधिकांश लिव-इन जोड़ों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद महिला के लिए समाज का सामना करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह के सामाजिक बहिष्कार से लेकर अभद्र सार्वजनिक टिप्पणियां लिव-इन रिलेशनशिप के बाद उसके कष्टों का हिस्सा बन जाती हैं। जिस पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप अपना रही है, उसे यह जानना होगा कि आज भी पुरुषों और स्त्रियों के लिए स्पष्ट रूप से अलग नैतिक नियम हैं और इसका उदाहरण ब्रिएना पेरेली-हैरिस का शोध है, जो यूरोप के 11 देशों पर आधारित है। इसमें पाया गया कि लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक दृष्टि, चरित्रगत संदेह और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। शोध यह भी बताता है कि जहां पारंपरिक पारिवारिक और नैतिक मूल्य अधिक मजबूत हैं, वहां लिव-इन के बाद महिलाओं के लिए नए

अलगाव बढ़ाते अस्थिर रिश्ते ● प्रतीकात्मक

संबंधों में स्थापित होना, सामाजिक स्वीकृति पाना और सम्मानजनक जीवन में पुनः प्रवेश करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसी असमान और कठोर सामाजिक व्यवहार को शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से 'जेंडर्ड स्टिग्मा' कहा है। उक्त शोध यह स्थापित करता है कि लिव-इन संबंध महिलाओं के लिए केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा सामाजिक जोखिम बन जाता है, जिसके दीर्घकालिक मानसिक, सामाजिक और भविष्यगत दुष्परिणाम होते हैं।

तमाम अध्ययन इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि 'लिव इन रिलेशनशिप' कभी भी वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता। मनोविज्ञानी स्काट एम स्टैनली अपने 'स्लाइडिंग बनाम डिसाइडिंग सिद्धांत' में स्पष्ट करते हैं कि लिव-इन संबंधों में युवा अक्सर सोच-समझकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि परिस्थितियों के साथ धीरे-धीरे फिसलते हुए बड़े जीवन-निर्णयों में प्रवेश कर जाते हैं। इन रिश्तों में स्पष्ट और सचेत प्रतिबद्धता नहीं होती। यही असंतुलन आगे चलकर भावनात्मक असुरक्षा, मानसिक तनाव और संबंधों की अस्थिरता का कारण बनता है। स्टैनली का शोध कहता है कि लिव-इन संबंध टूटने पर अवसाद, आत्मसम्मान में गिरावट और भविष्य के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्टैनली का मानना है कि लिव-इन संबंध आकर्षक लग सकते हैं, पर वास्तव में वे उच्च-जोखिम वाले हैं, जिनके प्रायः नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से स्टैनली की विचारधारा को सत्यापित करते हुए दिखाई देती है कि विवाह संस्था व्यक्ति को जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव-इन-रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता।

भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती उस संस्कृति के पीछे भागना है, जिसे पश्चिमी संस्कृति और बालीवुड ने स्थापित किया है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस देश में विवाह संस्था को नष्ट करने और समाज को अस्थिर करने और हमारे देश की प्रगति में बाधा डालने की व्यवस्थित योजना है। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के प्रसारण से विवाह संस्था का खात्मा हो रहा है। विवाहित रिश्तों में साथी के साथ बेवफाई और स्वतंत्र लिव-इन-रिलेशनशिप को प्रगतिशील समाज की निशानी बताया जा रहा है। युवा पीढ़ी ऐसे दर्शन की ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि उन्हें इसके दीर्घकालिक परिणामों का पता नहीं है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदना किसी भी तरह से संतोषजनक जीवन नहीं है। विवाह संस्था व्यक्ति के जीवन को जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव-इन-रिलेशनशिप में अपेक्षित नहीं है।

लिव इन समर्थकों को सोशल साइंस रिसर्च में प्रकाशित शोध 'कोहैबिटेशन डिसोल्यूशन एंड साइकोलाजिकल डिस्ट्रेस अमंग यंग अडल्ट्स' को पढ़ना चाहिए। इस शोध के अनुसार लिव-इन संबंध टूटने के बाद अवसाद, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। लिव-इन संबंध का टूटना एक गंभीर तनावपूर्ण जीवन-घटना है, जिसके दूरगामी और घातक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय की शक्ति

धन, समय और सफलता आपस में गहराई से जुड़े हैं। पैसा कहता है मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। वक्त कहता है मैं सही हूं तो सब कुछ सही है। सफलता कहती है मैं मिल गई तो फिर और किसी की आवश्यकता ही क्या। हालांकि जब इन तीनों की प्राप्ति हो जाए तो असल परीक्षा तभी शुरू होती है। इस परीक्षा में पास होने की कुंजी अस्पताल, जेल और श्मशान घाट में मिलती है। अस्पताल में हमें समझ आएगा कि जिस पैसे को कमाने के पीछे हमने स्वास्थ्य की अवहेलना की, उस स्वास्थ्य से बढ़कर पैसा कुछ भी नहीं है। जेल में अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता की कीमत पर वे लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने अमानवीय और अनैतिक मार्ग अपना कर पैसा या कथित सफलता प्राप्त की है। श्मशान में अनुभूति होगी कि अभी जो हमारे पास वक्त है, वह कितना अनमोल है। इसलिए घड़ी के अनुसार जीना अक्सर सफलता की कुंजी माना जाता है। हमें समझना होगा कि धन एक साधन है, लेकिन समय उससे भी बड़ा है और इसका सही प्रबंधन ही जीवन में सफलता की कुंजी है।

समय के सदुपयोग से ही धन अर्जन संभव है, किंतु गंवाए समय की पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हर पल का महत्व समझ कर लक्ष्य-निर्धारण, परिश्रम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना ही सफलता, समृद्धि और सार्थकता को सुनिश्चित करता है। समय ही वह संसाधन है, जो धन कमाने, अनुभव प्राप्त करने और जीवन में संतुष्टि पाने का अवसर देता है। इसलिए समय का सम्मान कर उसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। सफल होने के लिए यह नहीं देखना कि हम कितने व्यस्त हैं, बल्कि यह समझना है कि किन कार्यों में व्यस्त हैं। इस क्रम में अपने उन 20 प्रतिशत कार्यों पर ध्यान दें, जो हमें 80 प्रतिशत परिणाम देने में सक्षम हैं। समय की शक्ति पहचान कर और उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन करके ही हम समृद्ध और सार्थक जीवन जी सकते हैं।

डा. निर्मल जैन

उचित सख्ती

यमुनापार के आनंद विहार क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान चलाने वालों पर हाई कोर्ट की सख्ती सर्वथा उचित है। अदालत ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि वह इस क्षेत्र में सड़क पर कब्जा कर दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराए। वास्तव में ये निराशाजनक है कि अस्थायी दुकानदारों के साथ ही रेहड़ी व पटरी वालों ने यहां की सड़कों को घेर रखा है। ऐसे में वातायात जाम लगता है और लोगों का सड़कों के किनारे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एमसीडी के सर्वे में योग्य पाए गए विक्रेताओं को ही यहां सामान बेचने की अनुमति दी जाएगी।

हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में आनंद विहार में अतिक्रमण हटाने के बाद अन्य स्थानों पर भी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए

ये मामला आनंद विहार से जुड़ा अवश्य है, लेकिन दिल्ली के कई स्थानों पर इस तरह का अतिक्रमण है। एमसीडी को अदालत के निर्देशों के आलोक में यहां आवश्यक कार्रवाई करनी ही चाहिए, साथ ही उसे राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने पर काम करना चाहिए, ताकि यहां से गुजरने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अतिक्रमण हटाने के बाद क्षेत्र में लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने व सुंदरीकरण करने संबंधी निर्देश भी बेहद महत्वपूर्ण है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी सहायक होगा?

आज का सवाल

क्या अजीत पवार के निधन से उनके नेतृत्व वाली राकांपा के समक्ष अस्तित्व का संकट बढ़ गया है?

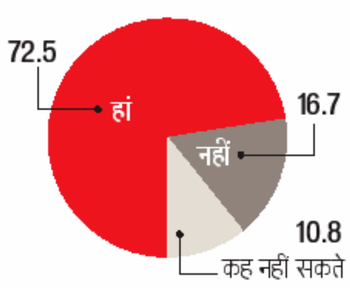

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

आकांक्षाओं को पंख लगाए बजट

'सुधारों की गति बढ़ाए बजट' विषय से प्रकाशित तरुण गुप्त का लेख पढ़ा। आगामी बजट के संदर्भ में कुछ प्रमुख प्रश्न प्रासंगिक दिखते हैं। एक यही कि हाशिए पर मौजूद समुदायों और ग्रामीण भारत के लिए क्या केवल सब्सिडी काफी है या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में ऐसे ठोस सुधार होंगे जो उन्हें सीधे बाजार और कौशल से जोड़ सकें? विशेष रूप से आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए क्या यह बजट केवल 'महिला-हितैषी' होने का दावा करेगा या उनकी आर्थिक भागीदारी को जीडीपी के मुख्य हिस्से के रूप में स्थापित करने हेतु कार्यस्थलों पर सुरक्षा, शिशु गृह और उद्यमशीलता के लिए व्यापक आवंटन सुनिश्चित करेगा? शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सरकार को अपनी प्राथमिकताओं पर आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्या बजट में शोध, नवाचार और 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' जैसे भविष्य के कौशल के लिए ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार होगा जो भारत को ग्लोबल टैलेंट हब बना सके? क्या अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने की होड़ में क्या हम एमएसएमई और मध्य वर्ग की उन चिंताओं को दूर कर पाएंगे जो करों के बोझ और बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं? यदि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो बजट को एक वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा बनने से ऊपर उठना होगा। सरकार को यह सोचना होगा कि क्या वह पुरानी नीतियों के सरलीकरण मात्र से संतुष्ट है या वह ऐसे साहसिक-निर्णायक सुधारों के लिए तैयार है जो जमीन पर बदलाव ला सकें। समय की मांग है कि सरकार ऐसी जवाबदेह राजकोषीय नीति बनाए, जो न केवल निवेश को आकर्षित करे, बल्कि हर भारतीय की आकांक्षाओं को पंख लगा सके।

समीक्षा मिश्रा-आइआइएमसी, जम्मू

मदर्स आफ आल डील्स

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) संपन्न हुई है। यह डील होने के बाद संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस 'मदर्स आफ़ आल डील्स' कहां है। कहीं ना कहीं विश्व के अंदर एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में यह डील मददगार साबित होगा। यह डील सिर्फ भारत और यूरोप के 200 करोड़ आबादी (लगभग विश्व का 25 प्रतिशत हिस्सा) के लिए ही मददगार ही सिर्फ साबित नहीं होगा। बल्कि विश्व राजनीति में अमेरिकन वर्चस्व के रूप मे स्थापित अमेरिका और विश्व के आर्थिक महाशक्ति (वर्ल्ड फैक्ट्री) के रूप में कायम चीन को भी कड़ा संदेश जाएगा। यह डील भारतीय उत्पादों के लिए यूरोप एक बड़ा बाजार स्थापित होगा। अब भारत के 99 प्रतिशत से ज्यादा सम्मान यूरोपीय देश में काम या बिना टैक्स के बिकेंगे। कपड़ा, चमड़ा, ज्वेलरी सहित अन्य सेक्टर को नए बाज़ार उपलब्ध होगे इसके साथ भारतीय आइटी और एजुकेशन सर्विसेज को भी यूरोप में नया बाजार मिलेगा। जिस तरह से भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ यह डील की उसकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है। एक तरह से यह भारत की आर्थिक क्षेत्र मे एक कूटनीति के विजय के रूप में देखा जा रहा है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

मणिपुर की आग कब बुझेगी

मणिपुर राज्य के इंफाल पश्चिम जिले के गांव कौत्रुक चिंग लेइकाई आज भी उस डर के साथ जी रहा है, जिसे देश के बाकी हिस्सों में शायद ही कोई महसूस कर सके। इंफाल से 25 किलोमीटर दूर बसा यह गांव घाटी और पहाड़ की सीमा पर स्थित आखिरी बस्ती है। इसके आगे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और यहीं से मणिपुर की सबसे जटिल और खतरनाक कहानी जन्म लेती है। मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के दौरान यह गांव सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल था, लेकिन ढाई साल बाद भी यहां हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। गोली नहीं चल रही, बम नहीं गिर रहे, लेकिन चैन की नींद आज भी लोगों के लिए सपना बनी हुई है। गांव के लोग बताते हैं कि हर रात पहाड़ियों की ओर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कभी जानवरों जैसी चीखें, कभी सामूहिक शोर। आरोप है कि कुकी उग्रवादी इन आवाजों के जरिए गांव में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग मानसिक रूप से टूट जाएं और गांव खाली करने पर मजबूर हो जाएं। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस गांव में 57 परिवार रहते हैं। किसी भी कोने में कोई घटना होती है, उसका असर सबसे पहले हमारे गांव में दिखता है। डर यहां स्थायी मेहमान बन चुका है। कौत्रुक चिंग लेइकाई का सामरिक महत्व भी कम नहीं है। यह गांव राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहद करीब है और यहां से पहाड़ी इलाकों तक पहुंच आसान है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

पोस्ट

यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से मोदी ने न केवल ट्रंप के दांव को निस्तेज किया, बल्कि विश्व में भारत के विरोधियों को बड़ा झटका भी दे दिया। इससे भारत एक बड़े स्तर के विनिर्माता एवं निर्यातक के रूप में भी स्थापित होगा। जेवियर@ZavierIndia

फ्रांस माइक्रोसाफ्ट और जूम जैसे अमेरिकी माध्यमों के बजाय विजियो जैसे यूरोपीय विकल्पों का उपयोग शुरू करेगा। अब किसी संप्रभु राष्ट्र की परिभाषा में तकनीकी संप्रभुता के पहलू को भी जोड़ा जाना चाहिए। बिग टेक कुछ और नहीं, बल्कि नए दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी ही हैं।

श्रीधर वेंबू@svembu

चुनावी लोकतंत्र में सफलता के तीन रास्ते हैं। शासन में गुणवत्ता, निजी जीवन में शुचिता एवं ईमानदारी और आम जनता एवं जड़ों से जुड़ाव। राजनीति में सफलता एवं प्रासंगिकता के लिए इन तीनों में किसी एक में तो महारत हासिल करनी ही पड़ती है। अजीत पवार की ताकत जनता के साथ उनका जुड़ाव था। लोग उनसे बहुत लगाव रखते थे और सार्वजनिक जीवन में यह बात बहुत मायने रखती है। यशवंत देशमुख@YRDeshmukh

जनपथ

रहे सियासी पारियों में जो सदा 'अजीत',
किंतु नियति से आज तक कौन सका है जीत!
कौन सका है जीत कहूं क्या इससे ज्यादा,
असमय सबको छोड़ गए यूं अजीत दादा।
किंतु न रुकती सोच दिख रही सत्यानाशी,
ममता जी के बोल आज भी रहे सियासी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 195

अर्थ जागरण

एक नजर में

एमेजोन ने की 16 हजार नौकरियों की कटौती

बेंगलुरु: दिग्गज ई-कामर्स कंपनी एमेजोन ने बुधवार को कहा कि वह वैश्विक स्तर पर 16 हजार नौकरियों की कटौती करेगी। तीन महीने में कंपनी में यह छंटनी का दूसरा बड़ा दौर है। कंपनी कोरोना महामारी के दौरान ज्यादा हायरिंग के बाद रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। कंपनी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में भी 14 हजार कर्मचारियों की छंटनी की थी। ताजा छंटनी से भारत में कार्यरत कर्मचारियों के भी प्रभावित होने की संभावना है। (रायटर)

मारुति सुजुकी को 3,879 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली: देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ चार प्रतिशत बढ़कर 3,879 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का कहना है कि नए लेबर कोड लागू करने पर 594 करोड़ रुपये खर्च होने के कारण शुद्ध लाभ प्रभावित हुआ है। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में कंपनी को 3,727 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बीती तिमाही में कंपनी की संचालन आय 49,904 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 38,764 करोड़ रुपये थी। (प्रेट्र)

2025 में 42% बढ़ा विलय व अधिग्रहण सौदों का मूल्य

नई दिल्ली: कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान रणनीतिक विलय व अधिग्रहण (एमएंडए) सौदों की राशि में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष देश में कुल 113 अरब डालर के विलय व अधिग्रहण सौदे हुए हैं। यह वृद्धि घरेलू सौदों के कारण रही है और कुल मूल्य में इनकी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है। इसके साथ ही विदेश से आने वाली राशि में सालाना आधार पर 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (आइएएनएस)

पहले नौ माह में यूरिया की बिक्री 3.8% बढ़ी

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2025) के दौरान देश में यूरिया की बिक्री 3.8 प्रतिशत बढ़कर 3.11 करोड़ टन रही है। इसमें ज्यादा आयात का प्रमुख योगदान रहा है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया (एफएआइ) की ओर से बुधवार को जारी डाटा के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2025 में यूरिया का घरेलू उत्पादन 2.24 करोड़ टन रहा है। (प्रेट्र)

रेड चीफ ने आयुष्मान खुराना को नया ब्रांड एंबेसडर बनाया

नई दिल्ली: देश के दिग्गज फुटवियर ब्रांड रेड चीफ ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। रेड चीफ निर्माता लेयन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज ज्ञानचंदानी ने कहा कि आयुष्मान खुराना में हमें एक ऐसा साथी मिला है, जो ब्रांड की भावना को पूरी तरह दर्शाता है। इस साझेदारी के साथ हम अपनी ब्रांड पहचान को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही युवा उपभोक्ताओं से जुड़ाव बढ़ाना चाहते हैं। आयुष्मान के जरिये कंपनी अपनी फार्मल लेदर, कैजुअल लेदर, स्पोर्ट्स शूज और स्नीकर्स रेंज पर केंद्रित अपने नए दृष्टिकोण को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहती है। (वि.)

दो साल में दोगुना हुआ गोल्ड लोन पोर्टफोलियो

मुंबई, प्रेट्र: कीमती कमोडिटी के मूल्य में वृद्धि से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो नवंबर, 2025 तक दो साल में लगभग दोगुना होकर 15.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नवंबर, 2025 तक के साल में सोने के बदले लोन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि नवंबर, 2024 तक इसमें 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर, 2023 में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 7.9 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था।

क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने के बदले लोन लेने में हुई आसानी से नवंबर के आखिर में कुल खुदरा कर्ज पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी एक साल पहले के 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गया है। कंपनी ने कहा कि सोने की बढ़ती कीमतों और मजबूत गारंटी की वजह से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। इतना ही नहीं सोने की कीमतों में उछाल ने उधार लेने वाले की लोन योग्यता बढ़ा दी है। क्रिफ हाई मार्क ने कहा कि 56 प्रतिशत से ज्यादा गोल्ड लोन पुरुषों ने लिए हैं, जबकि महिलाओं ने कर्ज अदा करने में बेहतर प्रदर्शन किया है। गोल्ड लोन कारोबार में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकारी बैंकों के पास है, जबकि गोल्ड लोन फोकस्ड एनबीएफसी के पास बकाया पोर्टफोलियो का 8.1 प्रतिशत हिस्सा है। एसेट क्वालिटी के नजरिये से देखें तो बकाया भुगतान में सुधार हुआ है और नवंबर, 2025 तक के साल में सभी फंसे कर्जों का स्तर कम हुआ है। खास बात यह है कि गोल्ड लोन पोर्टफोलियो सभी खुदरा लोन श्रेणी में सबसे कम डिफाल्ट की श्रेणी में आते हैं।

- सोने के बदले लोन लेने में हुई आसानी ने कुल खुदरा कर्ज पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी बढ़ाई
- 56 प्रतिशत से ज्यादा गोल्ड लोन पुरुषों ने लिए, कर्ज चुकाने के मामले में महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा

15.6 लाख करोड़ रुपये रहा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो नवंबर 2025 में

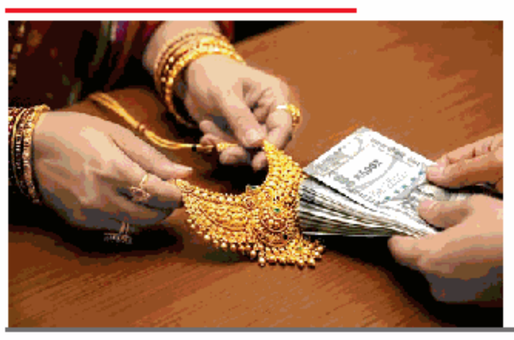

7.9 लाख करोड़ रुपये था कुल गोल्ड लोन नवंबर 2023 के अंत में

कुल गोल्ड लोन में दक्षिणी राज्यों की तीन-चौथाई हिस्सेदारी

अगर गोल्ड लोन को क्षेत्रीय नजरिये से देखें तो तीन-चौथाई हिस्सेदारी दक्षिणी राज्यों की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर, 2025 तक के साल में गुजरात 67 प्रतिशत के साथ पोर्टफोलियो वृद्धि में सबसे आगे रहा, इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र 50 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नहीं चुकाए जाने वाले लोन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।

फिर नए शिखर पर सोना और चांदी

नई दिल्ली, प्रेट्र: कमजोर डालर और वैश्विक बाजार में मजबूत खरीदारी के ट्रेंड के बीच सोना और चांदी बुधवार को नए उच्चस्तर पर पहुंच गए। चांदी ने लगातार तीसरे दिन अपनी बढ़त जारी रखी और 15,000 रुपये या 4.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में सफेद धातु शुक्रवार के 3,29,500 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद भाव से 40,500 रुपये बढ़कर 3,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। सोना भी सर्राफा बाजारों में 5,000 रुपये या 3 प्रतिशत बढ़कर 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चस्तर पर पहुंच गया। मंगलवार को यह कीमती धातु 1,66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि सोने और चांदी में लगातार और मजबूत रैली देखी जा रही है और तेजड़ियों को कीमतों को ऊपर ले जाने के लिए लगभग हर दिन नए कैटेलिस्ट मिल रहे हैं। गांधी ने कहा कि इस तेजी को मुख्य रूप से बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव और लगातार ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं से समर्थन मिल रहा है, जिससे सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है।

5,000 रुपये बढ़कर 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चस्तर पर पहुंची पीली धातु

15,000 रुपये की बढ़त के साथ 3,85,000 रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची चांदी

भारत-ईयू समझौता: दूसरे दिन भी सेंसेक्स 487 अंक चढ़ा

मुंबई, प्रेट्र: भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को लेकर उत्साहित सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 487.20 अंक बढ़कर 82,344.68 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 646.49 अंक चढ़कर 82,503.97 पर पहुंच गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 167.35 अंक बढ़कर 25,342.75 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, भारत इलेक्ट्रानिक्स दिसंबर तिमाही की कमाई के बाद लगभग नौ प्रतिशत बढ़ा। इटरनल, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट दूसरे बड़े फायदे में रहे।

अब ईयू बनेगा भारतीय स्मार्टफोन का बड़ा बाजार

समझौते पर अमल के बाद पांच साल में 50 अरब डालर तक जा सकता है इलेक्ट्रानिक्स निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ व्यापार समझौते पर अमल होने पर ईयू अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन सकता है। ईयू में फिलहाल भारतीय स्मार्टफोन व अन्य इलेक्ट्रानिक्स आइटम के निर्यात पर 14 प्रतिशत शुल्क लगता है। व्यापार समझौते पर अमल के बाद यह शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे ईयू के बाजार में भारतीय इलेक्ट्रानिक्स आइटम काफी सस्ती हो जाएंगे और ईयू के बाजार में चीन, वियतनाम जैसे देशों से आने वाले इलेक्ट्रानिक्स आइटम से भारतीय आइटम आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। गत मंगलवार को भारत व ईयू के बीच व्यापार समझौते की सफल वार्ता पूरी होने पर आगे की प्रक्रिया के लिए हस्ताक्षर किए गए।

इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन का अनुमान है कि ईयू के साथ व्यापार समझौते से वर्ष 2035 तक भारत का ईयू में होने वाल इलेक्ट्रानिक्स निर्यात 100 अरब डालर तक पहुंच सकता है। वर्तमान में ईयू के बाजार में भारत का इलेक्ट्रानिक्स निर्यात 12 अरब डालर का है और इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी स्मार्टफोन की है। ईयू सालाना 750 अरब डालर के इलेक्ट्रानिक्स आइटम का आयात करता है और इस हिसाब से ईयू के बाजार में भारतीय इलेक्ट्रानिक्स आइटम के निर्यात को बढ़ाने की पूरी गुंजाइश है और शुल्क में 14 प्रतिशत तक की कटौती से इसमें मदद मिलेगी। अभी भारत में बनने वाले आइफोन का सबसे अधिक निर्यात अमेरिका में होता है। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि ईयू में 27 देश हैं और इनसे जुड़े कई देशों की प्रति व्यक्ति आय 30 हजार डालर से अधिक है। इसलिए ईयू में एपल के आइफोन बिक्री बढ़ने की पूरी संभावना है।

- भारत के इलेक्ट्रानिक्स निर्यात में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक
- ईयू की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने से आइफोन की बिक्री बढ़ने की संभावना

12 अरब डालर है वर्तमान में ईयू के बाजार में भारत का इलेक्ट्रानिक्स निर्यात

750 अरब डालर के इलेक्ट्रानिक्स आइटम का आयात करता है ईयू अभी

दूसरे देशों की कंपनियां भारत में करेंगी अधिक निवेश

जानकारों का कहना है कि ईयू के साथ व्यापार समझौता होने से दूसरे देशों की इलेक्ट्रानिक्स कंपनियां और अधिक भारत में निवेश करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें अब यूरोप का बाजार भी दिखाई देगा। जापान, ताइवान की कंपनियां भारत में इलेक्ट्रानिक्स आइटम के लिए अलग से निवेश कर सकती हैं। इस समझौते से इलेक्ट्रानिक्स आइटम बनाने वाली भारतीय कंपनियों को कच्चे माल भी कम दाम पर मिल सकेंगे। ईयू इलेक्ट्रानिक्स आइटम के पार्ट्स का सप्लायर है, लेकिन अभी ईयू से उन्हें आयात करने पर शुल्क देना पड़ता है। समझौते पर अमल के बाद यह शुल्क समाप्त हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग की लागत कम हो जाएगी। अभी इलेक्ट्रानिक्स आइटम के कच्चे माल के लिए भारत मुख्य रूप से चीन पर निर्भर करता है।

एमएसएमई के लिए व्यापार के नए मौके खुलेंगे: पीएचडीसीसीआइ

नई दिल्ली, एएनआइ: ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते से माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए व्यापार के नए मौके खुलेंगे और यह देश के आर्थिक माहौल में एक बड़ा बदलाव लाएगा। पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआइ) के सीईओ और सेक्रेटरी जनरल रणजीत मेहता के मुताबिक, यह समझौता इंडियन इंडस्ट्रीज़ को 23 ट्रिलियन डालर वाले एक समूह से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। मेहता ने कहा कि इस समझौते से टेक्सटाइल, अपैरल, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों को पक्का फायदा होगा और इससे हमारे देश में नौकरी के मौके भी खुलेंगे। भारत और ईयू दुनिया की इकोनमी का लगभग 25 प्रतिशत है।

भारत के लिए सकारात्मक असर लाएगा ईयू से एफटीए

नई दिल्ली, प्रेट्र: मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए सकारात्मक असर लेकर आएगा। उसका मानना है कि इस समझौते से कम टैरिफ और बेहतर बाजार पहुंच से विदेशी निवेश को आकर्षित करने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और रोजगारपरक सेक्टर की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और ईयू ने बुधवार को एफटीए के लिए बातचीत खत्म होने का एलान किया था और इसे 'मदर आफ आल डील्स' बताया गया है। इसके तहत 93 प्रतिशत भारतीय निर्यात को 27 देशों के इस ब्लाक में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी जबकि ईयू से लक्जरी कारों और वाइन का आयात सस्ता होगा। लगभग दो दशकों तक चली बातचीत के बाद यह समझौता पूरा हुआ है और इससे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनमी भारत और दूसरे सबसे बड़े इकोनमिक ब्लाक ईयू को मिलाकर दो अरब लोगों का बाजार बनेगा।

मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि ईयू के साथ भारत की ट्रेड बातचीत का पूरा होना व्यापार रिश्तों में विविधता लाने की उसकी लगातार कोशिशों को दिखाता है। इस मुक्त व्यापार समझौते पर इस साल हस्ताक्षर होने और इसके लागू होने की उम्मीद है।

मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि ईयू आयात पर कम टैरिफ से लागत कम करने में भी मदद मिल सकती है। मूडीज ने कहा कि यूरोपियन कार बनाने वालों को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में आसानी से पहुंच मिलेगी, जिससे वे ज्यादा प्रीमियम माडल पेश कर पाएंगे।

- मूडीज रेटिंग्स ने कहा-कम टैरिफ और बेहतर बाजार पहुंच से एफडीआइ आकर्षित होगा
- मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगारपरक सेक्टर की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी

दिसंबर में 7.8 प्रतिशत रही औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर

नई दिल्ली, प्रेट्र: खनन, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के दम पर भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर दिसंबर 2025 में दो साल से अधिक के उच्च स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़ा था।

आधिकारिक बयान में कहा गया, 'दिसंबर 2025 में औद्योगिक गति और मजबूत हुई क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7.8 प्रतिशत बढ़कर दो वर्ष से अधिक के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। नवंबर 2025 में इसमें 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने नवंबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के अनुमान 6.7 प्रतिशत को संशोधित करके 7.2 प्रतिशत कर दिया है।

बजट में शामिल होंगी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें

नई दिल्ली, प्रेट्र: एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी शामिल होंगी। आयोग अपनी रिपोर्ट पहले ही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को सौंप चुका है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह पांच साल के लिए केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे का एक फार्मूला प्रदान करता है। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया की अगुआई में 16वां वित्त आयोग 31 दिसंबर, 2023 को बनाया गया था। हालांकि, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों को मानती रही है।

एनके सिंह के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यों को पांच साल के समय के लिए केंद्र के बांटे जा सकने वाले टैक्स पूल का 41 प्रतिशत दिया जाए, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा सुझाव गए स्तर के बराबर है। पहले वित्त आयोग ने आबादी, क्षेत्रफल, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश और आय असमानता के आधार पर केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा तय किया था। कर बंटवारे का मुद्दा लंबे समय से केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों में टकराव का मुद्दा रहा है।

अपनी रिपोर्ट पहले ही राष्ट्रपति को सौंप चुका है आयोग, केंद्र-राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे का फार्मूला प्रदान करता है आयोग

एक सप्ताह में दूसरी बार रुपये ने छुआ सर्वकालिक निचला स्तर

मुंबई, प्रेट्र: बुधवार को डालर के मुकाबले रुपया 31 पैसे गिरकर 91.99 पर बंद हुआ। इससे पहले 23 जनवरी को भी रुपया इसी स्तर पर बंद हुआ था। एक सप्ताह में दूसरी बार है जब रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है।

यूरोप के साथ ट्रेड डील से राहत मिलने से रुपया बढ़त के साथ खुला। हालांकि, डालर की बढ़ती मांग और चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने निवेश धारणा पर असर डाला। रुपया 91.60 पर खुला और 91.50 के शुरुआती हाई लेवल को छुआ, लेकिन सारी बढ़त गंवाकर डालर के मुकाबले 91.99 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को रुपया डालर के मुकाबले 22 पैसे मजबूत होकर 91.68 पर बंद हुआ था।

2025 में एटीएम से नकद निकासी घटी

मुंबई, प्रेट्र: वर्ष 2025 में एटीएम से नकदी निकालने में कमी आने के संकेत मिले हैं। हालांकि, नकदी निकालने का औसत आकार पहले से ज्यादा रहा है। आटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) का प्रबंधन संभालने वाली सीएमएस इन्फो सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में देशभर में प्रत्येक एटीएम से हर महीने औसतन 1.21 करोड़ रुपये नकदी निकाली गई जबकि 2024-25 में यह 1.30 करोड़ रुपये था। 73,000 एटीएम का प्रबंधन संभालने वाली यह कंपनी अब तक वित्त वर्ष के हिसाब से आंकड़ों को साझा करती थी, लेकिन अब इसने कैलेंडर वर्ष के तहत आंकड़ों को साझा करना शुरू किया है।

सीएमएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक में प्रत्येक एटीएम से सबसे ज्यादा 1.73 करोड़ रुपये निकाले गए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सबसे कम 83 लाख रुपये निकाले गए। कंपनी ने कहा कि अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में एटीएम से नकदी निकालने का रुझान ज्यादा दिखाई दिया। 2025 में जहां प्रत्येक मशीन से 1.30 करोड़ रुपये निकाले गए जबकि मेट्रो इलाकों में यह आंकड़ा 1.18 करोड़ रुपये और शहरी इलाकों में 1.11 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने खपत के माहौल पर भी रुझान को साझा किया है। इसमें पिछले साल सितंबर में जीएसटी सुधारों के बाद हुए बदलावों की तरफ इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में इंश्योरेंस का खर्च 25 प्रतिशत के साथ दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होगा। सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों के चलते इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

- देशभर में प्रत्येक एटीएम से हर महीने औसतन 1.21 करोड़ रुपये नकदी निकाली गई
- अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में एटीएम से नकदी निकालने का रुझान ज्यादा दिखा

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अब आधार एप से ही अपडेट कर सकेंगे अपना मोबाइल नंबर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने व आधार से जुड़ी सेवाएं सरल बनाने के लिए नया आधार एप लांच किया है। इसकी मदद से अब आप अपना मोबाइल फोन नंबर घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं। आधार एप पर चेहरे के सत्यापन से मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।

अभी होटल बुकिंग, एयरपोर्ट या अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड का फिजिकल कापी मांगा जाता है। इससे आपका पता, आपके पिता के नाम जैसी जानकारी भी दूसरे के पास चली जाती है। अब सेवा प्रदाता को सिर्फ अपना नाम व उम्र एप के जरिये ही दे सकेंगे। फिजिकल कापी का दुरुपयोग रोकने के लिए आधार एप लांच किया गया है। इस एप पर आफलाइन भी आधार वेरिफिकेशन हो सकेगा। यूआइडीएआइ ने यह एप औपचारिक रूप से बुधवार को लांच किया, परंतु अब तक एक करोड़ लोग एप को डाउनलोड कर चुके हैं। गूगल, सैमसंग, गुजरात पुलिस जैसी कई एजेंसियां व कंपनियां आधार एप से जुड़ गई हैं। गूगल और सैमसंग ने अपना वालेट आधार एप से जोड़ा है। आधार एप में डिजिटल प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। किसी के डिजिटल डाटा को उसकी सहमति के बगैर शेयर नहीं किया जा सकेगा। एप पर यह विकल्प भी दिया है कि कोई यूजर तय करे कि वह किस सीमा तक अपना डाटा शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है।

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लांच किया है नया आधार एप, आधार की फिजिकल कापी का दुरुपयोग रोकने को उठाया कदम

नए एप की खूबियां

- एप से ही चेहरे के सत्यापन से मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा
- एयरपोर्ट पर भी एप के माध्यम से करा सकेंगे अपनी पहचान
- बिना किसी झंझट के होटल व रेस्तरां बुकिंग में होगी आसानी
- एप से बैंकों के जुड़ने से यूजर आनलाइन खाता खोल सकेंगे

एअर इंडिया विमान हादसे से संबंधित अपीलों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे की आधिकारिक जांच में खामियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को सहमति दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने इन याचिकाओं पर विचार करने का निर्णय लिया है। इनमें आरोप लगाया गया है कि वर्तमान जांच नागरिकों के जीवन, समानता और सच्ची जानकारी प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही एअर इंडिया की बोइंग 787-8 फ्लाइट एआइ171 उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 241 यात्रियों व चालक दल के सदस्यों सहित 260 लोगों की मौत हो गई थी। जनहित याचिका दायर करने वाले एनजीओ 'सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन' की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि अब तक न तो केंद्र सरकार और न ही विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने याचिका पर जवाब दाखिल किया है।

'लेडी फार्मर' ने औषधीय पौधों की खेती से खोली तरक्की की नई राह

जागरण विशेष

नरेंद्र शर्मा ● जागरण

राजस्थान के झालावाड़ जिले की सोनिया ने परंपरागत खेती की जगह अपनाए नए तरीके

जयपुर: राजस्थान के झालावाड़ जिले की महिला किसान सोनिया जैन ने परंपरागत खेती के स्थान पर औषधीय पौधों की खेती को अपनाकर अपने लिए व अन्य किसानों के लिए तरक्की की नई राह प्रशस्त की है। उन्होंने कुसुम के फूलों, सफेद मुसली, ईसबगोल व शतावरी जैसे औषधीय पौधों के साथ सब्जियों की खेती शुरू की है। वह मार्केटिंग व प्रोसेसिंग का कार्य स्वयं करती हैं। सोनिया ने किसानों व कंपनियों के बीच बिचौलियों को हटाने के लिए खुद का ब्रांड 'दी लेडी फार्मर' नाम से बनाया है। वह अपने उत्पादों को इसी नाम से बाजार में उतार रही हैं।

औषधीय गुणों वाले कुसुम के फूलों की खेती को पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की उपज माना जाता था, लेकिन अब झालावाड़ में सोनिया की मेहनत से इसे सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। उनके खेत में प्रतिवर्ष लगभग 500 किलोग्राम कुसुम के फूल और एक हजार किलो बीज का उत्पादन होता है। इन फूलों से वह हर्बल चाय व बीजों से कुसुम का तेल तैयार करती हैं। महिला किसान का दावा है कि कुसुम चाय स्वास्थ्यवर्धक व आर्गेनिक है, जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत कम होती है। उनका मानना है कि यह चाय विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी है, क्योंकि मासिक धर्म में महिलाओं में होने वाली मैग्नीशियम व आयरन की कमी को पूरा करती है। यह चाय पाचन सुधारने, तनाव कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। वहीं, कुसुम का तेल कोलेस्ट्राल कम करने, ब्लड शुगर नियंत्रण, बालों व त्वचा की देखभाल व भोजन में भी होता है।

300 किसानों को साथ जोड़ा: झालावाड़ के गांव बालदा निवासी सोनिया ने 300 किसानों को अपने साथ जोड़ा है। उन्हें प्रशिक्षित कर उनके खेतों की उपज भी बढ़ाई है। उनका अपने काम से लगाव इतना गहरा है कि सिंगापुर में नौकरी कर रहे पति से कुछ समय के लिए दूर रहकर गांव में खेती का निर्णय लिया। प्रारंभ में उन्होंने परंपरागत रास्ता अपनाया, लेकिन बिचौलियों की समस्याओं व मौसम की मार से परेशान हो औषधीय फसलों की खेती का नवाचार किया। पाली हाउस, नेट हाउस व आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर खेती को टिकाऊ व लाभकारी बनाया। गांव में पांच हजार टन क्षमता का एक वेयरहाउस और पैकेजिंग कारखाना स्थापित किया है। वह पतंजलि समूह को कच्चा माल मुहैया करा रही हैं। वह औषधियों के लिए मूली की राख बेचकर भी कमा रही हैं।

नवाचार के लिए युवाओं को कर रहीं प्रेरित

लगभग 12 वर्षों से सोनिया जैन जैविक खाद के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में जुटी हैं। वह ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के साथ ही युवाओं को परंपरागत खेती के बजाय नवाचार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्हें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और राजस्थान सरकार की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। उनके नवाचारों से होते लाभ को देखने के लिए अब देश के विभिन्न राज्यों से कृषि विज्ञानी नियमित रूप से पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं झालावाड़ के पिछड़े इलाकों के किसानों की तकदीर बदलना चाहती हूं। सोनिया ने अपने कार्यों से कई लोगों को प्रेरित किया है। उनकी सफलता का राज केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और कृषि को टिकाऊ बनाना भी है।

राजस्थान में झालावाड़ की सोनिया जैन खेत में महिला किसानों के साथ ● जागरण

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

चिंतन

पवार हादसा और वीवीआईपी हवाई सुरक्षा पर उठते सवाल

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु केवल एक व्यक्ति की असमय विदाई नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर कठोर प्रश्नचिह्न है, जो वीवीआईपी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताती है पर व्यवहार में बार-बार असफल होती दिखाई देती है। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ यह हादसा, जिसमें पवार सहित पांच लोगों की जान चली गई। देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि तकनीक, नियम और निगरानी के बीच कहीं गंभीर चूक है, जो वीवीआईपी समेत आमजन पर भी भारी पड़ती है। प्रारंभिक तथ्यों के अनुसार, विमान ने लैंडिंग की पहली कोशिश असफल होने पर दोबारा उतरने का प्रयास किया। दूसरी कोशिश में विमान रनवे से पहले ही गिर पड़ा और आग लग गई। न आपात संकेत भेजा गया, न 'मेडे' कॉल। तकनीकी खराबी और लैंडिंग गियर की समस्या की आशंका जताई जा रही है। फिर भी, यह प्रश्न अभी से उठ खड़ा हुआ है कि क्या वीवीआईपी उड़ानों में जोखिम-प्रबंधन उतना सुदृढ़ है, जितना दावा किया जाता है। यह हादसा किसी एक क्षण की गलती का परिणाम हो सकता है पर इसके पीछे की पृष्ठभूमि लंबी है। छोटे हवाई अड्डों की सीमित संरचना, निजी चार्टर सेवाओं की निगरानी, मौसम और नेविगेशन सूचना की गुणवत्ता और सबसे अहम, निर्णय लेने की प्रक्रिया में दबावों की भूमिका। जब उड़ानें समय-सारिणी और राजनीतिक कार्यक्रमों से बंध जाती हैं तो क्या सुरक्षा के निर्णयों पर अनकहा दबाव बनता है? यह पहली बार नहीं है, जब भारत ने विमान हादसों में अपने नेतृत्व को खोया है। अजित पवार की दुर्घटना हमें उन पुराने जख्मों की याद दिलाती है, जो समय के साथ भी भरे नहीं हैं। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, जी.एम.सी. बालयोगी, वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, सीडीएस बिपिन रावत, होमी जहांगीर भाभा, विजय रूपाणी और ओपी जिंदल व चौधरी सुरेंद्र सिंह जैसे नाम केवल व्यक्ति नहीं, संस्थागत क्षति के प्रतीक थे। हर बार शोक व्यक्त हुआ, जांच बैठी, रिपोर्टें आईं पर क्या व्यवस्थागत सुधार स्थायी रूप से लागू हुए? यदि होते, तो ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों दोहरातीं? यह केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रश्न है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जीवन निजी नहीं होता। उनका अस्तित्व शासन की निरंतरता, नीति-निर्माण और सार्वजनिक हित से जुड़ा होता है, इसलिए, उनकी सुरक्षा को भावनात्मक सहानुभूति के बजाय संस्थागत जिम्मेदारी के रूप में देखना होगा। वीवीआईपी उड़ानों के लिए स्वतंत्र और नियमित सुरक्षा ऑडिट, पायलट के निर्णय की पूर्ण स्वायत्तता, आधुनिक नेविगेशन और लैंडिंग सहायता प्रणालियों की अनिवार्यता ये अब विकल्प नहीं, आवश्यक शर्तें हैं। विशेषकर छोटे हवाई अड्डों पर संरचनात्मक मानकों की समीक्षा जरूरी है। रनवे की दृश्यता, ग्राउंड-सपोर्ट सिस्टम, मौसम-डेटा की रियल-टाइम उपलब्धता और आपात प्रतिक्रिया की तैयारी इन सब पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। निजी चार्टर कंपनियों पर भी वही सख्त नियम लागू होने चाहिए जो वाणिज्यिक उड़ानों पर होते हैं और उल्लंघन पर दंड केवल कागजी न रहकर वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए। नागर विमानन मंत्रालय को एक व्यापक 'नेशनल वीवीआईपी एयर सेफ्टी पॉलिसी' लागू करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस त्रासदी से व्यवस्था बदले, ताकि भविष्य में कोई उड़ान, कोई जीवन और कोई जिम्मेदारी इस तरह अधर में न रहे।

नमन

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

राजनीति के अनुभवी स्तंभ थे अजित पवार

अजित पवार, जो दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तम्भ रहे हैं, विमान लैंडिंग हादसे का शिकार हो गए। उनकी पहचान केवल एक राजनेता के तौर पर नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें जनता ने 'दादा' कहकर सम्मान दिया। इस संबोधन में एक भावनात्मक जुड़ाव झलकता था- एक ऐसा सम्मान जो वे वर्षों के जन-समर्थन, बातचीत और कार्यों के कारण अर्जित कर पाए थे। उनकी कार्यशैली तेज, निर्णायक और प्रभावशाली रही। वे हमेशा जनता के बीच संवाद बनाए रखने में विश्वास रखते थे। पवार का अचानक और अप्रत्याशित निधन न केवल एक नेता की मृत्यु है, बल्कि महाराष्ट्र राजनीति के एक अद्वितीय अध्याय का अंत भी है।

बुधवार की सुबह, जब महाराष्ट्र की राजनीति नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाली थी, एक ऐसी खबर ने सबको हैरान कर दिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अजित पवार, जो दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तम्भ रहे हैं, अपने निजी विमान से बारामती की ओर जा रहे थे, तब उनका विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पवार सहित सभी सवारों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक अधिकारियों के अनुसार लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और रनवे के पास ही जोरदार टक्कर के साथ क्रैश-लैंड हो गया, जिससे यह भयावह दृश्य बना।

यह दुर्घटना राज्य के लिए एक बड़ा सदमा है, जिसने राजनीतिक, प्रशासनिक और जनता के सामूहिक मन को झकझोर दिया है। अजित अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली-प्रवरा में हुआ था। वह एक राजनीतिक परिवार से थे, जिनके चाचा शरद पवार भारतीय राजनीति के अग्रणी नेतृत्व रहे हैं। युवा अवस्था से ही उन्होंने राजनीति में रुचि विकसित की और समाज सेवा तथा संगठनवाद में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक सफ़र सहकारी आंदोलन से शुरू हुआ। 1982 से उन्होंने स्थानीय और ग्रामीण राजनीतिक कार्यों में भाग लिया और जल्दी ही अपने तेज संगठनात्मक कौशल के कारण लोकप्रिय हो गए। 1991 में उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद वे महाराष्ट्र राजनीति के केंद्र में आ गए। उनकी राजनीतिक यात्रा केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में 16 वर्ष तक काम किया, जहां से उन्हें ग्रामीण और सहकारी क्षेत्रों में व्यापक समर्थन मिला। इससे उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बनाया गया। वह बारामती निर्वाचन क्षेत्र से कई बार लगातार विधायक चुने गए और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे कृषि, बागवानी, बिजली, जल संसाधन और वित्त एवं योजना मंत्रालयों का नेतृत्व किया। विशेष रूप से जल संसाधन विभाग में उन्होंने कृष्णा घाटी तथा कोकण सिंचाई जैसी परियोजनाओं पर काम किया, जिससे कृषि-आधारित समुदायों को व्यापक लाभ हुआ। अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनूठा योगदान दिया। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत से राज्य के शासन में कई महत्वपूर्ण पद संभाले और विविध सरकारों में अपना स्थान बनाए रखा। 2010 में उन्हें पहली बार उपमुख्यमंत्री का पद प्राप्त हुआ, लेकिन 2013 में सिंचाई घोटाले के आरोपों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में क्लीन चिट मिलने के बाद वे फिर से पद पर लौट आए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक चुनौतियों ने भी उनके सामर्थ्य को कम नहीं किया। आज वह महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपमुख्यमंत्रियों में से एक माने जाते थे, और उनके प्रशासनिक कौशल तथा संगठन शक्ति की वजह से उन्हें विशेष सम्मान मिला। उनके योगदान ने कई योजनाओं और नीतियों को आकार दिया, जिससे राज्य के विकास की दिशा प्रभावित हुई।

राजनीति में किसी भी नेता का सफ़र विवादों से मुक्त नहीं रहता और पवार भी इससे अछूते नहीं थे। 2013 में

दिया गया एक विवादित बयान जब आलोचना की भेंट चढ़ा, तब उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने के आरोप भी लगे। समय-समय पर भ्रष्टाचार तथा पद दुरुपयोग के मुद्दों ने भी उनके राजनीतिक जीवन को जटिल बना दिया। लवासा लेक सिटी जैसी परियोजनाओं में कथित मदद के आरोपों ने भी उनके व्यवहार को लेकर सुर्खियां बनाईं। इन विवादों के बावजूद उनका जन-समर्थन और राजनीतिक प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि उनके प्रशंसकों का मानना रहा कि प्रशासनिक क्षमता तथा संगठनात्मक कौशल ने उनके विवादों को परास्त किया। उनकी राजनीतिक छवि अक्सर विरोधाभासी रही, जहां एक ओर आलोचक उन्हें कठोर राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल मानते थे, वहीं समर्थक उन्हें एक कुशल, अनुभवी और लोक-सम्मानित नेता के रूप में देखते थे। इसी विरोधाभासी छवि ने उन्हें महाराष्ट्र राजनीति का एक मजबूत स्तम्भ बनाया। अजित पवार की पहचान केवल एक राजनेता के तौर पर नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें जनता ने "दादा" कहकर सम्मान दिया। इस संबोधन में एक भावनात्मक जुड़ाव झलकता था- एक ऐसा सम्मान जो वे वर्षों के जन-समर्थन, बातचीत और कार्यों के कारण अर्जित कर पाए थे। उनकी कार्यशैली तेज़, निर्णायक और प्रभावशाली रही। वे हमेशा जनता के बीच संवाद बनाए रखने में विश्वास रखते थे। बारामती और उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने जल कृषि, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश के माध्यम से उन समुदायों को सीधे रूप से लाभ पहुंचाया। उनके नेतृत्व में कई योजनाएं और बजट पर निर्णय महाराष्ट्र की आर्थिक दिशा में स्थिरता और विकास का आधार बने। उनका नाम कई बार राज्य के बजट तैयार करने वाले नेता के रूप में भी सामने आया, क्योंकि उन्होंने वित्तीय मामलों में गहरी समझ और विस्तृत बारीकी दिखाई। अजित पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में थे जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब-जब भी गठबंधन सरकारों के बीच सत्ता के समीकरण बदलते, पवार अपनी समझदार रणनीतियों के कारण राजनीतिक निर्णयों पर असर डालते रहे। उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ ने अक्सर नीतिगत दिशा को प्रभावित किया, और कई बार गठबंधन निर्णय उनके प्रभाव के बिना सम्भव नहीं थे। यह अकेला कोई कार्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक कला थी, जिसमें उन्होंने संगठन शक्ति, कौशल और प्रशासनिक अनुभव को शासकीय निर्णयों के साथ जोड़कर एक संगठित राजनीति की मिसाल पेश की। कई विश्लेषक मानते हैं कि उनके अनुभव की वजह से शासन-प्रशासन में संतुलन बन रहा था और निर्णय लेने में उनकी भूमिका निर्णायक थी।

आज पवार के अचानक निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक विशाल खालीपन महसूस किया जा रहा है। एक ऐसा नेता जिसने न केवल राजनीतिक मशीनरी को समझा, बल्कि उसे दिशाहीन समयों में भी मजबूती से थामा, अब नहीं रहे। उनकी मौत से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति केवल पदों और शक्ति का नाम नहीं है; यह एक जन-सम्बंध, प्रशासन क्षमता, दूरदर्शिता और संघर्ष का मिश्रण है। पवार ने इन सभी चरित्रों को अपने जीवन में बख़ूबी अपनाया और महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में अपनी एक स्थायी पहचान बनाई। आज वे नहीं हैं, पर उनकी याद, चर्चा और उनके कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक राजनीति के परिदृश्य पर देखा जाएगा। अजित पवार का अचानक और अप्रत्याशित निधन न केवल एक नेता की मृत्यु है, बल्कि महाराष्ट्र राजनीति के एक अद्वितीय अध्याय का अंत भी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

आर्थिकी

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

विकास केंद्रित रणनीतिक बजट की उम्मीद

इन दिनों पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट की ओर लगी हुई है। सीतारमण का यह नौवां बजट होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में जहां भारत के यूरोपीय संघ (ईयू) सहित विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कारोबार और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में साहसिक सुधारों की गति बढ़ाने की रणनीति होगी, वहीं 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण से खपत और व्यय बढ़ाकर विकास दर बढ़ाने की भी विशेष रणनीति होगी। साथ ही गरीब, युवा, महिलाएं, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), हरित ऊर्जा और आर्थिक सुधारों पर बड़े ऐलान दिखाए देंगे। वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और 7.5 फीसदी विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण के समक्ष वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करते समय चुनौतियों की श्रृंखला सामने है। वर्ष 2026-27 में राज्यों के साथ संसाधनों के बंटवारे को लेकर सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा। इन चुनौतियों के बावजूद इस समय वित्त मंत्री की मुट्ठियों में विभिन्न वर्गों को राहत देने और विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रभावी आवंटन हेतु कर संग्रहण संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद हैं। चालू वित्त वर्ष के तहत 7.4 फीसदी विकास दर प्राप्ति के संकेत अच्छे आर्थिक परिदृश्य के प्रतीक हैं। चालू वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में प्रभावी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर 2024 तक आयकर सहित प्रत्यक्ष कर संग्रहण 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 8 फीसदी से भी ज्यादा है। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री आगामी वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12 से 12.5 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचाते हुए दिखाई देंगी। नए बजट में महिलाओं के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड, ऋण तथा बीमा प्लान की घोषणाएं हो सकती हैं।

नए बजट में वित्त मंत्री रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, पीएलआई योजना का दायरा बढ़ाने, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दे सकती हैं। प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना की शुरुआत संभावित है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण पर अधिक आवंटन संभावित है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और क्षमता संवर्धन के साथ दीर्घावधि वृद्धि को बनाए रखने, वैश्विक क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड के नए सुधार नए बजट के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेंगे। साथ ही आगामी बजट के माध्यम से वित्त मंत्री सीतारमण तेज विकास के लिए जरूरी और वित्तीय सुधारों को लागू करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने संबंधी बुनियादी रणनीतियां प्रस्तुत करते हुए दिखाई देंगी। यह भी संभावना है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री युवाओं के बीच रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों से सजाते हुए दिखाई दे सकती हैं। वित्त मंत्री सीतारमण नए बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा बढ़ाने और खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। वित्त मंत्री तेज रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित कर सकती हैं। उम्मीद करें कि नया बजट आम आदमी के लिए राहत, बाजार के लिए रफ्तार और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट होगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गलत सोच का चश्मा जल्दी उतार देना चाहिए

संकलित

दर्शन

जब सोच निषेधात्मक या गलत होती है, तब वह सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देती है। गलत सोच का चश्मा जितनी जल्दी हो, उतार देना चाहिए। बुरे विचार जितना दूसरों का नुकसान करते हैं, उतना ही स्वयं का भी करते हैं। कारण अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरा दिमाग ढंग से नहीं सोच पाता। हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। कहा गया है कि आपके विचार वहां तक ले जाते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। पर कमजोर विचारों में दूर तक ले जाने की ताकत नहीं होती। हम जो हैं वह सब विचारों का फल है। जो हम सोचते हैं, वही बन जाते हैं। मनुष्य अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अपने विचारों से स्वयं को। गलत सोच एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को धनवान और प्रतिष्ठित होते देख आदमी में नकारात्मक चिंतन जागता है। अपनी ईमानदारी उसे मूर्खतापूर्ण लगती है। वह पुनर्चिंतन करता है-क्या मिला मुझे आदर्शों पर चलकर? यह नकारात्मक चिंतन उसे भी गलत सोच के दलदल में उतार देता है। समाज में भ्रष्ट और बेईमान लोगों की उत्पत्ति इसी तरह के गलत विचारों के संक्रमण से हुई। इस तरह का गलत सोच हमारी दुनिया को छोटा कर देता है। भीतर और बाहरी दोनों ही दुनिया सिमट जाती हैं। तब हमारी छोटी-सी सफलता अहंकार बढ़ाने लगती है। थोड़ा-सा दुख अवसाद का कारण बन जाता है। कुल मिलाकर सोच ही गड़बड़ हो जाता है। अपने ही बोले हुए को सुनते रहना ज्यादा सीखने नहीं देता।

तुलसीदास जी द्वारा श्रीराम के दर्शन का उपाय

संकलित

प्रेरणा

एक ब्राह्मण दिनभर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम-राम रटता। संध्या के समय श्रीहनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक बार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा- उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए। ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहाः आप समर्थ महापुरुष है, आप भगवान के दर्शन करवा सकते है। वह हठ पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहाः ठीक है यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे त्रिशूल गाढ़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पडो। भगवा- के दर्शन हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाडकर वृक्षपर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं हुई। एक घुडसवार उधर से जा रहा था, उसने पूछाः पेड़ पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोलाः तुलसीदास जी ने कहा है पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो तुम्हे भगवान श्रीराम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा- क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला- जी हां ! वह व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्रीराम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्त्वज्ञान का उपदेश भी दिया। गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा था, जिनमें प्रेम-भाव हो एवं संत की कृपा हो वही भगवान के दर्शन पाता है।

अंतर्मन

आज की पाती

लाला लाजपतराय जी का प्रेरणादायक जीवन

भारत में बहुत से महापुरुष हुए। इन महापुरुषों ने भारत को ही नहीं, बल्कि दुनिया को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत से काम किए और दुनिया के लिए प्ररेक बनें। इन्हीं में से एक थे लाला लाजपतराय। उनका जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब में हुआ था। वह लेखक, वकील, क्रांतिकारी और बहुत से अच्छे गुणों से परिपूर्ण थे। उनका देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध वर्ष 1928 में किया था। इस विरोध के कारण उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। उन्हें पंजाब का शेर और पंजाब केसरी की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने आर्य समाज के लिए भी काम किया था। उनकी जयंती पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है।

- प्रतीक जैन, धमतरी

फोन हैकिंग के प्रयास को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता?

आज का मोबाइल फोन केवल कॉल करने या संदेश भेजने का साधन नहीं है। यह हमारी डिजिटल पहचान, आर्थिक सुरक्षा, निजता, सामाजिक प्रतिष्ठा और कई बार व्यक्तिगत सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। इसके बावजूद जब किसी व्यक्ति द्वारा फोन हैक करवाने या उसका प्रयास किए जाने की शिकायत सामने आती है, तो उसे अक्सर यह कहकर टाल दिया जाता है कि, "हैक तो हुआ नहीं, नुकसान क्या हुआ?" यही सोच इस पूरे विषय की सबसे बड़ी और खतरनाक भूल है। अपराध परिणाम से नहीं, इरादे और प्रयास से तय होता है। कानून में अपराध की परिभाषा केवल इस बात से नहीं होती कि अंतिम परिणाम क्या रहा, बल्कि इस बात से होती है कि इरादा (**Mens Rea**) क्या था और प्रयास (**Attempt**) किया गया या नहीं। जिस प्रकार- हत्या का प्रयास भी अपराध है, चोरी का प्रयास भी दंडनीय है। उसी प्रकार फोन हैक करने का प्रयास भी एक गंभीर साइबर अपराध है, भले ही वह तकनीकी कारणों से सफल न हो पाया हो। इसके बावजूद व्यवहार में **FIR** दर्ज नहीं होती, मामला **Non Cognizable** बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, पीड़ित को मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से अकेला छोड़ दिया जाता है, यह प्रवृत्ति कानून की भावना के विपरीत है।

फोन हैकिंग : कानूनी रूप से कितना मजबूत मामला है

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत फोन हैकिंग या उसके प्रयास पर कई सशक्त धाराएँ लागू होती हैं। धारा 43 / 66 : बिना अनुमति डिजिटल सिस्टम तक पहुँच। धारा 66**C** : डिजिटल पहचान (**OTP**, **SIM**, अकाउंट) का दुरुपयोग। धारा 66**D** : धोखाधड़ी की नीयत से कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग। धारा 72 : गोपनीयता का उल्लंघन।

इसके अतिरिक्त **IPC** की धाराएँ :419, 420, 506 और महिलाओं के मामलों में 354**D** ,भी परिस्थितियों के अनुसार लागू होती हैं। स्पष्ट है कि कानून में हैकिंग का प्रयास स्वयं में दंडनीय अपराध है, बशर्ते इरादा और तैयारी सिद्ध हो, जो आज के डिजिटल युग में चैट, कॉल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन और बयानों से संभव है। जब एक से अधिक लोग शामिल हों : यह आपराधिक साजिश है। वास्तविकता यह है कि फोन हैकिंग प्रायः किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होती। अक्सर इसमें निर्देश देने वाला तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति (हैकर) और सहयोगी या आर्थिक लेन-देन से जुड़े लोग शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-**B** (आपराधिक साजिश) स्वतः लागू होती है। यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या करवाने पर सहमत होते हैं, तो भले ही अपराध पूर्ण न हुआ हो, साजिश स्वयं एक स्वतंत्र अपराध है। इस पहलू की अनदेखी कर देना अपराधियों को सीधा लाभ पहुंचाता है। "कम पैसे में हैकर लगाया गया" या कम राशि में **hacker** तैयार हुआ काम को अंजाम देने के लिए इसलिए **hacking** संभव ही नहीं है।

एक खतरनाक भ्रम है : अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि हैकर को कम राशि दी गई हो, या भुगतान पूरा न हुआ हो, तो अपराध गंभीर नहीं माना जा सकता। यह धारणा पूरी तरह गलत है।

हैकिंगः एक तकनीकी क्षमता है। यह आवश्यक नहीं कि हर बार पैसे के बदले ही की जाए, तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति इसे मुफ्त में भी कर सकता है। कानून के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने पैसे दिए गए, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि किस उद्देश्य से डिजिटल गोपनीयता में सेंध लगाने का प्रयास किया गया। राशि कम होने से अपराध न तो हल्का होता है, न वैध। *- शारदा सिंह*

करंट अफेयर

कैम्ब्रिज विवि ने भारत में नया शोध केंद्र किया शुरू

ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत में अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए एक नए शोध केंद्र की शुरुआत और शीर्ष स्तर के स्नातक छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रवेश मार्गों की घोषणा की है।

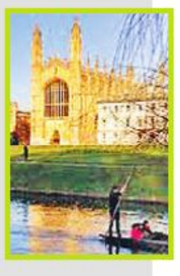

विश्वविद्यालय ने बताया कि 'कैम्ब्रिज -इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज' (सीएएस) नवाचार, शोध और शिक्षण पर केंद्रित होगा तथा ब्रिटेन के अग्रणी विश्वविद्यालय और भारत की तेजी से बढ़ती ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। यह नया केंद्र भारत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में काम करेगा और बौद्धिक आदान-प्रदान, नीति निर्माण में योगदान और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देगा। कैम्ब्रिज की कुलपति डेबोरा प्रेंटिस ने कहा, कैम्ब्रिज -इंडिया सीएएस भारत के श्रेष्ठ शोधकर्ताओं और नवोन्मेषकों के साथ सहयोग स्थापित करने और इस तेजी से बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था के साथ संबंध मजबूत करने का एक रोमांचक अवसर है। इस सप्ताह दिल्ली आए वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं प्रोफेसर प्रेंटिस ने यह भी घोषणा की कि विश्वविद्यालय कुछ स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं के साथ सीबीएसई की 12वीं कक्षा की योग्यता को मान्यता देगा।

ऑफ बीट

कसरत की थकान से उबरने में आइस बाथ है लोकप्रिय

पिछले कुछ साल में 'आइस बाथ' का चलन तेजी से बढ़ा है। दुनिया भर में खुद को स्वस्थ रखने वाले और व्यायाम करने वाले लोग इसे अपना रहे हैं, हालांकि

पहले केवल एथलीट ही इसका उपयोग करते थे। 'आइस बाथ' का मतलब बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़ों से भरे पानी में नहाना है। कसरत की थकान से उबरने के लिए 'आइस बाथ' 'आइस बाथ' लेने का मुख्य कारण मांसपेशियों में दर्द को कम करना और व्यायाम के बाद थकान से उबरना है। धावक, भारोत्तोलक और फुटबॉल खिलाड़ी सहित एथलीट आमतौर पर 'आइस बाथ' का उपयोग करते हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 'आइस बाथ' लेने से कसरत के बाद होने वाली थकान को दूर किया जा सकता है। शोध से पता चला है कि गहन व्यायाम के तुरंत बाद 'आइस बाथ' लेने से अगले कुछ घंटे और दिनों में मांसपेशियों का दर्द कम हो सकता है। 'आइस बाथ' से मांसपेशियों की ताकत, मजबूती और लचीलेपन जैसी चीजों में मदद मिल सकती है। 'आइस बाथ' से व्यायाम के बाद होने वाली सूजन, मांसपेशियों की सूजन और मांसपेशियों की क्षति जैसी चीजों में सुधार हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगातार कई दिन तक तीव्र व्यायाम करना पड़ता है तो आपके लिए 'आइस बाथ' एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

रुपया 11 पैसे टूटकर 91.79 प्रति डॉलर पर

मुंबई। रुपया बुधवार को शुरुआती बढ़त को गंवा बैठा और अंत में 11 पैसे टूटकर 91.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक में गिरावट से मिल रहा समर्थन लगातार विदेशी पूंजी की निकासी से बेअसर हो गया। अमेरिकी डॉलर सूचकांक में नरमी और यूरोप के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापारिक समझौते से मिली राहत से रुपया मजबूती से खुला था।

सोने के बदले कर्ज दो साल में दोगुना होकर हुआ 15.6 लाख करोड़

एजेंसी ▶▶| मुंबई

सोने की कीमतों में तेज उछाल के बीच सुरक्षित माने जाने वाले इस खंड में बैंकों और अन्य कर्जदाताओं की दिलचस्पी बढ़ने से देश में सोने के आभूषण के बदले कर्ज दो साल में करीब दोगुना होकर नवंबर 2025 तक 15.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

- सोने के बदले गोल्ड लोन में 42 फीसदी की वृद्धि दर्ज

क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2025 तक के एक साल में 'सोने के बदले कर्ज' (गोल्ड लोन) में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले नवंबर 2024 तक के वर्ष में इसमें 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इस वजह से नवंबर 2023 में 7.9 लाख करोड़ रुपये पर रहा कुल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो दो साल में बढ़कर 15.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

बैंकों और अन्य कर्जदाताओं की दिलचस्पी बढ़ी

पात्रता बढ़ने से कर्ज राशि ज्यादा हुई

क्रिफ हाई मार्क ने कहा कि ऋण पोर्टफोलियो में यह तेज बढ़ोतरी सोने की ऊंची कीमतों और मजबूत गारंटी की वजह से हो रही है। सोने की कीमतों में आई तेजी से कर्ज लेने वालों की पात्रता बढ़ने से कर्ज की राशि भी ज्यादा हो गई है।

खुदरा ऋण में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी बढ़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, सोने के बढ़ते कर्ज को लेकर बढ़ते भरोसे के कारण खुदरा कर्ज के कुल पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है। नवंबर 2025 के अंत तक कुल खुदरा ऋण में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 8.1 प्रतिशत थी।

गोल्ड लोन खातों की वृद्धि सीमित रही

रिपोर्ट के मुताबिक, सक्रिय गोल्ड लोन खातों की संख्या में वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रही और इसमें 10.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्ज अब कुल पोर्टफोलियो का लगभग आधा हिस्सा बन चुके हैं जबकि मार्च 2023 में इनकी हिस्सेदारी 36.4 प्रतिशत थी।

56 फीसदी से अधिक कर्ज पुरुषों ने लिया

विश्लेषण में पाया गया कि कुल गोल्ड लोन में 56 प्रतिशत से अधिक कर्ज पुरुष उधारकर्ताओं ने लिए। हालांकि कर्ज चुकाने के मामले में महिला कर्जदारों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है।

पीएसयू बैंकों का दबदबा बना हुआ

बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से गोल्ड लोन में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों का दबदबा बना हुआ है और इस कारोबार में उनकी हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत है। वहीं, गोल्ड लोन पर केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की हिस्सेदारी 8.1 प्रतिशत रही।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया अधिकृत आंकड़ा

दिसंबर में जमकर हुआ औद्योगिक उत्पादन 7.8% से बढ़ा उत्पादन, दो साल का बना रिकॉर्ड

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

खनन, विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर दिसंबर 2025 में दो साल से अधिक के उच्चतम स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़ा था।

आधिकारिक बयान में कहा गया, '' दिसंबर 2025 में औद्योगिक गति और मजबूत हुई क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7.8 प्रतिशत बढ़कर दो वर्ष से अधिक के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। नवंबर 2025 में इसमें 7.2 प्रतिशत (संशोधित) की वृद्धि दर्ज की गई थी।'

खास बातें

- खनन, विनिर्माण व बिजली क्षेत्रों का मजबूत प्रदर्शन रहा
- अस्थायी अनुमान 6.7 फीसदी को संशोधित किया गया था
- विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई

प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत

उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं में 8.1 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओं में 7.5 प्रतिशत, अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं में 12.1 प्रतिशत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 12.3 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 8.3 प्रतिशत रही।

अप्रैल-दिसंबर में वृद्धि दर घटी थी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने नवंबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के अनुमान को पिछले महीने जारी किए गए 6.7 प्रतिशत के अस्थायी अनुमान से संशोधित करके 7.2 प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 3.9 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 4.1 प्रतिशत थी।

विनिर्माण क्षेत्र में आईटी क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि

एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो दिसंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत रही थी। इसमें कहा गया, '' विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले उद्योग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक व ऑप्टिकल उत्पाद (34.9 प्रतिशत), मोटर वाहन, ट्रेलर व सेमी-ट्रेलर (33.5 प्रतिशत) और अन्य परिवहन उपकरण (25.1 प्रतिशत) हैं।''

खनन उत्पादन में 6.8 फीसदी की वृद्धि

खनन उत्पादन में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो दिसंबर 2024 में 2.7 प्रतिशत थी। बिजली उत्पादन में दिसंबर 2025 में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2024 की इसी महीने में यह 6.2 प्रतिशत थी।

विनिर्माण क्षेत्र में 23 उद्योग समूह शामिल

आईआईपी की वृद्धि में दिसंबर 2025 में शीर्ष तीन प्रमुख योगदान करने वाले क्षेत्र अवसंरचना निर्माण वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 23 उद्योग समूहों में से 16 ने दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 12.7 फीसदी रहा

आईआईपी आंकड़ों में दिसंबर 2025 के शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ताओं में बुनियादी धातुओं का विनिर्माण (12.7 प्रतिशत), मोटर वाहन, ट्रेलर व सेमी-ट्रेलर (33.5 प्रतिशत) और दवा औषधीय रसायन एवं वनस्पतिक उत्पाद (10.2 प्रतिशत) शामिल हैं।

लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी सेंसेक्स 487 अंक उछला

मुंबई (भाषा)। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता से बढ़े उत्साह के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 487 अंक चढ़ गया जबकि एनएसई निफ्टी में 167 अंकों की तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 487.20 अंक यानी 0.60 प्रतिशत उछलकर 82,344.68 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 646.49 अंक की तेजी के साथ 82,503.97 अंक तक पहुंच गया था। वहीं एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 167.35 अंक यानी 0.66 प्रतिशत बढ़कर 25,342.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद करीब नौ प्रतिशत तक उछल गए। इसके अलावा इटर्नल, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में भी तेजी रही। दूसरी तरफ, एशियन पेंट्स के शेयरों में चार प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

अमेजन 16,000 कर्मियों की जल्द करेगी छंटनी

न्यूयॉर्क। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन तीन महीने में दूसरी बार बड़े पैमाने पर छंटनी करते हुए लगभग 16,000 नौकरियों की कटौती कर रही है। कंपनी ने कहा कि उसकी कर्मचारियों की जगह जनरेटिव यानी सृजन से जुड़े कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल करने की योजना है। महामारी के दौरान बढ़ी हुई कार्यबल संख्या को भी धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेथ गैलेटी ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कंपनी विभिन्न स्तरों को घटा रही है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ा रही है और नौकरशाही को कम कर रही है।

नई दिल्ली। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात के सीमावर्ती भुज जिले के 'ग्रेट रन ऑफ कच्छ' के धोरडो में सोमवार को देशभक्ति और स्वदेशी शक्ति का ऐतिहासिक संगम देखने को मिला, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की विरासत खादी से निर्मित दुनिया का सबसे विशाल स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान और गौरव के साथ में भव्य एवं दिव्य रूप में प्रदर्शित किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा इस विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 'सफेद नमक के रेगिस्तान' के ऊपर आलोकित यह ऐतिहासिक तिरंगा राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी भावना एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रतीक बना। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने देश की एकता, अखंडता और गौरवशाली परंपरा को साकार होते हुए देखा। देशभर के खादी कारीगरों ने वीडियो संदेश के माध्यम से कच्छ में लगे दुनिया के सबसे विशाल तिरंगे को सैल्यूट करके नया कीर्तिमान बनाया।

राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत भुवनेश्वर में घरेलू पीएनजी कनेक्शन शुरू

भुवनेश्वर। गेल इंडिया लिमिटेड ने भुवनेश्वर में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए दो प्रमुख आवासीय सोसाइटियों में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (डीपीएनजी) कनेक्शन की शुरुआत की है। यह पहल राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत की गई है, जिससे शहर में सुरक्षित, सस्ता और लगातार गैस सप्लाई सुनिश्चित होगी। पहला कनेक्शन खंडगिरी क्षेत्र की कॉस्मोपोलिस रेजिडेंशियल सोसाइटी में शुरू किया गया, जहां 835 फ्लैट्स को पीएनजी सुविधा से जोड़ा गया। इस मौके पर गेल के अधिकारी और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी मौजूद रहीं। उन्होंने पीएनजी के फायदे बताते हुए कहा कि यह गैस सुरक्षित है, इस्तेमाल में आसान है, बिना रुकावट मिलती है और घरों के लिए किफायती भी है। इसके बाद ऐगिनिया स्थित श्री क्षेत्र रेजिडेंसी सोसाइटी में 144 फ्लैट्स के लिए भी डीपीएनजी कनेक्शन शुरू किए गए। इस अवसर पर सांसद अपराजिता सारंगी ने खुद के पीएनजी उपयोग के अनुभव साझा करते हुए लोगों से इस स्वच्छ ईंधन को अपनाने की अपील की।

चांदी रिकॉर्ड 3.85 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहा। कमजोर अमेरिकी डॉलर और वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच दोनों नए शिखर पर पहुंच गए। चांदी में लगातार तीसरे दिन तेजी आई और यह 15,000 रुपये यानी 4.05 प्रतिशत बढ़कर 3,85,000 रुपये (सभी कर सहित) प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले सत्र में यह 3,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, जबकि शुक्रवार को यह 3,29,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी। सराफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 5,000 रुपये यानी तीन प्रतिशत बढ़कर 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए शिखर पर पहुंच गया। मंगलवार को यह 1,66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

कंपनियों को 2044 तक होगी 3,300 नए विमानों की जरूरत

हैदराबाद। भारत और दक्षिण एशिया की विमानन कंपनियों को हवाई यातायात की बढ़ती मांग से 2044 तक करीब 3,300 नए विमानों की आवश्यकता होगी। विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि अनुमानित आपूर्ति में से करीब 90 प्रतिशत यानी 2,875 'सिंगल-आइल' विमान यानी एक गलियारा वाले विमान होंगे जबकि चौड़े आकार के विमानों की संख्या 395 होगी। दक्षिण एशिया के लिए अपने 'वाणिज्यिक बाजार परिदृश्य' (सीएमओ) में बोइंग ने कहा कि अगले दो दशकों में इस क्षेत्र की विमानन कंपनियों को करीब 45,000 पायलट, 45,000 तकनीशियन और चालक दल के 51,000 सदस्यों की आवश्यकता होगी। बोइंग के यूरेशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप के वाणिज्यिक विपणन के प्रबंध निदेशक अश्विन नायडू ने कहा कि भारत एक विकासशील बाजार है और देश में विमानों की संख्या में और वृद्धि होगी।

एस्सार 100 ईंधन चार्जिंग केंद्र करेगी स्थापित

एजेंसी ▶▶| बेतुल (गोवा)

एस्सार ग्रीन मोबिलिटी भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ माल ढुलाई पहल के तहत देशभर में 100 वैकल्पिक ईंधन एवं चार्जिंग केंद्र के नेटवर्क समर्थित 30,000 एलएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक को तैनात करने का लक्ष्य बना रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस विस्तार से माल ढुलाई कार्यों से सालाना लगभग 10 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है जो परिवहन उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एस्सार ग्रुप के परिचालन भागीदार (ऊर्जा) बी. सी. त्रिपाठी ने कहा,डीजल से छुटकारा पाने की प्रक्रिया तभी संभव होगी जब स्वच्छ विकल्प माल ढुलाई की परिचालन और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होंगे। यही वह कमी है जिसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

राशिफल

मेष कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मानसिक शान्ति रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार की स्थिति सन्तोषजनक रहेगी।

वृष कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन आगमन की स्थितियां बनी रहेंगी।

मिथुन आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अति उत्साही होने से बचें। सुस्वादु खानपान में रुचि बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी।

कर्क अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी।

सिंह कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कन्या कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। आय की स्थिति में सुधार होगा। संयत रहें। क्रोध के क्रोध से परेशान रहेंगे। भागदौड़ अधिक रहेगी।

तुला दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

वृश्चिक आय में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। मन में नकारात्मकता के प्रभाव से बचें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं।

धनु कारोबार पर ध्यान दें। कठिनाइयां आ सकती हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। पठन-पाठन में रुचि रहेगी।

मकर वाणी में सौम्यता रहेगी। नकारात्मक विचारों के प्रभाव से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

कुंभ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। संयत रहें। बातचीत में सन्तुलित रहें। कारोबार में सुधार होगा।

मीन शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा पर जाना हो सकता है। मानसिक शान्ति बनाये रखने के प्रयास करें। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बैंक ऑफ बडौदा आरसेटी कानपुर नगर के परिसर में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया।संस्थान कि निदेशक श्रीमति शिवांगी जायसवाल जी द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया और उपस्थित सभी सदस्यों ने राष्ट्र के प्रति अपनी एकता एवं निष्ठा का संकल्प लिया। इस अवसर पर आरसेटी के संकाय रीना यादव जी, विशाल कमल जी एवं कार्यालय सहायक रश्मि यादव जी और अभिषेक यादव जी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में सहभागिता कर समारोह की शोभा बढ़ाई। सभी उपस्थितजनों ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान के मूल्यों का पालन करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह का समापन देशभक्ति नारों एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

जेआईआईटी नोएडा में ICABB-2026 का शुभारंभ जैव-विज्ञान में वैश्विक नवाचारों पर मंथन

नई दिल्ली। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (JIIT), नोएडा 28 से 30 जनवरी 2026 तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन (ICABB-2026) की आतिथ्य करेगा। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को भारत सरकार द्वारा CSIR और ANRF का सहयोग प्राप्त है। यह आयोजन दुनिया भर के वैज्ञानिकों, और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाता है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय "जैव चिकित्सा और जैव अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नवीन नवाचार" पर आधारित है। उद्घाटन सत्र में पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉ. विजय कुमार सारस्वत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉ. सारस्वत, एक प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। इससे पूर्व वे डीआरडीओ के प्रमुख, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलाधिपति और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह उपस्थित थे।

नई दिल्ली से सीआईएसएफ वंदे मातरम् तटीय साइक्लोथॉन–2026 का वर्चुअल शुभारंभ

नई दिल्ली। सीआईएसएफ की प्रमुख राष्ट्रीय जनसंपर्क एवं जन-जागरूकता पहल "वंदे मातरम् तटीय साइक्लोथॉन–2026" का आज प्रातः 07:30 बजे मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शुभारंभ के साथ ही 25 दिनों के इस विशाल राष्ट्रीय अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। सीआईएसएफ की दो साइक्लिंग टीमें एक साथ बक्कखाली (पश्चिम बंगाल) एवं लखपत (गुजरात) से रवाना हुईं। ये टीमें देश के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 9 तटीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेंगी और 22 फरवरी 2026 को कोच्चि में इसका समापन होगा। विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति एवं अंतर-एजेंसी सहयोग शुभारंभ समारोह में अनेक विशिष्ट गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

शब्द पहेली - 6122

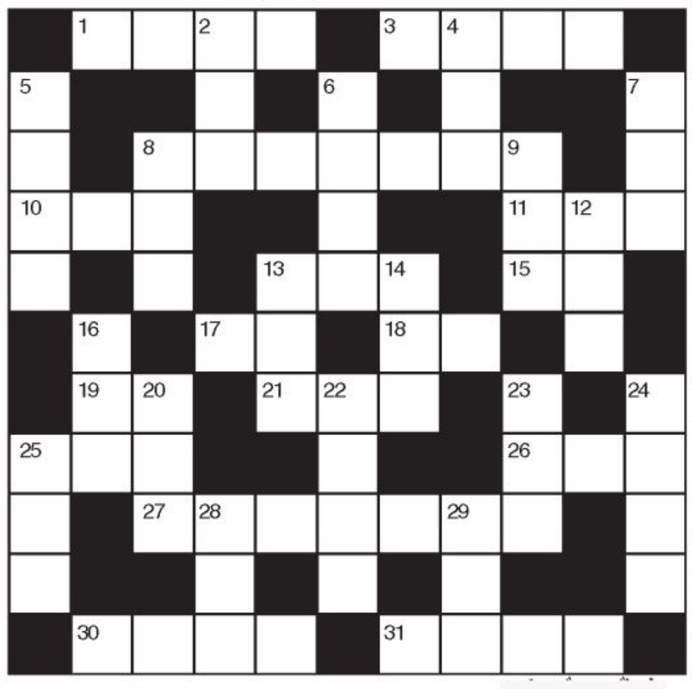

बाएँ से दाए

1. ईष्ट कृपा,वर-4
3. मान का विलोम-4
8. शैतानी करना-4,3
10. झगड़ा,बैर-3
11. जंगल,वन-3
13. सर्दी से बचने के लिये जलाई गई लकड़ियों का ढेर-3
15. जलने के बाद बचे अवशेष-2
17. कार्य-2
18. पतवार-2
19. नमाज से पहले हाथ-पांव धोना-2
21. नमस्कार-3
25. बूंद-3
26. जिज्ञासा,लगन-3
27. आत्मोत्सर्ग करना-4,3
30. मां के माता-पिता-2,2
31. रपटना-4

ऊपर से नीचे

2. वलय,घेरा-3
4. तीन घंटे का समय-3
5. खिसकना-4
6. उन्मादी,मदमस्त-4
7. यज्ञ,होम-3
8. नगर-3
9. तिरस्कृत-3
12. रूप अभिमान-3
13. शांति-3
14. प्रतिज्ञा-3
16. सहभोज-3
20. मोजा, पायताबा-3
22. उदारता-4
23. परवरिश करना-3
24. वचन तोड़ना-4
25. लेखनी-3
28. लिखावट-3
29. अमीर, धनवान-3

शब्द पहेली- 6121 का हल

अ	मा	न	त		अ		बी	र	ब	ल
	ला		वा		म	हि	मा		ल	व
म			य	की	न		र			कु
त	क	ली	फ		चै	त्र		क	ल	श
वा		ड		रा	न		गै		ह	
ला	प	र	वा	ह		का	र	गु	जा	री
	र		दा		अ	स्त		मा		मा
प्र	ख	र		पा	प		म	न	च	ला
जा			शा		ह	न	न			गू
प	र		पि	ह	र		ह		शा	
ति	जा	र	त		ण		र	ह	म	त

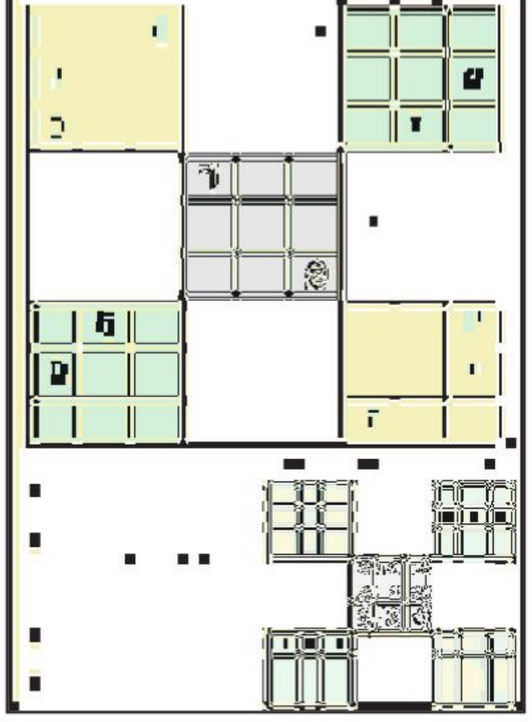

Last Day To Join Private Channel.
Closing entry for new members Now

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times

And more Newspapers

♦ **InternationalNewspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**

[National + InternationalEditorials]

Click here to join

♦ Lifetime validity at just 19 Rupees 📌

I give you my guarantee you, it will worth every penny 🙏